हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

25.03.2025/1100/केएस/वाईके/1

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरम्भ।

प्रश्न संख्या : 3300 (स्थगित)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार का कार्यकाल समापन की ओर बढ़ रहा है। धीरे-धीरे समापन ही हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस प्रश्न को लगे हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें माननीय तीन सदस्य जिनमें मैं, रणधीर शर्मा जी और त्रिलोक जम्वाल जी मेरे साथ में हैं जो सिर्फ इतनी ही जानकारी चाह रहे हैं कि तीन वर्षों में दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों के कितने संस्थान बंद/विलय/डिनोटिफाई किए गए तथा कितने संस्थान खोले गए, विभागवार तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा दें? अगर आपके पास यह ब्यौरा नहीं है तो आपके पास फिर किस चीज़ का ब्यौरा है? इस सूचना को छिपाने का अभिप्राय क्या है? इससे क्या हासिल हो रहा है? हम तो सिर्फ यही जानकारी चाहते हैं। अगर इस माननीय विधान सभा का सदस्य होने के बावजूद हम यहां पर दो-दो साल से किसी प्रश्न का उत्तर ही प्राप्त ना कर सके तो हमारा औचित्य ही क्या है? क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसी सत्र में जो जवाब हमने मांगा है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों के कितने संस्थान बंद/विलय/डिनोटिफाई किए गए तथा कितने संस्थान खोले गए? हर इंस्टीट्यूट को जब आप खोलते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन होती है और जब उसको बंद करते हैं तो भी उसकी नोटिफिकेशन होती है। मुझे लगता है कि यह सूचना तो एक मिनट में एकत्रित करके दी जा सकती है लेकिन छिपाई जा रही है इसलिए यह प्रश्न पैदा हो रहा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले कुछ सत्रों में यह सूचना दे दी जाएगी क्योंकि कई ऐसे संस्थान है जिनको मर्जर करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है और कई जगह डिनोटिफाई का कार्य पूरा नहीं हुआ **है। जैसे ही डिनोटिफाई और मर्जर का कार्य पूरा हो जाएगा, पूरी सूचना एकत्रित करके सदन में दे दी जाएगी।**

अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1105/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 3300------- क्रमागत

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी, नेता के पांव में ही सबका पांव होता है। (श्री त्रिलोक जम्वाल जी द्वारा प्रशन पूछने के लिए हाथ उठाने पर)...(व्यवधान) आपका प्रश्न भी है परंतु नेता प्रतिपक्ष जी ने सब कुछ पूछ तो लिया। माननीय सदस्य, अपना रास्ता अलग मत रखिए, एक जगह ही रखिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, रास्ता एक ही है परंतु देखने का नज़रिया सबका अपना-अपना है।

यह तो कन्टीन्यू प्रोसैस है और ये अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में बंद करते जाएंगे, करते जाएंगे। इसलिए इनके पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा होने तक कोई सूचना नहीं आएगी। अभी तक जितने संस्थान बंद किए हैं वह तो एक लिमिटेड नम्बर है और उसकी सूचना तक पिछले दो वर्षों से नहीं दी जा रही है। आप माह जनवरी, 2026 तक तो सूचना दे सकते हैं, उसको क्यों छिपाया जा रहा है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी शिक्षा विभाग में रिफॉर्म चल रहे हैं। स्कूल और कॉलेज बंद हो रहे हैं इसलिए यह एक बहुत लम्बी सूचना है। इसके अतिरिक्त अभी खाली बिल्डिंग्ज का एक और मुद्दा आया है। There is lot of things.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय श्री त्रिलोक जम्वाल को माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर के साथ चलना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले ही पूरा सवाल पूछ लिया है। (***)। मैं बताना चाहता हूं कि कई और विभागों में भी मर्जर और रेशनेलाइजेशन का कार्य शुरू किया गया है तथा आने वाले समय में कई और विभाग भी मर्जर और रेशनेलाइजेशन करेंगे। मैं इस बारे में जल्दी ही सूचना एकत्रित करवा दूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्पेसिफिक है कि दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों के कितने संस्थान बंद, विलय तथा डीनोटिफाई किए गए तथा कितने नये संस्थान खोले गए? विभागवार तथा विधान सभा क्षेत्रवार ब्यौरा दें। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 जुलाई, 2025 तो कब की हो चुकी है। हम तो तब तक की सूचना मांग रहे हैं

25.03.2026/1105/av/yk/2

आप आगे का बहाना लेकर पिछली सूचना क्यों छिपा रहे हैं? ...(व्यवधान) इस सूचना को छिपाने का कोई कारण नहीं बनता और माननीय मुख्य मंत्री जो लॉजिक दे रहे हैं, वह तो यहां पर बिल्कुल भी फिट नहीं होता। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से यही आग्रह है कि यह सत्र अभी दिनांक 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। इसलिए दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक जो संस्थान बंद, विलय या डीनोटिफाई हुए; आप उनका ब्यौरा दे दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि यही प्रश्न नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा, (***)अब मैं क्या जवाब दूं? **मैं यही कह रहा हूं कि आने वाले विधान सभा सत्रों के दौरान सभी डीनोटिफाई, विलय या बंद किए जाने वाले संस्थानों की सूचना दे दी जाएगी।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो (***) शब्द का इस्तेमाल किया है इसको कार्यवाही से निकालने के निर्देश दिए जाए।

अध्यक्ष : ठीक है, इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए क्योंकि भाजपा एक ही पार्टी है और उसके नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर हैं।

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

25.03.2026/1105/av/yk/3

प्रश्न संख्या : 4061

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में प्रवेश शुल्क में जिस प्रकार से बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में मैंने यह जानना चाहा था कि क्या इससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा? लेकिन इस बारे में मुख्य मंत्री की ओर से जवाब आया है कि

टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1110/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या : 4061 जारी श्री राकेश जम्वाल .... जारी

इसकी संभावना नगण्य है। हिमाचल प्रदेश के एंट्री प्वाइंटस पर गाड़ियों पर कई गुना टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। चाहे बड़ी गाड़ियां हों या छोटी गाड़ियां, सभी पर टैक्स में वृद्धि लागू की गई है। इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही प्रदेश के टूरिज्म पर कोई बोझ पड़ेगा। मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह स्पष्ट करें कि किस प्रकार प्रदेश की जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा?

दूसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो पुरानी कैटेगरी में गाड़ियां सम्मिलित थीं, क्या उसमें कोई नई कैटेगरी जोड़ी गई है, क्या हिमाचल की टैक्सियों और यूटिलिटी जीप के ऊपर भी यह टैक्स लगेगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि सूचना में पूर्ण अपडेट दे दिया गया है, फिर भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल की निजी गाड़ियों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता है जो बाहर से आने वाली गाड़ियां या कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन्हीं पर टोल टैक्स लगता है। और वह भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह टोल टैक्स उतना नहीं बढ़ाया गया जितना कहा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नॉर्मज के अनुसार फॉस्ट ट्रैक सिस्टम को इसके साथ जोड़ा गया है। उन्हीं नॉर्म्ज के अनुरूप जहां आवश्यक था, वहीं कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार टोल टैक्स का रिजर्व प्राइस 185 करोड़ रुपये था जबकि ऑक्शन 228 करोड़ रुपये में हुई है।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। हमारे गांव बॉर्डर से सटे हुए हैं और बहुत-से लोग बिजनेस के लिए दौलतपुर, गगरेट आते-जाते हैं। उनका प्रतिदिन आवागमन रहता है। यद्यपि आपने आर0डी0जी0 बंद होने के बावजूद भी एक प्रोग्रेसिव बजट प्रस्तुत किया है

25.03.2026/1110/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

और हिमाचल की गाड़ियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग प्रतिदिन कार्य हेतु आते-जाते हैं, उनके लिए क्या आप कोई पास की व्यवस्था करने का विचार रखते है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राकेश कालिया जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह गगरेट क्षेत्र से संबंधित है जो पंजाब के साथ लगता है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल की गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वे दिन में 10 बार भी आवागमन करें। पूर्व में एंट्री टैक्स कलैक्शन के दौरान लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थीं जिससे असुविधा होती थी। इस समस्या के समाधान हेतु इसे फास्ट ट्रैक सिस्टम के साथ जोड़ा गया है जिससे इसकी व्यवस्था अधिक सुगम हो गई है। जहां तक टैक्सी का प्रश्न है, उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया गया है यानी एल0एम0वी0 और टैक्सी पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। **स्थानीय स्तर पर जो लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं, उनके लिए पास की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हम इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे।**

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पांवटा साहिब और काला अंब जैसे इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 1000 लोग देहरादून से कार्य हेतु आते हैं। इसी प्रकार हरियाणा से भी हजारों कर्मचारी आते हैं जिनके वाहन अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। उनके वाहन का नम्बर उत्तराखण्ड का है। उन्हें प्रतिदिन बैरियर

क्रॉस करना पड़ता है, जहां ग्रीन टैक्स 170 रुपये यानी लगभग 350 रुपये प्रति दिन देना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, पांवटा से यमुनानगर तक ट्रकों का किराया लगभग 6000 रुपये है और उनको वापसी में प्रति ट्रक 800 रुपये एंट्री टैक्स का देना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि बॉर्डर क्षेत्रों में जो लोग प्रतिदिन इंडस्ट्री में कार्य हेतु आते हैं और जो वाहन प्रतिदिन सामान को लेकर आते-जाते हैं क्या उनके लिए कोई रियायत देने पर विचार किया जाएगा?

मुख्य मंत्री एन0एस0 द्वारा .... जारी

25-3-2026/1115/NS-AG/1

प्रश्न संख्या : 4061------क्रमागत

मुख्य मंत्री : हम वापसी में पूरी रियायत देंगे, उस पर हम विचार करेंगे। ...(व्यवधान) माननीय सुख राम जी ने कहा है कि कई बार लगातार लोग आते-जाते हैं तो इस बारे में मैंने पहले ही कहा है कि जो बॉर्डर्ज एरियाज हैं उन पर विचार करना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे राजस्व में कितनी कमी आएगी तो विचार करने के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते **हैं। मैं इन सब विषयों में सहानुभूतिपूर्वक भविष्य में विचार कर सकता हूं और हम फिर आगे बढेंगे।** मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग रेग्युलर आते हैं जैसे उत्तराखंड या हिमाचलवासी जो बॉर्डर्ज से बाहर रहते हैं, अगर वे अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हिमाचल में करवाएंगे तो उनको इस टैक्स का लाभ मिल सकता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः इन्होंने सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया। ...(व्यवधान) आप बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, मैं बताता हूं जो मैं समझ पाया। आपकी जो भी शंकाएं हैं, मुख्य मंत्री जी ने हाउस को एश्योर कर दिया कि मैं इन इश्यूज को कैबिनेट में ले जाकर जहां भी, जो भी प्रदेश-हित में करने की जरूरत होगी उसको मैं करूंगा। अब इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? ...(व्यवधान) श्री हरदीप सिंह बावा जी आप क्या बोलना चाहते हैं? माननीय सदस्य, आपकी कल चैम्बर में बैठ कर चर्चा हुई है।

25-3-2026/1115/NS-AG/2

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू के ऊपर अपना जवाब दिया है। यह मसला विचारधीन है। मेरी दो दिन पहले आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग से इस विषय पर बात हुई थी। मुख्य मंत्री जी ने भी एश्योर किया है। यह बात सही है जो सुख राम जी ने कही है। मेरा इतना ही कहना है कि पंजाब के साथ मेरे क्षेत्र का बॉर्डर है और इण्डस्ट्री के अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर काम करने के लिए रोज आते हैं और वे बॉर्डर क्रोस करके हिमाचल में आते हैं। हम लोगों की रिश्तेदारियां क्रोस बॉर्डर हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह सुझाव हैं कि कम-से-कम 5 किलोमीटर उस तरफ और इस तरफ के लोगों को पासिस की अवेलेबिलिटी करवाई जाए ताकि वे लोग रोज क्रोस बॉर्डर आ सकें।

Speaker: This reply has already come, so your supplementary is hereby rejected. ...(Interruption) Hon'ble Member Shri Randhir Sharma ji, ask your supplementary. When the reply has come, I will reject it.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो बॉर्डर्ज की जिन सड़कों पर एन0एच0ए0आई0 के टोल टैक्स बैरियर लगे हैं और उसके आधा किलोमीटर बाद ही एंट्री टैक्स बैरियर है। लोगों को एक किलोमीटर के अंदर ही दो बार टैक्स देना पड़ता है। क्या सरकार उन बॉर्डर्ज रोड्ज पर टैक्स कम करने का विचार करेगी? दूसरा, इस एंट्री टैक्स के लगने के बाद पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर पर भी टोल टैक्स बैरियर लगाने की घोषणा की है और यह घोषणा पंजाब के वित्त मंत्री ने विधान सभा के अंदर की है। अगर वे भी बैरियर लगाते हैं तो बॉर्डर पर तीन बैरियर क्रोस करने पड़ेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पंजाब सरकार की विधान सभा के अंदर वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करेगी या पंजाब सरकार के साथ वार्ता करेगी कि वे कोई बैरियर न लगाएं और एंट्री टैक्स का प्रावधान न करे? क्या इस पर सरकार कोई आश्वासन देगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दो बैरियर हैं उनको एन0एच0ए0आई0 के साथ जोड़ दिया जाए। अगर वे इसको स्वीकार करते हैं तो हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

25.03.2026/1120/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 4061... जारी मुख्य मंत्री... जारी

दूसरा, जो आप पंजाब के वित्त मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, वह तथ्यहीन है। श्री जय राम ठाकुर जी भी तथ्यों पर नहीं बोलते हैं। (***) और वे भी कभी तथ्यों पर नहीं बोलते। कल इन्होंने दिल्ली में भी एक प्रेस स्टेटमेंट दी है। आपने कहा कि हमने विधवाओं और अनाथ बच्चों के नाम पर टैक्स लगा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने यह टैक्स कहां लगाया? अभी तो यह बिल पास हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि अभी इस बिल पर माननीय राज्यपाल महोदय की असेंट नहीं मिली है। ...(व्यवधान) सरकार की मंशा तो स्पष्ट हो गई हैपरंतु अभी राज्यपाल महोदय की असेंट नहीं मिली है। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप जो मंशा की बात कर रहे हैं उसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने विधान सभा में जो यह बिल लाया था उसमें यह अधिकार प्राप्त किया है कि यदि भविष्य में कभी विधवाओं और अनाथ बच्चों के नाम पर 2 पैसे या 5 पैसे सैस लगाना पड़े तो वह अधिकार हमें मिलना चाहिए। अभी यह बिल पास हुआ है, इसके बाद एक्ट बनना है, फिर इसमें गवर्नर की असेंट होनी है, उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन होगी। नोटिफिकेशन के बाद सरकार यह निर्णय करेगी कि यह सैस लगाना है या नहीं। हो सकता है हम सैस न लगाएं। आपकी पार्लियामेंट के बाहर कल यह स्टेटमेंट आई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ और विधवाओं के नाम पर सैस लगा दिया जबकि ऐसा नहीं है। आप यह भी कह रहे हैं कि हमने टोल टैक्स बढ़ाकर अपना राजस्व अर्जित किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि टोल टैक्स मेरे समय से नहीं लग रहा है; टोल टैक्स 30 वर्षों से लग रहा है। लेकिन हमने टोल टैक्स भी उतना नहीं बढ़ाया है जितना हल्ला किया

जा रहा है। एक वर्ष पहले जो महंगाई हुई है, हमने उसके हिसाब से ही टोल टैक्स बढ़ाया है।आप पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं और दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं लगता। अभी हमने इस सैस को लगाया ही नहीं है लेकिन पूरे नेशनल मीडिया में यह प्रचार कर दिया गया कि प्रदेश सरकार ने यह सैस लगा दिया है। आप जानते हैं कि

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

25.03.2026/1120/RKS/AS-2

यह सैस अभी लागू नहीं किया गया है लेकिन आप राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं बॉर्डर क्षेत्रों के सभी माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि भविष्य में हमें कुछ करना होगा तो उस पर कैबिनेट में चर्चा करके सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष : अगला प्रश्न 4062 ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इस संदर्भ में इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ...(व्यवधान) यदि ऐसी कोई टिप्पणी होगी तो मैं उसे रिकॉर्ड से निकलवा दूंगा। मैं कार्यवाही के एक-एक शब्द को देखता हूं। क्या रिकॉर्ड में रहना है और क्या नहीं, यह मैं देख लूंगा। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, आप चिंता न करें। जो भी असंसदीय शब्द होगा या जिस शब्द को रिकॉर्ड में रखने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड़ जी

25.03.2026/1120/RKS/AS-3

प्रश्न संख्याः 4062

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि मनाली में जो कूड़ा प्रबंधन का प्लांट स्थापित है उसमें काफी समय से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है। इसके साथ लगते क्षेत्र में बहुत अधिक दुर्गंध आती है। मेरा प्रश्न है कि क्या इस ओर आपका मंत्रालय ध्यान दे रहा है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा मंत्रालय इस गंभीर विषय पर पूरा ध्यान दे रहा है। मनाली में ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के हर नगर निकाय, नगर परिषद और नगर निगम में कूड़ा प्रबंधन हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। इसका सही रूप से डिस्पोजल करना हमारी प्रथम जिम्मेवारी है। नगर परिषद, मनाली में कुल 7 वार्ड हैं जहां से लगभग 4.81 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। इस कूड़े को घर-घर से इकट्ठा किया जाता है जिसके लिए 68 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

श्रीबी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1125/बी.एस./ए.एस.-1

प्रश्न संख्याः 4062 क्रमांगत...लोक निर्माण मंत्री जारी...

तथा 14 वाहन वहां पर लगाए गए हैं। इस कूड़े को रागड़ी स्थित कूड़ा प्रबंधन संयंत्र में भेजा जाता है। पूर्व नगर परिषद मनाली द्वारा M/s. Next Gen Chemicals के माध्यम से रागड़ी में Waste to Energy Plant स्थापित किया गया था। परंतु M/s. Next Gen Chemicals द्वारा कूड़े का निस्तारण सही तरीके से न करने के कारण उसका अनुबंध 17 जुलाई, 2024 को नगर परिषद मनाली द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसके पश्चात नगर परिषद मनाली द्वारा M/s. Sunton Life Ltd. को यह अवार्ड किया गया है और अब इसका कार्य चला हुआ है। उपरोक्त फर्म ने रागड़ी में लगभग 1.5 बीघा भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रभावी रूप से संचालित किया गया है और अभी तक जो टोटल लिगेसी वेस्ट वहां पर निकला है वह 1.99 लाख मिट्रिक टन है। जिसमें से प्रोसेस 79 हजार मिट्रिक टन हो चुका है और बैलेंस 21 हजार मिट्रिक टन लेगेसी वेस्ट है। जिसको आने वाले समय में सरकार द्वारा पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

वित्तीय सहयोग के रूप में भी वर्ष 2025-26 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1.29 करोड़ रुपये मनाली को दिए गए हैं और टाइड ग्रांट के रूप में 44 लाख रुपये मनाली नगर परिषद को दिए गए हैं।

माननीय सदस्य जी को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि वह एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है और बहुत से हमारे होटलियर्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोगों ने हमसे संपर्क किया है। एक-दो मसले इससे संबंधित नहीं हैं, मनाली का जो लेफ्ट बैंक है उसकी हालत भी ठीक नहीं है। हालांकि हम उसको लगातार ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं जल्द विधान सभा सत्र के बाद मैं मनाली का दौरा करूंगा और जो लेफ्ट बैंक सड़क है उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और साथ ही जो हमारा कूड़ा संयंत्र है उसका भी हम निरीक्षण करेंगे और इसमें जो भी सहयोग दिया जा सकता है उसको करके इसे पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जाएगा।

25.03.2025/1125/बी.एस./ए.एस.-2

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि एक स्पेशल नोडल एजेंसी स्थापित की जाए। जो इस प्रबंधन की देखरेख स्वयं करे, ताकि इस पर कार्य शीघ्र हो सके और जो टूरिस्ट सीजन आने वाला है, उससे पहले वहां पर जो दुर्गंध आती है उसे कम से कम बंद किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भी सुझाव दिए हैं, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और जैसे मैंने कहा हम स्वयं वहां जाकर इसका निरीक्षण करेंगे। क्योंकि मनाली में पूरे देश के लोग आते हैं। It is more or less a window for the entire State. इसलिए वहां से ऐसी कोई भी छवि नहीं जानी चाहिए जिससे हिमाचल की सुंदरता और **पर्यावरण पर कोई प्रश्नचिह्न लगे। इसलिए इसे पूरी तरह ठीक करना हमारी प्राथमिकता है। इस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।**

25.03.2025/1125/बी.एस./ए.एस.-3

प्रश्न संख्याः 4063

श्री इंद्र दत्त लखनपाल : उपस्थित नहीं।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वृक्षारोपण पर यह कार्यक्रम मैंने प्रश्न के रूप में उठाया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वन विभाग के बजाय इसे मुख्य मंत्री महोदय ने सामाजिक कार्यक्रम बनाया है और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना प्रदेश में लॉन्च की है। जिसमें 285 महिला मंडल, 70 युवक मंडल और 13 सामुदायिक समूहों की भागीदारी से प्लांटेशन किया जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो हमारे नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, खासकर मेरे शाहपुर विधान सभा और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी पेड़-पौधे हटाए गए हैं उसकी एवज में मैं देखता हूं कि जो श्यूहं से ले करके जोल तक यह हटाए गए हैं। ये हमारे बुजुर्गों के समय के लगाए हुए विशेषकर पीपल और हॉर्डर के वृक्ष थे। आज जो नेशन हाइवे पर डिस्टर्वेंस हुई है। इसमें एन0एच0ए0आई0 मुआवजे के रूप में पैसा भी दे रही है तो क्या वर्तमान सरकार नेशनल हाईवे पर उखाड़े गए पौधों के बदले कोई विशेष योजना या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर रही है? श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1130/DT/DC-1

प्रश्न संख्या 4063 जारी श्री केवल सिंह पठानिया जारी....

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 68 प्रतिशत वन भूमि है और इस वन भूमि में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों या किसी एन0जी0ओ0 ने काम किया है, उसमें मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन वनों का लगाने के एवज में, जैसा कि कहा भी जाता हे कि our State is the lungs of North Zone, इसमें केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की क्या मदद कर रही है? 1972 में हमारे 20-22 हजार परिवार पोंग बांध बनने के कारण विस्थापित हुए थे, इस मामले में हमारी केंद्र सरकार क्या मदद कर रही है? यह मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमारी जो फोरेस्ट लैंड है वह 68 परसेंट है और जो फारेस्ट क्वर है वह 29.52 परसेंट है। हमारी सरकार ने पहली बार यह निश्चय किया है कि इस फारेस्ट क्वर को कितने परसेंट तक

आगे बढ़ाना है। इसलिए हमने प्रदेश के फारेस्ट क्वर को वर्ष 2030 तक 29.52 परसेंट से बढ़ाकर 32 परसेंट करने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। पहली बार हमने परिवर्तन किया। महिला मंडल, युवक मंडल और यदि कोई सी0एस0आर0 के तहत वन लगाना चाहता है ऐसे समूहों को हम एक लैंड का टुकड़ा दे देंगे और उस लैंड के टुकड़े में वह वन विकसित कर सकते है। लेकिन पहले बार इसके लिए हम प्रोत्साहन राशि लेकर आए। महिला मंडल जो 2 हैक्टयर भूमि में पौधे लगायेगी तो सरकार उन्हें 1 लाख 30 प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। यह योजना हमनें छः वर्षके लिए बनाई है। अगर कोई महिला मंडल या युवक मंडल या कोई एन0जी0ओ सौ पौधों लगाने का विचार करती है और उस 100 पौधों में से 50 पौधे जीवित रहते हैं और सैपलिंग करते हुए 50 पौधे खराब हो जाते हैं तो उन खराब पौधों का भी 80000 रुपये उन्हें दिया जायेगा। जब युवा मंडल, महिला मंडल या कोई एन0जी0ओ0 उन पौधों की देखभाल करेगी तो प्रतिवर्ष 80000 रुपये छः वर्ष तक दिया जायेगा यानी जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते तक यह राशि उनको दी जायेगी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत इस योजना को लाया गया है। मेरा यह भी मानना है कि पौधा रोपण तो हर बार हो जाता है, हर बरसात में पौधा रोपण होता है और उस पौधा रोपण में विधायक के द्वारा एक पौधा रोपित कर दिया जाता है या मुख्य मंत्री

25.03.2026/1130/DT/DC-2

लगा देता या अन्य मंत्री लगा देते हैं। लेकिन सही मायने में हमारा फारेस्ट क्वर कितना हो उस दृष्टि से हम एक योजना लेकर आये जिससे आने वाले समय में सभी महिला मंडलों व युवक मंडलों को उनके गांव के नजदीक पैसा कमाने का अवसर भी मिलेगा और हमारे जंगल भी बचेंगे। इसके अतिरिक्त हम इकोलॉजिकल सर्विस के रूप में, जो कि माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने पूछा है, पूरे भारत वर्ष को हम 90000 करोड़ रुपये की इकौलॉजिकल सर्विसिज हर साल देते हैं। Indian Institute of Forest Management से इसकी स्टडी सरकार ने करवाई है। इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि we are the water ball of the Northern India and the lungs of the Northern India. हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ तो हम पर्यावरण को बचा रहे हैं और प्रदेश में वन क्षेत्र को

बड़ा रहे हैं। पेड़ काटने में हमारी सरकार के द्वार स्वयं प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए जो हमारे अधिकार है वे भी सुरक्षित रहने चाहिए।

नैशनल हाइवे में पेड़ो के कटान की बात माननीय सदस्य ने की है। मैंने स्वयं पिछले डेढ़-दो साल से ढगवार से कांगड़ा के बीच में सड़क का मिडीयम 5-5 मीटर किया हुआ है। उसमें फारेस्ट क्वर की हमने कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि एन0एच0ए0आई0 से मिलकर सड़कों किनारे के किनारे पेड़ लगा कर सुंदर रोडज का निर्माण करें। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो हमारे क्षेत्र में पौधा रोपण करना चाहते हैं परंतु सरकार उनको पौध रोपण करने की अनुमति प्रोपर ढंग से नहीं देती। अगर उनको अनुमति दे, चाहे वह 50 बीघा ही जंगल को अडाप्ट करे उसके लिए वे अपना आदमी भी रखेंगे उसकी देखभाल भी करेंगे , उसके बाद अगर वे पांच साल के बाद वन विभाग यह फारेस्ट हैंडओवर करते हैं, तो क्या सरकार कार्बन क्रेडिट कार्ड का जो लाभ मिलना उस को देने पर विचार करेगी ताकि वे इस कार्य में आगे बढ़ें।

मुख्य मंत्री श्री ,एन0जी0 द्वारा जारी...

25.03.2026/1135/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4063.....जारी श्री सुख राम चौधरी के पश्चात..... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां हमने 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' लाई है, वहीं 'मुख्य मंत्री विस्तार योजना' इंडस्ट्री वालों के लिए भी लाई है। **जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उनको एक-एक जंगल का भाग दे दें, तो बिल्कुल देंगे।** डी-कार्बोनाइजेशन व कार्बन कैप्चर के लिए उनको जो पॉइंट्स मिलते हैं, वे भी बेच सकते हैं। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो इंडस्ट्रीलिस्ट पांवटा साहिब में खाली पहाड़ों पर जंगल लगाना चाहता है, हम उनको जगह अलॉट करेंगे और वे वहां पर

बाड़बंदी भी करें, उन पौधे की रक्षा भी करें और उनके लिए चौकीदार की व्यवस्था भी करें। सरकार उनका स्वागत करती है और वे हमारी इस योजना का लाभ उठाएं। माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि मुझे लिस्ट दे दीजिए कि कहां-कहां पर कौन-कौन सी इंडस्ट्री पेड़ लगाना चाहती है। उनके पास जाकर हमारे अधिकारी कोऑर्डिनेट करेंगे। हम डी-कार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और पहली बार बायोचार के दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नई व्यवस्था के साथ काम कर रही है। पहली बार यह व्यवस्था परिवर्तन हमारी सरकार द्वारा लाया जा रहा है। सवा तीन साल में हमने कई बदलाव किए हैं। उन बदलावों में डी-कार्बोनाइजेशन, कार्बन सिंक और कार्बन कैप्चर भी शामिल हैं। सभी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन क्रेडिट जो भी होगा, वह इंडस्ट्रीज़ को देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

25.03.2026/1135/डी.सी.-एन.जी./2

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग के विषय में माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं। पिछले लंबे समय से महिला मण्डल और युवक मण्डल पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं लेकिन वन विभाग की ओर से उनकी लायबिलिटीज़ या पेमेंट लम्बित है, वे देनदारियां कब तक दे दी जाएंगी? मुझसे बहुत से मजदूर बार-बार मिलते रहते हैं। अभी तो पिछले साल से 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' शुरू हुई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि चाहे वह नर्सरी के अंदर हो, अलग-अलग डिवीजन के अंदर हो या सर्किल के अंदर हो, वे पेमेंट्स कब तक कर दी जाएंगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' की कुछ लायबिलिटीज़ लम्बित पड़ी हुई हैं। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमने इसी वर्ष यह योजना लाई है। पिछले 40 वर्षों से एक ऐसी योजना चल रही थी जिसमें फॉरेस्ट गार्ड स्वयं पौधे लगाता था। मैंने अभी आदेश दिए हैं कि आगे से जो भी 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' के तहत पौधे लगाए जाएंगे, उसका 80 प्रतिशत कार्य महिला मण्डल, अधिकतर

भाग युवक मण्डल, स्वयंसेवी संस्थाएं और गांवों के अन्य मण्डल करेंगे। उनको पैसा भी मिलेगा और इस योजना का लाभ भी मिलेगा। **इसके अलावा जो इनकी लायबिलिटीज़ हैं, वे अगले वित्तीय वर्ष में पूरी कर दी जाएंगी।**

श्री सुरेन्द्र शौरी : मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि सरकार ने महिला मण्डल, युवक मण्डल और स्वयं सहायता समूहों को प्लांटेशन का काम दिया है। मेरे ध्यान में ऐसा आया है कि जैसे ही यह योजना शुरू हुई, तो ऐसे-ऐसे युवक व महिला मण्डलों को भी काम दे दिया गया जिनकी पिछले 10 साल से कोई भी गतिविधि नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वन विभाग जिन-जिन महिला मण्डलों और युवक मण्डलों को काम दे रहा है, तो उनके पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए कि उन्होंने समाज सेवा में क्या-क्या काम किए हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में क्या किया है, क्या इससे पहले कोई प्लांटेशन की है और उनकी कोई फोटोग्राफ या उनका रजिस्टर और रिकॉर्ड चेक किया जाए ताकि काम ठीक

25.03.2026/1135/डी.सी.-एन.जी./3

तरह से हो। जब यह स्कीम आ गई तो बहुत सारे मण्डल इसका लाभ लेने के लिए बना दिए गए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आपके ध्यान में कोई ऐसा मण्डल है तो उसका जिक्र कर दीजिए? उसके बाद उसकी इंक्वायरी हो जाएगी। ...(interruption) This is missive. You should be very specific.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। पौधा लगाने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जो भी महिला मण्डल या युवक मण्डल होगा, अगर वह अपने गांव के किसी क्षेत्र में पौधे लगाना चाहता है, तो सरकार उसे पौधे लगाने के लिए पैसा देगी। यह योजना इसी वर्ष शुरू की गई है और इसको मॉनिटर भी किया जाता है। यह पहले की योजना नहीं है। जो भी महिला मण्डल या युवक मण्डल चाहेंगे, वे 'राजीव गांधी

वन संवर्धन योजना' के तहत अभी भी अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे विभाग में कोई भी महिला मण्डलों अपना नाम रजिस्टर करवा दे ताकि समय के अनुसार उनकी बाड़बंदी कर दी जाए और उन्हें इंसेंटिव का फायदा मिल सके। यह गांव के लोगों के हाथ में गांव का काम है। सरकार यह योजना किसान, आम लोगों और युवाओं के लिए लेकर आई है। आप भी उसका लाभ उठाइए। आपका क्षेत्र देवदार के बहुत अच्छे पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, आप इस योजना का लाभ उठाइए। इसमें हमने 7 प्रतिशत फलदार पौधों को लगाने का भी प्रावधान रखा है। हमारा मानना है कि फलदार पौधे भी जंगलों में लगने चाहिएं ताकि हमारे पुराने रिवाजों को भी जीवित रखा जा सके।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' के लिए हमारे क्षेत्र व जिला के अंदर जो नर्सरीज़ हैं, जहां से प्लांट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनकी पेमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रोब्लम्स

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1140/एच0के0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 4063 जारी ..... **श्री नीरज नैय्यर जारी** .....

अध्यक्ष : यह मांग नहीं है, आप प्रश्न पूछो कि पेमेंट्स हो चुकी हैं या अभी तक नहीं हुई हैं?

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनकी पेमेंट होगी या नहीं? यह पेमेंट छोटी हैं। इन पेमेंट्स का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इन सभी पेमेंट्स की एक डेढ़ साल से बहुत ज्यादा पेंडेंसी है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, the maintenance of nurseries.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने जो अंतिम सप्लीमेंट्री पूछा है, यह बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री प्रश्न है। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात की है कि

नर्सरी वाले जो पौधे पैदा करते हैं, उनको पेमेंट नहीं होती। हम पेमेंट्स के बारे में भी एक एस0ओ0पी0 बनाएंगे ताकि उचित समय में पेमेंट हो सके। ऐसा नहीं हो कि वह पेमेंट्स के लिए लटका रहे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी द्वारा यह पूछा गया है कि फोरेस्ट विभाग ने जो नर्सरी मेंटेन की है जहां से प्लांटेशन होगी, उन नर्सरी को मेंटेन करने वाले लेबर के बारे में है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं। उनको मेंटेन करने के लिए जो उनके पैसे नर्सरी विभाग में लगे है। हर महीने उन्हें मिलने चाहिए और इसके लिए हम एस0ओ0पी0 बनाएंगे।

25.03.2026/1140/एच0के0/ए0पी0/-02

प्रश्न संख्या : 4064

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मेरा प्रश्न था उसके रिगार्डिंग मुझे सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें मेरा पहला नंबर है लुहरी-जाजर वाया सोईधार का और जो यहां पर डिटेल दी गई है। उस डिटेल के अनुसार सड़क को चौड़ी करना और जी0एस0बी0 (Granular Sub-Base) का काम इसमें लगभग हो गया है। परंतु वहां पर धरातल पर स्थिति ये है कि वन महकमा और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की आपस में लड़ाई चली है। क्योंकि ये सड़क वर्ष 1970 से पहले बनी है। उस सड़क को जब पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा चौड़ा करना था तो फॉरेस्ट विभाग उसके बीच में आ गया था और फॉरेस्ट विभाग द्वारा कहा गया कि सड़क को चौड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी एफ0सी0ए0 नहीं है। इसलिए वहां का काम रुका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बहुत पुरानी सड़क है और इस सड़क में बहुत-सी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। रात को लोग इस सड़क को आज की स्थिति में चलने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग इस पर ओर ध्यान दें। यहां पर मुझे सिर्फ अधिकारियों ने लिख कर जवाब है। लेकिन जमीन पर जो भी काम करना है या धरातल पर जो काम हो रहा है उसे ढंग से करना होगा।

क्योंकि अभी तक इसमें काम नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरी वहां पर बातचीत हुई है कि सिर्फ एफ0सी0ए0 की वजह से इस काम को रोका गया है। दूसरी सड़क भी है जिसमें उन्होंने पैसा दिया हुआ है। यह सड़क है हरिपुर आनी से तलूना गांव। इस सड़क की स्थिति भी बहुत खराब है। दलाश से कंडागई सड़क के बारे में बताया गया है कि इस सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु दलाश से कंडागई सड़क की वर्तमान में जो स्थिति है वह यह है कि उस सड़क में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। इस सड़क की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे पांचवी सड़क पर आ रहा हूं। लूहरी से नित्थर सड़क जिसमें एम0डी0आर0 का एक भाग है जोकि स्टेट बजट पर बनाई गई है। यह है लूहरी से नित्थर एम0डी0आर0-120। इसमें दिक्कत यह है कि लूहरी पांच किलोमीटर के बाद हमारी फल मंडी है। जहां पर कुछ दिनों के बाद सेब सीजन शुरू होगा। इस मंडी में करसोग, सिराज, आनी, किनौर और रामपुर से सेब वहां पर आता है। सड़क कि चौड़ाई कम होने

25.03.2026/1140/एच0के0/ए0पी0/-03

के कारण, वहां बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं और इस सड़क से ट्राले नहीं जा पाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में तो लिखा है कि इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पांच किलोमीटर के पैच को खोला दिया जाए, यह मैं आदरणीय मंत्री जी से चाहूंगा। दूसरा गुगरा से कुटवा डोहवी सड़क।

अध्यक्ष : यह तो छठा प्रश्न आ गया। आप बाद में पूछ लेना। पहले इनका जबाव आने दें। माननीय लोक निर्माण मंत्री।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी ने एक बड़ा एक्सॉस्टिव और अक्यूमुलेटिव प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी विधान सभा की सभी सड़कों का प्रश्न एक ही प्रश्न में लगा लिया है। हमारा प्रयास है, आनी के साथ मेरी और हमारी सरकार की संवेदनाएं भी हैं और खासा प्यार आपके साथ है, आपके

इलाके के साथ है। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने तकरीबन छह सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पहली सड़क आपने कही है लूहरी जाजर वाया सोईधार से दलाश सड़क को पी0एम0जे0एस0वाई0 (3) बैच 2 वर्ष 2023-24 में 15 करोड़ रुपये की लागत से इसे स्वीकृति प्राप्त हुई है। **यह कार्य ठेकेदार द्वारा 1 करोड़ 26 लाख रुपये में अवंटित हुआ है और इस सड़क का कार्य कार्यरत है और सड़क का कार्य समय पर पूरा किया जाएगा।** इस सड़क के उन्नयन कार्य टायरिंग तथा सड़क को चौड़ा करने के लिए कार्य प्रगति पर है। अभी तक इस सड़क पर 302 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है और मूल्य तकरीबन 9 करोड़ रुपये का कार्य इसमें अभी शेष है। **जिसे वर्ष 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा।** दूसरी सड़क के बारे में अभी माननीय सदस्य द्वारा ज़िक्र किया गया है हरिपुन आनी से तूलना गांव सड़क

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1145/AT/HK/01

प्रश्न संख्या 4064 जारी..... लोक निर्माण मंत्री जारी...

के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, टायरिंग तथा सड़क को चौड़ा करने का कार्य PMGSY-I के तहत वर्ष 2019 में पूर्ण कर दिया गया है। इस पर कुल मु0 181 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

तीसरा जो माननीय सदस्य ने कहा है कि दिलास से कंडागई सड़क के उन्नयन की बात कही है। यह कार्य नाबार्ड RIDF-27 के अंतर्गत वर्ष 2019 में पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में इस सड़क के लिए किसी भी मद में कोई बजट का प्रावधान नहीं है लेकिन विभाग अपनी मशीनरी और लेबर के माध्यम से इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। जो ये FCA की एक सड़क का जिक्र कर रहे हैं। उसका मैं इनसे संज्ञान ले लूंगा। जहां-जहां वन विभाग से अभी तक क्लीयरेंस नहीं मिल पाई है। उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक टीमरी धार सड़क है, इसको भी हमने PMGSY-IV में डलवाया था। लेकिन PMGSY में एक कंडीशन होती है कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन्स को कनेक्ट किया जाएगा। इस सड़क में डबल कनेक्टिविटी होने के कारण और अब सब कुछ जीओ-टैगिंग के माध्यम

से होता है। लेकिन इसको ऑनलाइन दिखा रहा है। जिसकी वजह से यह कनेक्टिविटी नहीं हो पाई।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि PMGSY-IV में जो स्वीकृतियां मिली हैं उनमें सबसे अधिक स्वीकृति आपके विधान सभा क्षेत्र में आई है। यहां कुल 26 सड़कें पूरी हुई हैं और 259 करोड़ रुपये की राशि आने वाले समय में इस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आने वाले समय में खर्च की जाएगी। इसका श्रेय हमारे विभाग के अधिकारियों, JE और XEN को जाता है। जिन्होंने समय पर DPR बनाकर के दिल्ली भेजी। यह एक सामूहिक प्रयास होता है। आपके क्षेत्र में सड़कों से जुड़े अन्य कार्यों को भी हम चरणबद्ध तरीके से बजट के प्रावधान के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे।एक आपने जो मंडी के खैखसू क्षेत्र की बात की है। क्योंकि वह निथर का इलाका है, मैंने भी वहां का बहुत बार दौरा किया है। तो फिलहाल उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में हम

25.03.2026/1145/AT/HK/02

AMP के तहत कुछ बजट उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे और उसको चलता हुआ करने का प्रयास करेंगे। ताकि जितने हमारे लोग मंडी में आते हैं, रामपुर और आनी से आ रहे हैं उनको सुविधा मिल सके।

25.03.2026/1145/AT/HK/03

प्रश्न संख्या - 4065

श्री मलेन्द्र राजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इंडोर स्टेडियम के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा भी है। यह बॉर्डर क्षेत्र में नशे की समस्या भी बहुत रही है और युवाओं के लिए यह इंडोर स्टेडियम की जो घोषणा की हुई है। वह ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जैसे ही इसकी DPR तैयार होकर विभाग के पास आती है, क्या इसका तुरंत बजट प्रावधान करके कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, इसके अलावा भी कई मामले आपके पास लंबित पड़े हैं, जिनमें मेरा क्षेत्र भी शामिल है।

आयुष मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि भूमि स्थानांतरण का मामला 12-12-2025 को खेल विभाग के नाम पर भूति स्थानांतरण हो चुकी है। खेल विभाग के DSO कांगड़ा ने अधिशासी अभियंता इंदौरा को DPR बनाने के लिए लिखा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि सौभाविक रूप से PWD विभाग का में जो XEN है वह आपके कहने पर लगा हुआ है, उसको आप आदेश करें कि जल्द-से-जल्द उसकी DPR आप तैयार करें। जैसे ही DPR तैयार होगी हम उसे तुरंत वित्त विभाग और माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

अध्यक्षः क्या इसमें FCA हो गया है?

आयुष मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, FCA का यह मामला नहीं है। यह सरकारी भूमि है, जिसकी केवल लैंड ट्रांसफर हुई है।

प्रश्न संख्या 4066 श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1150/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या 4066

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) Programme तथा Invest India के अंतर्गत 5 ऑफिसर, 3 विधायक और 1 कंसल्टेंट जापान, हांगकांग एवं वियतनाम घूमने के लिए गए थे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घूमने के लिए नहीं गए थे, ये दौरा करने गए थे।

श्री बिक्रम सिंह : जी, सर। इन्होंने एक्सपोज़र विज़िट बताई है। इस पर 2,04,22,830/- रुपये की धनराशि व्यय हुई थी। मैंने पूछा था कि इसका क्या फायदा हुआ तो उत्तर आया है कि यह एक एक्सपोज़र विज़िट थी अतः इस दौरे का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से निवेश को आकर्षित करना नहीं था। फिर यह कैसा दौरा था और इसका क्या उद्देश्य था और इस एक्सपोज़र से प्रदेश को क्या लाभ मिला? जो आपका RAMP है, क्योंकि यह पैसा भारत सरकार से आता है, तो Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) Programme के अंतर्गत हमें कितना बजट मिला और उसमें से कितना बजट खर्च कर दिया गया?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय बिक्रम सिंह जी भी उद्योग मंत्री रहे हैं। ऐसे-ऐसे भ्रमण में ये भी गए हैं। जो इन्होंने प्रश्न किया, मैं कहना चाहूंगा कि RAMP में प्रोविज़न है और यह भारत सरकार का प्रोजैक्ट है। इसकी गाइडलाइन्ज़ के अनुसार इसका एक इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम भी है। इसमें यह है कि हमें मैन्युफैक्चरर्स को कंज्यूमर्स तक भी ले जाना है। इसमें Reverse Buyer Seller Meet होती है। हम इन तीन देशों में गए थे और अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य के डेलिगेशन ने इन्वेस्टर्स के साथ, वहां की जो एंबेसीज़ हैं, वहां पर मीट की है। हम जापान गए थे, जापान की एंबेसी ने हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। इन्वेस्टर्स को वहां बुलाया। इसके अलावा हांगकांग में भी जो वहां की एंबेसी है, उन्होंने हमारा सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। वियतनाम में हम सियोल में गए वहां भी उन्होंने हमारा सारा फंक्शन किया। इसके अतिरिक्त जापान में मैडिकल जापान प्रदर्शनी, 2025 का भी निरीक्षण किया जिसमें जापान के विभिन्न उद्योगों एवं स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में निवेश की सम्भावनाओं पर चर्चा की गई तथा Reverse Buyer Seller Meet में भी

चर्चा की गई। इसके उपरांत हांगकांग में पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इलैक्ट्रोनिक्स से सम्बन्धित औद्योगिक क्लस्टर का भी भ्रमण किया गया। वियतनाम में हमारी जो यंग बैंग इंडस्ट्रियल स्टेट है, ई0वी0 मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोसैसिंग है, वियतनाम में हनोई स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से एक इंट्रेक्शन सैशन भी रखा गया । इसके अलावा हमने इन तीनों देशों में हिमाचल प्रदेश के जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन बिजनैस कम्युनिटी

है, उनको बुलाया, उनके साथ इंट्रैक्ट किया। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, हेंडीक्राफ्ट हैंडलूम, इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी आदि सैक्टर के बारे में हमने वहां पर बातचीत की। श्री अनिल शर्मा जी भी उस डैपुटेशन में हमारे साथ थे। आप इनसे भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है, अमूमन ऑफिसर और मिनिस्टर ही डेलिगेशन में जाते थे। यह पहली बार है कि मुख्य मंत्री जी ने चाहे वह इंडस्ट्री के डेलिगेशन्ज़ हैं, फोरैस्ट या एग्रीकल्चर के डेलिगेशन्ज़ हैं,उनमें पहली बार विधायकों को डाला और हमारा जो डेलिगेशन गया था उसमें हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी थे,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1155/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 4066------- क्रमागत

उद्योग मंत्री---- जारी

उस डेलिगेशन में श्री विपिन सिंह परमार जी भी थे ...(व्यवधान) Hon'ble Speaker, Sir, Shri Vipin Singh Parmar Ji was part of the delegation but he couldn't join us. माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह, अगली बार हम आपको भी लेकर जाएंगे।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री से यह पूछा है कि यह जो आर0ए0एम0पी0 कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कितना बजट दिया? दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जब यहां पर इतनी बातें लिख दीं तो यहां पर यह लिखने का क्या मतलब था कि "इस दौरे का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से निवेश को आकर्षित करना नहीं था"। जबकि यह इसीलिए किया गया था क्योंकि आर0ए0एम0पी0 के अंतर्गत ऑब्जैक्टिव्ज में यह कहा गया है कि हम जहां जाएंगे वहां पर जाकर चीजों को समझेंगे। उसके बाद उसको हिमाचल प्रदेश में लागू करवाएंगे जिससे कि यहां पर इन्वैस्टमैंट आएगी। यह एक्सपोज़र लेने या कोई घूमने-फिरने वाला टूअर थोड़ी न है? आप वहां पर अच्छा काम करके आए हैं जिसके बारे में मुझे माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा ने बताया है। इन्होंने फोटो निकालकर बताया है कि मेरी यहां भी मीटिंग हुई और वहां

भी हुई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जा आए यह अच्छी बात है। लेकिन यदि मौजूदा उद्योग मंत्री जा रहे हैं तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि उसमें हम भी जा सकते हैं। इसलिए जब भी अगली बार ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। हम माननीय मुख्य मंत्री के धन्यवादी है क्योंकि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है कि इस डेलिगेशन में विधायकों को भी सम्मिलित किया। लेकिन मैंने जैसे इसके उद्देश्य और ऑब्जैक्टिव्ज के बारे में पूछा था तो उसका विस्तृत उत्तर आना चाहिए था क्योंकि फिर दो-चार चीजें और पूछी जा सकती थीं। माननीय उद्योग मंत्री, अब आप इसमें बजट के प्रावधान की जानकारी दीजिए?

25.03.2026/1155/av/yk/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें एम0एस0एम0ई0 में आर0ए0एम0पी0 के प्रोजैक्ट्स के अंतर्गत 105 करोड़ रुपये अलग-अलग सेक्टर में आए हैं। इसमें एक्सपोज़र बिजनैस के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये आए हैं जिसमें से इस पर दो करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा हमने पहली बार एम0एस0एम0ई0 का रिज़ के ऊपर फैस्ट किया था जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री जी ने की थी। हमने उसमें हैण्डीक्राफ्ट और हैण्डलूम का प्रदर्शन किया था। वहां पर लगभग 2500 रुपये की हैण्ड वूवन शॉल्ज एक ही मंच पर एकत्रित की थी जिससे कि हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उस वक्त हमने अपनी महिला एन्टरप्रेन्योर्ज का एक सम्मेलन किया। इसके अलावा हमने वहां पर 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' का प्रदर्शन भी किया। हमने भारत के लगभग 250 टोप सी0ई0ओज0 को बुलाया और पीटरहॉफ में सम्मेलन किया। जिसमें हमारे लगभग 10,000 करोड़ रुपये के करीब एम0ओ0यू0 साइन हुए और हमने 10,000 करोड़ रुपये में से 2500 करोड़ रुपये की सिंगल विंडो क्लीयरैंस में उनकी क्लीयरैंस की है। हम अब उनको लैण्ड उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए हम निजी या सरकारी भूमि देखेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में निवेश आए। अगली बार जब हमारा उद्योग विभाग के अंतर्गत कोई डेलिगेशन जाएगा तो हम एन्श्योर करेंगे कि उसमें हमारे पूर्व उद्योग मंत्री जी भी हमारे साथ जाएंगे। यह जो फॉरेन

ट्रिप हुआ था इसमें हिमाचल सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा था, इसमें भारत सरकार के प्रोजैक्ट का पैसा लगा था।

25.03.2026/1155/av/yk/3

प्रश्न संख्या : 4067

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने जो 'राजीव गांधी डे बोर्डिंग' योजना शुरू की है, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से 'अटल आदर्श विद्यालय' नामक एक योजना चलाई थी। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुख्य मंत्री जी की ओर से आना चाहिए। क्या आप हमें यह जानकारी देंगे कि अटल आदर्श विद्यालय योजना जो पूर्व सरकार ने चलाई थी वह बंद कर दी गई है? अगर बंद कर दी गई है तो उसकी क्या वजह रही या आपने अटल आदर्श विद्यालय का नाम बदलकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग किया है?

टी सी द्वारा जारी.....

25.03.2026/1200/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या : 4067 जारी श्री जय राम ठाकुर.. जारी

अगर राजीव गांधी के नाम पर किया गया तो क्यों किया गया जबकि दोनों पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? क्या यह एथील्स और पर्टिकुलरली किसी के सम्मान के विरुद्ध नहीं है? आप यह बात स्पष्ट करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करती है क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और संस्कार सभी उच्च पदों पर रहने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। आपने अटल टनल का नाम बदल दिया जबकि उसका फाउंडेशन स्टोन राजीव गांधी टनल के नाम से रखा गया था। ...(व्यवधान) आप सुनो तो सही। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैंने एन0एच0आई0 और डिफेंस मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है कि अटल टनल का फाउंडेशन श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा रखा गया था इसलिए उसका नाम उनके नाम पर रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री साहब ने अटल आदर्श विद्यालय के बारे में पूछा है। आपने अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना की जबकि वास्तव में यह बोर्डिंग स्कूल था। इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी थी और इस योजना को बंद नहीं किया गया है। इस अधूरी योजना को पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवा रहे हैं ।

दूसरी योजना राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है। जब हमने देखा कि शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में बहुत कमी आई है और वर्ष 2021 में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए तो हमने शिक्षा नीति को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग योजना लाई। इसमें सिर्फ डे में बच्चे रहेंगे और शाम को अपने घर जाएंगे। इसलिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना अलग है और अटल आदर्श विद्यालय योजना अलग है। अटल आदर्श विद्यालय में हॉस्टल है और डे बोर्डिंग में हॉस्टल नहीं है। यह हमने इसलिए भी किया क्योंकि प्री नर्सरी से लेकर प्लस टू तक के छोटे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, उनको उनके लिए दिन में खाने की व्यवस्था की ताकि वे ट्यूशन भी पढ़ें वहां और अच्छा पढ़कर क्वालिटी एजुकेशन लेकर भविष्य की दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। इसलिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की योजना लेकर आए हैं और जो अटल आदर्श विद्यालय है, वह

25.03.2026/1200/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

बोर्डिंग स्कूल वाला है उसको भी बंद नहीं किया गया है। प्रधानमंत्रियों का सम्मान करना हमारी सरकार की नीति है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, हम सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं। अटल आदर्श विद्यालय को बंद नहीं किया गया है।

प्रश्न काल समाप्त।

25.03.2026/1200/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

अध्यक्ष : अब जीरो आवर होगा। जीरो आवर में मेरे पास बहुत सारे विषय आए हैं। 13 माननीय सदस्य जीरो आवर में अपना विषय रखना चाहते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे

विषय हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से रिप्लाई हो चुके हैं या भविष्य में लगे हैं। My request to the Hon'ble Members is that the issues, which are already listed in the shape of questions, whether starred or unstarred, and the reply has been given, and you are not satisfied with the reply, then you resort to other methods, not to the Zero Hour. अब इससे पहले कि मैं जीरो आवर शुरू करूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी स्पष्टीकरण हेतु अपना विषय उठाना चाहते हैं।

स्पष्टीकरण

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपकी ऑनेस्ट कमिटमैंट थी कि मुझे प्रश्न काल के बाद स्पष्टीकरण हेतु मौका दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो टिप्पणी की है, वह अपने आप में बहुत गंभीर टिप्पणी है और वह बार-बार इस टिप्पणी को दोहराते हैं कि पूर्व मुख्य मंत्री तथ्य पर नहीं बोलते। उसके बाद जब आपने बोला तो कहा कि आप भी गलत बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, क्या यहां पर एक ही आदमी ठीक बोलते हैं बाकी सब गलत बोलते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : यह ठीक है कि वह रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है लेकिन इन्होंने बोला है।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

25-3-2026/1205/NS-AG/1

श्री जय राम ठाकुर-------जारी

अगर बात कही है तो दूर तलक जाएगी। आपका बार-बार इस प्रकार से टिप्पणी करना और व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना सही नहीं है। हम व्यवस्था पर बोलें, हम सिस्टम पर बोलें तो उचित लगता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसके आगे बात कही कि मैंने पार्लियामैंट के सामने कोई इंटरव्यू दिया है। मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला था और मैं रास्त में चला था, गाड़ी में बैठने से पहले मीडिया वालों ने रास्ता रोक दिया तो वहां पर मैंने दो बातें कही हैं। मैंने गलत क्या कहा? क्या यह सत्य नहीं है कि इसी माननीय सदन में

आपके द्वारा बिल लाया गया था जिसका हमने विरोध किया और उसमें विधवा और अनाथ बच्चों के लिए सैस लगाने की बात थी? हमारे विरोध के बावजूद भी वह बिल पारित हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बिल पारित नहीं हुआ? ठीक है, उसकी एक प्रोसैस है और आगे उसकी असेंट राज्यपाल महोदय से होनी है, नोटिफाई होना है और फिर लागू होगा। लेकिन बिल तो पारित हुआ और मेजोरिटी के साथ पारित हुआ है। हमने इसमें क्या गलत बोला? हमने तब भी हाउस के अंदर विरोध किया था और हाउस के बाहर भी उसका विरोध किया। उन्होंने मुझसे पर्टिकुलरली पूछा कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का कोई बिल आया है। तब मैंने वहां पर बात कही। मैंने क्या गलत कहा, क्या तथ्य छिपाया और क्या तथ्य गलत बोला? दूसरा, आपने कहा कि आपको आदत पड़ गई है, आपके नेताओं को और (***) मैंने तो नहीं बोला लेकिन मैं सोचता हूं कि बोल ही दूं। (***)के प्रधानमंत्री के ऊपर भद्दी-से-भद्दी टिप्पणियां करे या करते रहें और उसके बावजूद हम नहीं बोलें, यह कैसे संभव होगा? अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलना पड़ेगा।

अध्यक्षः (***)that will not be a part of the record.

Shri Jai Ram Thakur: Why it should not be part of the record?

अध्यक्षः (***) and since he is not the Member of this House and will not be in a position to reply to any reference made, and the (***) is also not a Member of this House, so that will not be a part of the record.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

25-3-2026/1205/NS-AG/2

श्री जय राम ठाकुर : मैं अपनी बात कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस हाउस के पार्ट हैं? वे प्रधानमंत्री हैं।

अध्यक्ष : प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोले गए हैं, अगर बोले जाएंगे तो मैं रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनने दूंगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, कहां क्या-क्या बातें की जाती हैं? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके नेता के बारे में हमें बोलना है तो उसकी इजाजत आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही आप हमारे नेताओं के बारे में बोलने की इजाजत लेते हैं।

अध्यक्ष : आप इस माननीय सदन के अंदर मत बोलें, आप बाहर जो मर्जी बोलें।

श्री जय राम ठाकुर : मैं तो यह भी कहूंगा कि आपने ड्रेस कोड लाया तो अपने ही नेता को ड्रेस कोड की थोड़ी संज्ञा दीजिए। आपने यह भी बात कही है और अब बात आगे तक जाएगी।

अध्यक्ष : इन्होंने हिमाचल में लाया कोई देश के लिए नहीं लाया। यह तो हिमाचल प्रदेश में लाया। इस बात को लोकसभा वाले बोलें।

श्री जय राम ठाकुर : (***) आप अपनी पार्टी के नेताओं को भी समझाएं कि कपड़े उतार करके किस प्रकार से पार्टी में प्रदर्शन करते हैं।

Speaker: This will not be a part of the record कि (***) This is objectionable. ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये बातें तो कहनी पड़ेंगी। अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करेंगे तो इनके नेताओं के बारे में भी बोला जाएगा।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

25-3-2026/1205/NS-AG/3

अध्यक्ष : (***) This will not be a part of the record. Any reference regarding (***) and (***) is not a part of the record.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी बार-बार इस प्रकार से टिप्पणी करते रहे और मैं आज तक नहीं बोला लेकिन आज बोलना पड़ा क्योंकि इन्होंने टिप्पणी की। ये बार-बार इस प्रकार से टिप्पणी करते रहे और हर बात पर राजनीति करते रहे। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रदेश के विषयों पर चर्चा की और

गंभीर चर्चा हुई कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए और किस तरह से मदद कर सकते हैं, तमाम इश्यूज पर चर्चा हुई है।

अध्यक्ष : यह अच्छी बात है।

श्री जय राम ठाकुर : यहां पर मेरी गैर मौजूदगी में बोला जाता है कि जय राम चला गया, दिल्ली चला गया, रोकने के लिए चला गया। जैसे कि हम आपको बता कर गए कि हम क्या करने के लिए गए हैं? क्या हमें आपसे पूछ कर जाना है? इन बातों को बारे-बार राजनैत्तिक दृष्टि से नहीं करना चाहिए। आप अपने नेताओं को मिलने जाते हैं तो हमने कभी टिप्पणी नहीं की।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

25.03.2026/1210/RKS/As-1

श्री जय राम ठाकुर जारी.....

कल श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने यह बात कही है और यह कार्यवाही का हिस्सा है। ...(व्यवधान) भविष्य में क्या होना है, यह तो आप तय नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

Speaker : Let's take it in a lighter way. आपने कुछ रेफरेंस ऐसे कर दिए हैं, जिन पर रिएक्शन होना वाजिब है।

श्री जय राम ठाकुर : मैंने तो सिर्फ यही कहा कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। आप मान रहे हैं कि हमेशा के लिए आपकी सरकार सत्ता में रहेगी लेकिन आने वाले समय में आपकी सरकार नहीं होगी, यह बात तय है। ...(व्यवधान) इसमें आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही है? हम राजनीति में हैं और स्वाभाविक रूप से हम भी राजनीतिक टिप्पणी करेंगे और आप भी। लेकिन मुख्य मंत्री जी जब सदन के अंदर बोल रहे हों तो जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए और जो बातें पूछी जाएं उन्हीं का ही जवाब देना चाहिए। आप बिल्कुल विशुद्ध राजनीति के आधार पर टिप्पणियां करते हैं जोकि उचित नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता स्वयं जो टिप्पणियां करते हैं उन्हें बाद में भूल जाते हैं। आप इनका भी रिकॉर्ड निकलवाएं और मेरे रिकॉर्ड की कॉपी भी इन्हें भेज दें।

अध्यक्ष : आप दोनों ही आज अच्छे मूड में और फुल ऑफ एनर्जी हैं इसलिए मैं आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूं। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : नेता प्रतिपक्ष जी, हमने कभी अटल आदर्श विद्यालय का नाम बदलने की बात नहीं की है। ...(व्यवधान) कल आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में बोल रहे थे। हमने यह टिप्पणियां कब कीं? ...(व्यवधान) आप तनाव में अपनी बात भूल जाते हैं। ...(व्यवधान) इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, यह आपका कसूर है। अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा आपका सम्मान करते हैं। ...(व्यवधान)

25.03.2026/1210/RKS/As-2

मैंने आपको कहा था कि बिल पास होने से हमें भविष्य में सैस लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ है लेकिन उस एक्ट में गवर्नर साहब की असेंट के बाद ही हमें पावर मिलेगी। आपने कहा कि हम विधवाओं और अनाथ बच्चों के नाम पर 5 रुपये सैस लगा रहे हैं और बाद में यह 100 रुपये तक हो जाएगा। लेकिन अभी हम यह सैस कहां लगा रहे हैं? मैंने कहा था कि यह अधिकार मिलने के बाद सरकार विचार करेगी कि कितना सैस लगाना है। उसमें अधिकतम सीमा 5 रुपये है। हम न्यूनतम सैस भी लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में यह कहना कि सैस लगा दिया है, गलत है। दिल्ली के गलियारों में इस प्रकार की बात कहना उन विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए अपमानजनक है। ...(व्यवधान) राजनीति आप कर रहे हैं। आप पूरी शब्दावली की राजनीति कर रहे हैं। आप यह अच्छी तरह समझते हैं कि मैंने क्या कहा है। आप जानबूझकर अनजान बनते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि आप बड़े शराफत वाले आदमी हैं। ...(व्यवधान) आप पूरे पॉलिटिशियन हैं।

अध्यक्ष : मुझे मालूम है आप दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं।

मुख्य मंत्री : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये अपनी बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ...(व्यवधान) यह अच्छी बात है। आप रात को अच्छी नींद लिया करें। नींद न आने के कारण आप बार-बार सीट से उठते हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये इस खुशफहमी में रहते हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सरकार नहीं जाएगी। ...(व्यवधान) आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं। आप मेरा पिछला इतिहास देख लें। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, आप इनको मेरा पिछला इतिहास बताएं। मैं जिस पद पर रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं। अभी तो मेरा लंबा समय शुरू भी नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

25.03.2026/1210/RKS/As-3

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप इस प्रकार की बातें करके इन्हें डराया न करें। आप इन सबको डराते रहते हैं तभी तो ये ऐसा बोलते हैं। ...(व्यवधान) आपको हिमाचल प्रदेश की जनता लंबे समय तक रखेगी। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : श्री जय राम ठाकुर जी, यह तो कर्मों का फल और भगवान का आशीर्वाद होता है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1215/बी.एस./ए.एस.-1

मुख्य मंत्री जारी...

और साथियों का आशीर्वाद होता है। अगर सरकार जानी होती तो जिस दिन आपने बोला था न कि सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, उसी दिन चली जाती और उस दिन सरकार जाने के बहुत मौके थे। लेकिन इसी भगवान ने हमें दोबारा बनाया। उन्होंने कहा नहीं इन्होंने प्रदेश को लुटाया है उन्ही को लाओं जो प्रदेश की संपदा को बचाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

25.03.2025/1215/बी.एस./ए.एस.-2

शून्यकाल आरंभ

अध्यक्ष : यह सब कुछ पहले हो चुका है। अब शून्यकाल है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे विषय हैं। मैं सबसे पहले श्रीमती रीना कश्यप, माननीय सदस्य पच्छाद, को बोलने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आपका समय बड़ा ब्रीफ होता है।

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शून्यकाल में मुझे बोलने के लिए समय दिया। कई दशक पूर्व हिमाचल प्रदेश के कल्याण विभाग, ग्राम पंचायत, कोटला पंचोला, धार गनयान में घरों का निर्माण कर एक कॉलोनी बसाई गई थी। जिस भूमि पर यह कॉलोनी बसाई गई, वह राजस्व अभिलेख में कल्याण विभाग के नाम है और इस कॉलोनी में बसे हुए लोग अनुसूचित जाति से संबंधित लोग हैं और बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में भूमि कल्याण विभाग के नाम होने के कारण इन लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये लोग काफी लंबे समय से कच्चे मकानों में ही वहां रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा कि आप संबंधित विभाग को आदेश दें कि जो लोग 50 वर्षों से लगभग 300 लोग वहां रह रहे हैं उनके मकान इसी जमीन पर बनाए जाएं और उन लोगों को वहां रहने के लिए कल्याण विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 दी जाए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन मंत्री जी से करना चाहूंगी।25.03.2025/1215/बी.एस./ए.एस.-2

अध्यक्ष : माननीय सवदस्य, आपने एक बहुत गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और निश्चित तौर से मंत्री जी, मंत्रालय और अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया होगा। विधान सभा सचिवालय ने भी इसका संज्ञान लिया है और विभाग से कहा

जाएगा कि वे आपके द्वारा उठाए गए विषय पर कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से आपको और सदन को अवगत कराया जाएगा।

25.03.2025/1215/बी.एस./ए.एस.-3

अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती जी शून्य काल में अपना विषय उठाएंगे। I am giving a chance to those persons whose issues are very important.

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं ऊना के अंदर जो एक वन कटान का मामला बार-बार उठा रहा हूं उसके बारे में वर्तमान सरकार को आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। इसमें माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी का भी प्रश्न लगा था। प्रश्न संख्या 4063, जिसके अंदर यह विषय लिया गया था कि वर्ष 2024 में वृक्षारोपण के लिए कितने पैसे खर्च किए गए तो उत्तर में आया कि लगभग 53, 04,69,728 रुपये खर्च किए गए। इसी तरह से वर्ष 2025-26 में 26,73,09,590 रुपये खर्च हुए हैं। हम लोग हर साल कुल मिलाकर इतना पैसा वृक्षारोपण के लिए लगाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऊना जिला के अंदर पिछले लगभग दो-ढाई वर्षों से जो विषय ध्यान में आ रहा है, पहले भी वहां पर छोटा-मोटा वन कटान चलता था और लोगों को पकड़ा भी जाता था लेकिन अब स्थिति यहां तक आ गई है कि, क्योंकि वन मंत्री जी की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी के पास है। अभी अनेक क्षेत्रों में, चाहे कुटलैहड़ के क्षेत्र हो, आदरणीय विवेक जी यहां पर बैठे हैं, चाहे चंबल गांव का मामला हो, चाहे लठियानी गांव का मामला हो और चाहे गगरेट विधान सभा क्षेत्र का मामला हो। ऊना में पेड़ों का कटान बड़े स्तर पर हो रहा है, अखबारों में आ रहा है कि एक-एक हजार पेड़ अवैध रूप से काटे गए। इसका सरकार को एक बार निरीक्षण करवाना चाहिए और मेरा मानना है कि यह निरीक्षण स्थानीय वन अधिकारियों या स्थानीय पुलिस से नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी से करवाया जाना चाहिए। जितने भी जंगल वहां काटे गए हैं। वहां पर 40-40 ट्रक लकड़ी से भरे हुए पकड़े गए हैं पुलिस ने इसकी फोटोज भी अखबार में दी हैं, इतना बड़ा वन कटान ऊना जिला में हो रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि हम लोग करोड़ों रुपया वृक्षारोपण पर खर्च कर रहे हैं। अगर ये पेड़ बचेंगे तो 10-20 साल बाद इतने होंगे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1220/DT/DC-1

शून्य काल जारी

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी

ये सदियों से लगे हुए पेड़ हैं। लेकिन आजकल लोग उनको काट कर अपना घर भर रहे हैं, ऐसा भी देखने में आ रहा है। इसमें मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं करता। लेकिन वन विभाग के कुछ अधिकारी इसमें संलिप्त हैं बहुत से कर्मचारी अन्य विभागों के भी इसमें संलिप्त हैं। इसलिए पेड़ न कटें और जंगल सुरक्षित रहें, उसके लिए मेरा एक सुझाव यह रहेगा कि जब पेड़ों पर निशान लगाये जाते हैं तो उस समय इनकी विडियोग्राफी की जाए।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी भट्टियां यानी बॉयलरज लगाये गये हैं वे जंगलों के पास है। ये बॉयलरज सड़क के किनारे यानी किसी पब्लिक पलेस में लगाये जाने चाहिए और वहीं पर खैर की लकड़ी आये और वहीं पर कथे का जो भी काम होना है वह हो।

प्राइवेट एरियाज में खैर कटान की परमिशन 10 साल बाद दी जाती है। उसी की आड़ में अगर उसके साथ लगती वन भूमि है तो वहां पर पेड़ों का कटान कर दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी वन भूमि में लगे पेड़ों का कटान अगर पहले हो जायेगा तो प्राइवेट लैंड के बहाने ठेकेदर जो सरकारी जंगल के अंदर कटान कर जाते हैं, वह शायद नहीं होगा। ऐसे तीन-चार मेरे सुझाव भी हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा।

अध्यक्ष : वैसे माननीय सदस्य हमारे ध्यान में आपका ही प्रश्न है जो 28 मार्च को लगा है, यद्यपि आपने एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है, मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी।

25.03.2026/1220/DT/DC-2

अब डॉ0 जनक राज शून्य काल में अपना विषय रखेंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में आपने मुझे अपना विषय रखने का मोका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष मणिमहेश यात्रा का, जो हिमाचल प्रदेश में लोगों की आस्था, विश्वास और सांसकृतिक पहचान का प्रतीक है, उस के संबंध में कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष मानसून सीजन में भारी वर्षा के कारण एक भयानक आपदा का रूप मणिमहेश मे देखने में आया। यह प्रबंधन की ही कमी रही जिसके कारण हजारों लोगों को परेशानी हुई सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इस वर्ष, अभी मणिमहेश यात्रा में चार माह का समय शेष है, इसलिए समय रहते इसके लिए सरकार और प्रशासन को तैयारी कर लेनी चाहिए। पिछले वर्ष की आपदा जो इस क्षेत्र में आई उसके अनुभवों के दृटिगत मेरे कुछ सुझाव हैं और यह सुझाव ठोस और अनिवार्य सुझाव के रूप में भी लिए जा सकते हैं। पहले तो मौसम आधारित ग्रीन और रेड कॉरिडोर लोगों के आने-जाने के लिए बनाए जाएं। यात्रा मार्ग पर चलने के लिए लोगों की संख्या नियंत्रित की जाए, लोगों का पंजीकरण आवश्यक किया जाये, हर पांच किलोमीटर के बाद हाइ एलटिट्यूड सिकनेस के लिए मेडिकल सेंटर्ज बनाए जाएं। एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 की टीमों की प्री-डिप्लॉयमेंट वहां पर की जाए। मैं माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि पिछले वर्ष इन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में उपस्थित होकर वहां के लोगों को आपदा में राहत देने का कार्य किया। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि वहां पर जो कुछेक स्लाइडिंग जोंस भी हैं, इसके लिए जो पांच-छः स्लाइडिंग जोंस हैं, जिन स्थानों पर यह सम्भावना हैं कि वहां इस बार भी लैंड स्लाडिंग होगी, वहां पर दोनों छोर में अगर एडवांस में ही 15-20 दिनों के लिए मशीन डिप्लॉय कर दें तो पिछले साल जो लोगों को असुविधा हुई, सरकार की किरकिरी हुई उससे इस साल हमें निजात मिलेगी।आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : वैसे तो अभी और भी महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन मणिमहेश यात्रा में अभी काफी समय है और जब भी इस यात्रा का अगाज होता है तो मैं प्रशासन से कहूंगा कि आपको भी उस बैठक में शामिल करें और जो भी सुझाव आपने यहां दिए हैं वहां पर भी दें। सरकार के प्रयास होंगे कि इस बार यात्रा अच्छे प्रकार से हों।

25.03.2026/1220/DT/DC-3

अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी अपना विषय रखेंगे।
श्री केवल सिंह पठानिया इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं।
अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी, अपना विषय रखेंगे। माननीय सदस्य आपके दो विषय हैं लकिन अभी आप केवल अपना एक ही विषय रखें।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय रखने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
यह बहुत ही जरूरी बात है, प्रदेश में जो आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 के संबंध में सर्वे हो रहा है, इसमे जिन लोगों के पास पहले से ही प्रमाण पत्र हैं और जो आई0आर0डी0पी0 में हैं और अगर उनकी वार्षिक आय 50000/- रुपये से कम हो तभी राजस्व विभाग द्वारा उनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है बाकियों को नहीं देते। यदि कोई विडो है, गरीब है या बेरोजगार है उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा
श्री ,एन0जी0 द्वारा जारी...

25.03.2026/1225/डी.सी.-एन.जी./1

श्री जीत राम कटवाल..... जारी

वर्चुअली वही आदमी आई0आर0डी0पी0 के लिए पात्र हो रहे हैं जिनके पहले से बने हुए हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस विषय पर अवश्य गौर करें और आपने प्रमाण पत्र का जो एक फोर्मेट रखा हुआ है कि 50 हज़ार रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले से बी0पी0एल0 या आई0आर0डी0पी0 कैटेगरी में हैं। जो नए आदमी हैं, उनको वह प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है और वे एंटरटेन नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो जायज़ आदमी हैं, वे सर्वे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने निश्चित तौर पर फिर से एक गम्भीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और सरकार इसका आवश्यक तौर पर संज्ञान लेगी। विधान सभा सचिवालय ने भी इसका संज्ञान लिया है और हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य की मंशा के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को भी अवगत करवाएंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य का जो दूसरा विषय है, वह प्रश्न संख्या : 4040 में लिस्टिड था और उसके लिए आप विधान सभा के अन्य नियमों के तहत नोटिस दे सकते हैं। Now Hon'ble Member Shri Kewal Singh Pathaniaji can raise his issue. Since you were absent, again I am giving you chance to speak.

25.03.2026/1225/डी.सी.-एन.जी./2

(माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा शून्य काल के दौरान सिलेंडर की शोर्टेज व बुकिंग के नए-नए नियमों से हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कल मुझे विधान सभा के बाहर एक सुरेन्द्र नाम का लड़का मिला और उसने कहा कि हमारे किचन से सिलेंडर गायब है।

अध्यक्ष महोदय, देखिए, (एक कागज़ दिखाते हुए) इसमें लिखा है कि 'विधान सभा में गैस सिलेंडर खत्तम और 600 लोगों का खाना लकड़ी के ऊपर बनाया, शैफ भी हैरान'। पिछले कल जब मैं मोर्निंग वॉक पर गया तब भी मुझे पांच आदमी इसी प्रकार की बात बोल रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं। पिछले कल मैंने एक प्रैस कॉंफ्रैंस देखी थी। कल दिल्ली के अंदर एक पत्रकार सम्मेलन हुआ और उसमें कहा गया कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। पिछले कल ही एल0पी0जी0 सिलेंडर को बुक करने का नोटिफिकेशन के माध्यम से नया नियम आ गया। यह नोटिफिकेशन केन्द्र सरकार के निर्णय पर इंडियन ऑयल

कॉर्पोरेशन ने की है। इसमें लिखा गया है कि बुकिंग के नियमों में बदलाव किया जाता है। एक ओर तो प्रैस कॉंफ्रैंस में स्टेटमैंट आती है कि कहीं भी कमी नहीं है और दूसरी ओर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बुकिंग नियमों में बदलाव इस प्रकार से किया गया है कि डबल कनैक्शन वाले उपभोक्ता को 35 दिन, सिंगल कनैक्शन वाले उपभोक्ता को 25 दिन और प्रधान मंत्री उज्जवला योजना वाले उपभोक्ता की 45 दिन बाद बुकिंग की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री उज्जवला योजना जोकि गरीब आदमी के लिए है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अमीर आदमियों के लिए 25 व 35 दिन रखे हैं तथा अति निर्धन परिवारों के लिए 45 दिन का बुकिंग टाइम निर्धारित किया है।

25.03.2025/1215/बी.एस./ए.एस.-3

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि यह एक ज्वलंत मुद्दा है। यह समस्या पूरे प्रदेश के अंदर तो है कि बल्कि विधान सभा के अंदर भी यह समस्या उत्पन्न हो रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है और मैं चाहता हूं कि इस पर अवश्य संज्ञान लिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने निश्चित तौर पर एक गम्भीर व महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और माननीय सदस्य ने जो भी रैफरेंसिस दिए हैं, वे सरकार के ध्यान में होंगे तथा सरकार इस पर आवश्यक कदम उठाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय सदस्य की मंशा के अनुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी, उससे आपको व माननीय सदन को अवगत करवा दिया जाएगा।

वैसे तो शून्य काल समाप्त हो गया है लेकिन माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र शौरी हाथ उठा रहे हैं इसलिए वे अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा जो विषय आज नहीं लिए जा सके, वे अगले कार्यदिवस पर टेकअप कर लेंगे।

25.03.2026/1225/डी.सी.-एन.जी./4

(माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र शौरी द्वारा शून्य काल के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, गुशैणी का भवन जोकि भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, उससे हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 01 व 02 सितम्बर, 2025 को भारी बरसात के कारण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, गुशैणी का भवन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पर पहाड़ी दरकी और उस स्कूल का पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पर 472 बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर एक किलोमीटर दूर ही एक भवन किराए पर लिया गया था और अक्तूबर-2025 से लेकर मार्च-2026 तक वे बच्चे किराए के उसी भवन में पढ़ रहे हैं। वह भवन संबंधित मकान मालिक ने निःशुल्क उपलब्ध करवाया था और दिनांक 31-03-2026 तक उसके साथ करार हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर नए भवन के लिए जिस भूमि का चयन किया गया था, उसका पिछले 6-7 माह में एफ0सी0ए0/एफ0आर0ए0 का केस अप्रूव नहीं हो पाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिनांक 31-03-2026 के बाद बच्चे कहां पर पढ़ने जाएंगे? यह बहुत बड़ी समस्या है

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1230/एच0के0/ए0पी0/-01

शून्य काल जारी ..... श्री सुरेन्द्र शौरी जारी ....

लेकिन अब बच्चे 31 मार्च के बाद कहां जाएगें और कहां पर वे अपनी पढ़ाई करेंगे। यह बहुत ज्यादा समस्या का विषय है। लेकिन जो वहां पर मकान मालिक है, उनसे बात करने

के बाद उन्होंने यह कहा है कि वे एक-डेढ़ साल तक ही मकान को किराये पर दे सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस मकान मालिक को उसके मकान का किराया दिया जाए। वहां पर एफ0आर0ए0 जल्दी की जाए ताकि नये भवन का निर्माण किया जा सके।

अध्यक्ष : आपके विषय का विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है और हम चाहेगें कि विभाग इस विषय पर उचित कार्रवाई करें।

शून्य काल समाप्त।

25.03.2026/1230/एच0के0/ए0पी0/-02

अध्यक्ष : अभी बहुत से विषय रह गये हैं, वे विषय कल प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट होंगे। कल जो अन्य विषय शून्य काल में आएंगे, वे उसके बाद लिस्ट होंगे। अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे :-

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1). समिति का **130वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **62वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है;

(2). समिति का **131वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **209वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(3). समिति का **132वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **11वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

25.03.2026/1230/एच0के0/ए0पी0/-03

अध्यक्ष : अब किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का **31वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **सप्तम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **41वाँ मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) पर बने **33वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटिड** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

(1) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा की गई "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है; और

25.03.2026/1230/एच0के0/ए0पी0/-04

(2) समिति का **सप्तम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा की गई "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

25.03.2026/1230/एच0के0/ए0पी0/-05

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर इस माननीय सदन में दिया गया था, उसकी वस्तुस्थिति को वे करेक्ट करवाना चाह रहे है and the authorization is with the Hon'ble Deputy Chief Minister. So, I will request the Hon'ble Deputy Chief Minister कि जो प्रश्न संख्या : 2319 की वस्तुस्थिति के बारे में वक्तव्य दें।

उप-मुख्य मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिनांक 18.03.2026 को दिए गए स्थगित तारांकित प्रश्न क्रमांक 2319 के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जो "संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा विस्तार" से सम्बन्धित था।

सरकार के ध्यान में आया है कि उस उत्तर में श्री युद्धवीर सिंह ठाकुर, ओ0एस0डी0 का नाम गलती से शामिल हो गया। यह गलती अन्य समान प्रश्नों के साथ उत्तर तैयार करते समय हुई है। अभिलेखों की जांच के बाद यह सही स्थिति स्पष्ट हो गई है। सही जानकारी इस वक्तव्य के माध्यम से सदन के रिकॉर्ड में रखी जा रही है, धन्यवाद।

25.03.2026/1230/एच0के0/ए0पी0/-05

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा होगी और आज ही चर्चा का समापन है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी आज ही उत्तर दिया जाएगा। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें और समय अवधि में अपना वक्त्वय समाप्त करने का प्रयास करें। मेरे पास 10 माननीय सदस्यों की सूची प्राप्त हो चुकी है। काँगेस विधायक दल से पांच और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से 5 विधायक इस पर वक्त्वय देंगे। आखिरी स्पीकर श्रीमती रीना कश्यप के रूप में विपक्ष की ओर से थीं। अब मैं माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी से आग्रह करूगां कि वे इस चर्चा में आगे हिस्सा लें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट अनुमान वर्ष 2026-27 के लिए इस माननीय सदन में पेश किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1235/AT/HK/01

राजस्व मंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, हमारा हिमाचल सुंदर भी है और प्यारा भी है। हिमाचल का गठन सन 1948 में हुआ, जब तीस से अधिक पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसे सी-श्रेणी के केंद्र शासित प्रदेश का रूप दिया गया। बाद में इसे 1 नवंबर 1965 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब से लगती पहाड़ी राज्यों को इसमें शामिल करके एक विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। आगे चलकर 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस समय के हमारे प्रथम मुख्य मंत्री डॉ0 यशवंत सिंह परमार के अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला।

आज हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य है। इस राज्य के निर्माण में कांग्रेस की विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एकजुट करने का विचार रखा। उस समय अंग्रेजों के जाने के बाद 600 से अधिक छोटी-बड़ी रियासतें थीं। उन्हें विकल्प दिया गया था कि वे भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या एक स्वतंत्र देश वनाएं। लेकिन पंडित नेहरू और उस समय के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सूझबूझ से इन सभी 600 छोटी-बड़ी रियासतों को भारत में मिलाया गया। कश्मीर, जो अलग रहना चाहता था जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया तब वहां के राजा ने कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल होने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों, जिनकी अपनी-अपनी संस्कृति और भाषाएं थीं उन्हें भी अलग से भारत के संघीय ढांचे में शामिल किया गया और अलग-अलग राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विकसित होने का अवसर मिला। यह सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण संभव हो पाया। हम इन महान नेताओं और उनके विचारों के प्रति कृतज्ञ हैं जिनके कारण आज हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में है।

अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश देश का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसमें केवल 13 प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती है।

25.03.2026/1235/AT/HK/02

(माननीय सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

यदि आगे देखें, तो हिमाचल में लगभग 80 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है। सभापति महोदय हिमाचल में करीब 9 लाख से अधिक लोग खेती और बागवानी से जुड़े हुए हैं और यहां कर्मचारियों की संख्या देखें तो लगभग 2 से 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 1 लाख 30 हजार से अधिक पेंशनर्स हैं। अगर बजट की बात करें, तो लगभग 43 प्रतिशत बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर है। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है वह अपने प्रकार का पहला बजट है जिसमें लंबे समय बाद समाज के उस वर्ग को

प्राथमिकता दी गई है जिसकी संख्या अधिक है और जिनकी ज़रूरतें भी अधिक हैं जैसे किसान, बागवान, मछुआरे, डेयरी फार्मर और भेड़ पालक।

हमारे कुछ साथियों को यह बजट नीरस लग रहा है क्योंकि उन्हें पहले घी और मलाई खाने की आदत थी इसलिए उन्हें इसमें मजा नहीं आ रहा है। सारा बजट किसानों और बागवानों को चला गया इसलिए उनकी सोच के अनुसार यह नीरस लग रहा है। क्योंकि ये मलाई खाने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल की आय मुख्य रूप से कृषि और बागवानी पर निर्भर है। केवल 13 प्रतिशत भूमि पर खेती होती है और उसमें भी 80 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है। हमारे यहां हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं लेकिन उनसे हमें कितना लाभ मिल रहा है

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1240/केएस/वाईके/1

राजस्व मंत्री जारी ---

केवल 12 परसेंट रॉयल्टी, कुछ सालों के बाद 16 परसेंट फिर जा कर कहीं 30 परसेंट मिलती है। उसमें भी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया कि जो हमें 12 परसेंट रॉयल्टी मिलनी थी, जो प्रोजैक्ट्स इन्होंने दिए, उसको स्टैगर करके 4 व 5 परसेंट पर ला दिया तो हमें कहां से इनकम आनी थी?

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

दूसरा, बागवानी और कृषि ही हमारी आय का साधन है। इनमें जो हम जी0एस0टी0 लेते थे, वह भी हमसे केंद्र सरकार छीनकर ले गई। अब हम करे तो क्या करे? अभी जब हमने अपनी आय बढ़ाने की कोशिश की, रिफॉर्मज़ शुरू किए और वे भी इस किस्म के शुरू किए कि जैसे पानी हमारा सोना है, हमने सोने के ऊपर सैस लगाने की बात की तो केंद्र सरकार ने अपने पी0एस0यूज़0 को कोर्ट में भेजकर उसके ऊपर रोक लगवा दी। उसके बाद हमने रेवन्यू सैस लगाने की बात की, उसमें भी केंद्र सरकार के पी0एस0यूज़0 हाईकोर्ट में चले

गए। 16 तारीख के लिए वह केस लटका हुआ है। कहीं उस पर भी रोक ना लग जाए। ये हिमाचल में हमें किसी भी तरह से रिफॉर्मज़ भी नहीं करने देते। ये हमारा गला घोंटना चाहते हैं। जैसे कल कहा गया कि हिमाचल में तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, ये इनके ख्याली पुलाव हैं और ये चाहते भी यही है क्योंकि ये ऑप्रेशन लोटस कर गए। मैं तो सोच रहा था कि ये कभी मानेंगे नहीं परंतु पिछले कुछ दिन पहले सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम आधा सफल हुए। ये मान गए कि इन्होंने अनैतिक काम किया, मान गए कि इन्होंने दल-बदल करवाया, मान गए कि इन्होंने पैसे के दम पर ई0डी0 और सी0बी0आई0 के नाम पर 9 विधायकों को इस पार से उस पार लगा दिया। ये खुद मान गए। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब ये खुद मान गए और फिर ये अलग-अलग बात करते हैं। यहां पर पानी और जमीन के ऊपर भी ये हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। यहां पर सैस की बात हो रही है। सैस हर सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार कितने सैस लगा रही है? इन सैस पर 8 से 9 लाख रुपये से ज्यादा ये कमा रहे हैं जो हमारे साथ शेयर नहीं करते, वह सारा का सारा पैसा पता नहीं ये लोग कहां डाल देते हैं? ...(व्यवधान)

25.03.2025/1240/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष महोदय, ये हमें ना पानी में और ना ही हवा में जीने दे रहे हैं। रिफॉर्मज़ के लिए हम इस माननीय सदन में बहुत सारे बिल ले कर आते हैं और उनके ऊपर विचार-विमर्श करके पास करके भेजते हैं। ऐसे बिल हैं, ऐसे-ऐसे प्रस्ताव गवर्नर को जाते हैं कि अगर उनके ऊपर तुरंत फैसला लिया जाता तो हमारी इकोनॉमी और हमारी इनकम में बढ़ौत्तरी होनी थी। परंतु यहां पर क्या है कि गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। जाते-जाते बड़ी नसीहत देते हैं। मैं अगर उनकी नसीहत की बात करुं, जो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल-स्पिति, पांगी और भरमौर आदि हैं, उनके लिए जमीन देने के लिए नौतोड़ के नियम बने हैं परंतु वर्ष 1980 का जो फोरैस्ट कंज़र्वेशन एक्ट है, उसके रहते हुए यह सम्भव नहीं है और उसके लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अनुच्छेद-5 के तहत सरकार के प्रस्ताव पर जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रस्ताव पर माननीय गवर्नर महोदय जो जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षक होते हैं,उनको इतनी शक्तियां दी गई हैं कि विधान सभा या पार्लियामेंट के जो कानून बने हैं, उनमें संशोधन

करने की भी उनको शक्तियां दी गई हैं, ससपेंड करने की भी शक्तियां दी गई हैं। इससे पूर्व के राज्यपालों ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में डवलपमैंट और नौतोड़ में जमीन देने के लिए इस प्रावधान का निर्वहन किया। उसका वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनको जमीन मिलनी शुरू हुई परंतु वर्तमान गवर्नर जिनका लगभग 3 साल का कार्यकाल रहा,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1245/av/yk/1

राजस्व मंत्री---- जारी

हमारी कैबिनेट ने उनको प्रस्ताव भेजा और उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद् से भी प्रस्ताव गया। तीन वर्ष का समय बीत गया, उसी बात को लेकर 8 बार तो मैं खुद राज्यपाल महोदय के पास गया जिसमें एक-आध बार मेरे साथ यहां पर बैठी माननीय सदस्या लाहौल-स्पिति और भरमौर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी गए। उसके बाद मैं जनजातीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों को लेकर गया। मैं अंतिम बार दिनांक 1 जनवरी, 2026 को गया, वहां पर उस समय माननीय मुख्य मंत्री भी नये वर्ष की शुभ-कामनाएं देने गए थे। मैं उस दिन फिर से वही प्रस्ताव लेकर गया था और मैंने वहां पर फोटो भी खिंचवाया तथा राज्यपाल महोदये से निवेदन भी किया कि अब तो बहुत हो गया, अब तो कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हो जाएगा। लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद जब माह जनवरी और फरवरी भी निकल गए तो मैंने फिर सोचा की अंतिम बार फिर से राज्यपाल महोदय से मिलने की कोशिश करता हूं। मैंने फिर से उनसे एक बार दोबारा से गुहार लगाई परंतु राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा कि आपको 9 मार्च के बाद समय मिलेगा। लेकिन वे 8 मार्च को ही रवाना हो गए। अब आप खुद ही बताइए कि यह बिल तीन वर्षों से पैंडिंग पड़ा रहा और प्रस्ताव भी पैंडिंग पड़े रहे। उनके लिए जो उन्होंने संवैधानिक तरीके से परमिशन देनी थी, अगर वह दी होती तो तीन वर्षों में मेरे जनजातीय क्षेत्रों में हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कान होनी थी क्योंकि उस जमीन पर वे लोग सेब या कोई और

फलदार पौधे लगाते तो वे मालामाल होते। यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं कि राज्यपाल महोदय को यह शक्तियां हैं या वह शक्तियां हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल संविधान से ऊपर हो सकता है? हम सभी संविधान के अधीन हैं। हम चाहे किसी भी पद पर बैठे हों परंतु संविधान हमेशा ऊपर होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां पर सीधी और स्पष्ट बात करने आया हूं। यह लड़ाई संविधान और मनमानी के बीच की लड़ाई है और यह बात राज्यपाल महोदय और केंद्र सरकार दोनों पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार राज्यपाल की शक्तियों की सीमा तय की है और स्पष्ट किया है कि कोई भी संवैधानिक पद संविधान से ऊपर

25.03.2026/1245/av/yk/2

नहीं हो सकता। यह शमशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं जो अपने कार्य मंत्री परिषद् की सलाह और सहायता पर करते हैं। व्यक्तिगत विवेक का दायरा बहुत सीमित है और इसका बहाना बनाकर शासन चलाना संविधान के विपरीत है। यह राज्यपाल महोदय के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, State of Punjab Vs. Principal Secretary to the Governor में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक लम्बित नहीं रख सकता। उसे या तो उचित समय में मंजूरी देनी होगी या पुनर्विचार के लिए वापिस भेजना होगा। पॉकैट विटो जैसी स्थिति संविधान की भावनाओं के विपरीत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेटेस्ट तमिलनाडु का एक केस गया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इतने महीने के अंदर राज्यपाल या राष्ट्रपति बिल को पास नहीं करते तो deem to be consented समझा जाएगा। परंतु उसका बाद में प्रेजिडेंशियल रेफ्रेंस दिया, उसमें उसका टाइम नहीं दिया परंतु उनको कहा कि उचित समय में करना चाहिए। इसलिए यह राज्यपाल की मर्जी नहीं है कि वह अपनी मनमानी करें और विधान सभा के बिल्ज के ऊपर वे कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते।

अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत सीधा है। जनता ने सरकार चुनी है, किसी और ने नहीं और जनादेश से बड़ा कोई और आदेश नहीं। संविधान सर्वोपरि है और मनमानी खत्म होगी; वह चाहे केंद्र की हो या राज्यपाल की हो।

अध्यक्ष : (***) शब्द की जगह मनमानी शब्द का प्रयोग किया जाए। ...(व्यवधान) इसको अभी विपक्ष की ओर से प्वाइंट आउट किया जाएगा तो मैंने इसको खुद ही ठीक कर दिया।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर चुनी हुई सरकार के फैसले रोके जाएंगे और बिल्ज को रोक जाएगा या लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा तो इस सदन में से एक ही आवाज उठेगी कि लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं। संविधान के खिलाफ एक कदम भी नहीं। राज्यपाल नहीं, संविधान चलेगा केंद्र सरकार नहीं चलेगा। यह देश किसी पद की ताकत से नहीं बल्कि संविधान और जनता की ताकत से चलता है।

टी सी द्वारा जारी...

25.03.2026/1250/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

राजस्व मंत्री .... जारी

अध्यक्ष महोदय, यह देश किसी पद की ताकत से नहीं, बल्कि संविधान और जनता की ताकत से चलता है। संविधान के सामने हर शक्ति झुकेगी और लोकतंत्र की आवाज हर हाल में जीतेगी, यही मैं कहना चाहता हूं।

केंद्र सरकार से हमें आर0डी0जी0 के तहत पैसा आना चाहिए था, बहुत सारे साथी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यह दिया, वह दिया, फलाना दिया और हमें केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आप किस व्यवस्था में रह रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान है, वह एक संघीय ढांचा है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं। ये सोच कि वन नेशन, वन इलेक्शन या वन नेशन वन सिस्टम हो जाएगा, यह संभव नहीं है। जब तक संविधान है जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं तब तक इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे और जो यह कहते हैं कि खैरात मिल रही है, वह गलत है। केंद्र सरकार और हमारा संघीय

ढांचा है, हमारा कोपरेटिव फेडरलिज्म है, इसमें एक सत्ता दिल्ली में है और एक सत्ता राज्यों में है। जब राज्यों की संरचना की गई थी तो संविधानदाताओं को यह ज्ञान था कि भविष्य में कुछ ऐसे भी स्टेट्स होंगे जो आर्थिक रूप से वायबल नहीं होंगे उनके लिए अनुच्छेद 275 का प्रावधान किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमिशन इस पर फैसला करते हैं, परंतु 16वां फाइनेंस कमिशन केन्द्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दो लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है उनके पास इसके बारे में कोई ठोस तर्क नहीं है। जब हमारा बजट डेफिसिट पर है, जब तक हम बराबर नहीं होंगे, यह केंद्र का दायित्व है कि हमें आर0डी0जी0 मिलती रहे लेकिन 16वें वित्तायोग और केंद्र सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। ये कम-से-कम तर्क तो देते । क्या हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टे हो गया है? 13वें, 14वें और 15वें वित्तायोग ने स्वयं इस बात को माना कि हिमाचल को आर0डी0जी0 की जरूरत है। किसी और प्रदेश को इसकी जरूरत हो या ना हो लेकिन हिमाचल को तो इसकी जरूरत है। आज इस सदन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हिमाचल को आर0डी0जी0 मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप (विपक्ष) चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप हिमाचल विरोधी हैं। इनके चुप रहने से यह साफ हो गया है कि ये हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से उन्नत नहीं देखना चाहते। आप बहुत सारी बातें

करते हैं लेकिन स्पष्ट कहिए कि मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप हां या न में बोलें ।

अध्यक्ष महोदय, इनके मुंह में ताले लग गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश हितैषी हो ही नहीं सकते। ये हिमाचल के साथ तब भी खड़े नहीं हुए जब हिमाचल में स्टेटहुड की बात हुई थी। इस विचारधारा के लोगों ने इसी सदन में कहा था कि स्टेटहुड को मारो ठुड। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई। ...(व्यवधान)

Speaker: Order in the House, please. प्लीज बैठे-बैठे ना बोलें। This is a part of record. Rakesh Jamwal ji, this is a part record. You go through the 1962 debate of the Vidhan Sabha.

राजस्व मंत्री : सर, ये हिमाचल विरोधी ही नहीं है, ये हिमाचल (***) है जैसे देश (***) होते हैं, ये हिमाचल (***) हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह आपको (विपक्ष) बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला गया। प्रधान मंत्री जी के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है अगर कोई रेफरेंस होगा तो वह रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। ...(व्यवधान) ओपोजिशन को बोला जा सकता है । ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. No reference of the Hon'ble Prime Minister has come. If there will be any reference with regard to the Hon'ble Prime Minister, that will not form part of the record. ...(Interruption) Please take your seats now. विपक्ष का आ रेफरेंस आ सकता है। ...(व्यवधान) I agree with you. विपक्ष का आ रेफरेंस आ सकता है। ...(Interruption)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

25-3-2026/1255/NS-AG/1

(**व्यवधान**)...

Speaker: Please take your seats. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : कहां बोला मैंने प्रधानमंत्री, आप झूठ क्यों बोलते हो? कहां बोला, कहां बोला?

Speaker: Please take your seats. …(Interruption)

राजस्व मंत्री : सर, ये झूठ बोल रहे हैं मैंने प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया। …(व्यवधान) नहीं बोला। सर, ये झूठ बोल रहे हैं,मैंने प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया।

Speaker: I am very carefully listening to each and every word of all the Hon'ble MLAs. …(Interruption) …. Please, please. Nothing is going on record. This is undesirable. This is not required. This is undesirable. I will now allow it to happen. …(Interruption) आपके भी जब माननीय सदस्य बोलेंगे तो वे इन सारे शब्दों का जवाब भी दे सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी बोलेंगे और ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठ जाइए, प्लीज। जो पहली या दूसरी दफा जीत कर आए हैं वे बैठ जाएं। अभी श्री सतपाल सिंह सत्ती जी जवाब देंगे, you please cooperate with me because Satti ji has requested me क्योंकि उन्होंने कहीं जाना है इसलिए I may extend the House for half an hour. Please take your seats. …(Interruption) राजस्व मंत्री को अपना भाषण खत्म करने दें और उसके बाद श्री सतपाल सिंह सत्ती जी बोलेंगे। …(Interruption)

राजस्व मंत्री : शर्म करो, मैंने नाम ही नहीं लिया।

Speaker: (***) will not be a part of the record. …(व्यवधान) ऐसा कुछ नहीं बोला है I Please take your seats. …(Interruption) Please take your seats. राजस्व मंत्री जी, आप बोलिए I Please cooperate with me.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया। मैंने इनको हिमाचल (***) कहा है। मैंने कहा जैसे (***) हैं ये हिमाचल (***) हैं। …(व्यवधान) ये क्यों गलत है? क्या कोई आपकी मर्जी से आएगा? …(व्यवधान)

25-3-2026/1255/NS-AG/2

अध्यक्ष : ये तो बोल सकते हैं, अब आप भी बोलो। ...(Interruption) Please take your seats. यह बोला जा सकता है। यह संसदीय शब्द है। (***) कोई असंसदीय शब्द नहीं है। ...(Interruption) This is parliamentary.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं (***) को छोड़ कर विद्रोही बोलता हूं। अब विद्रोही बोल दिया। ...(Interruption)

Speaker: Please take your seats. Please cooperate with me नहीं तो मुझे हाउस एडजोर्न करना पड़ेगा। Please cooperate with me. राकेश जी बैठ जाएं । मैं देख रहा हूं whatever undesirable words will be removed from the record. Please take your seats. सत्ती जी ने बोलना है इसलिए I am cooperating with you. Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seat, Satti ji. ठाकुर साहब, बैठ जाओ, ये बोल देंगे जो कुछ बोलना है। हां, हम वे सारा निकाल देंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह शब्द मैंने खुद वापिस ले लिया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?

अध्यक्ष : हां, आपने वापिस ले लिया है। नेगी जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान) Order in the House, please. Please listen to the Hon'ble Minister. बजट में ऐसे रेफरेंसिज आते हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि

शीशे पर पारा चढ़ जाए तो आईना बनता है,

और इनको आईना दिखाओ तो इनका पारा चढ़ जाता है।

...(व्यवधान)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

25-3-2026/1255/NS-AG/3

अध्यक्ष : राकेश जी, प्लीज बोलने दें। ...(व्यवधान) सुनो, प्लीज।

राजस्व मंत्री : मैं उसके बारे में भी आईने में बताता हूंः

हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे,

फिक्र वे करें जिनकी शक्ल में कुछ

और दिल में कुछ और है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज-प्लीज इनको बोलने दें। Please, please. Negi ji, please. I may inform the Hon'ble House because the law students from the H.P. University are witnessing your proceedings, so please be in order in the House so that they take a proper message from the House.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत में संघीय ढांचे फैडरल स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से केंद्र के बढ़ते वर्चस्व, राज्यपालों की भूमिका, वित्तीय असंतुलन, जी0एस0टी0 मुद्दे, केंद्रीय एजेंसियों ई0डी0, सी0बी0आई0 के बढ़ते हस्तक्षेप और क्षेत्रीय बादशाही विवादों से खतरा है। ये चुनौतियां सहकारी संघवाद को कमजोर करती हैं जिससे राज्य अपनी स्वायतता को खो रहे हैं। यह सबसे बड़ी खतरनाक बात है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि अगर इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना है

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

राजस्व मंत्री ....जारी

कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को एक रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और यहां भाजपा की तो क्या आप आर0डी0जी0 की मांग नहीं करते? ये आर0डी0जी0 के ऊपर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इनकी विचारधारा की सरकार है। यहां दो किस्म की बातें नहीं चलेंगी। आप blow hot-blow cold वाली बात नहीं कर सकते। आपको इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई तब भी आपने हमारा साथ नहीं दिया। हिमाचल में बिना वर्दी के दिल्ली पुलिस प्रवेश कर गई और यहां से हमारे नौजवानों को उठाकर ले गई लेकिन तब भी आपने हमारा साथ नहीं दिया। ...(व्यवधान) सर, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना है। अगर कोई वारंट लेकर आता है तो पहले थाने में जाकर बताना पड़ता है। पिछली बार सी0आर0पी0एफ0 वाले नौ लोगों को पकड़ कर अपने साथ ले गए और उन्होंने हमारे विधान सभा का गेट भी तोड़ दिया। यह आप क्या करने जा रहे हैं? आप किस किस्म की व्यवस्था करने जा रहे हैं? आपके जो 9 लोग यहां से भाग गए थे उनके घरों में सी0आर0पी0एफ0 के लोग एक साल से पहरा दे रहे हैं। इन लोगों को हमसे क्या खतरा है? इन्हें खतरा तो आप लोगों से होना चाहिए क्योंकि आपने उन्हें जो कुछ दिया होगा उसके बदले में वे कहीं उल्टा न बोल दें इसलिए उन्हें पकड़ कर रखा है। आपने उन लोगों को कैद करके रखा है। हमें जो जी0एस0टी0 मिलता था वह अब केंद्र सरकार के पास जाता है लेकिन उसका पूरा शेयर हमें नहीं मिल रहा है। आपने जो दिल्ली और राज्यों के बीच जी0एस0टी0 बांटने का फॉर्मूला बनाया है उसे आपको बदलना होगा। उसमें जो पॉपुलेशन और एरिया फैक्टर को रखा गया है उस हिसाब से हिमाचल बहुत पीछे चला जाएगा। क्या इसमें हिमाचल प्रदेश की गलती है कि हमने कम बच्चे पैदा किए? क्या यह हमारी गलती है कि हमने जंगल नहीं काटे इसलिए हमें सेंटर शेयर का पैसा कम मिलेगा। यह फॉर्मूला गलत है और इस फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है अन्यथा जो हमारा देश कश्मीर से

कन्याकुमारी तक एक है वह दोबारा से छिन्न-भिन्न हो जाएगा। आप जो वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं, वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि

25.03.2026/1300/RKS/As-2

हिमाचल प्रदेश को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, जिनका सीना 56 इंच का नहीं था, उनका छोटा-सा सीना था और उसमें उन्होंने खड़े होकर तीन-तीन गोलियां खाईं। वह महापुरुष महात्मा गांधी जी थे। अगर महात्मा गांधी जी न होते तो शायद आज हम आजाद नहीं होते। महात्मा गांधी जी के नाम से जो 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना' थी उसे खत्म कर दिया गया। इसकी जगह ये ऐसी स्कीम लेकर आ गए जिसमें जबरदस्ती 'राम' शब्द को जोड़ा गया। हम राम के खिलाफ नहीं हैं। अगर आपने इस योजना को लाना ही था तो राम के नाम से लाते। परंतु आपने अंग्रेजी और हिन्दी के शब्दों की जुगलबंदी करके जबरदस्ती 'राम' शब्द को बीच में घुसेड़ दिया। यह आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप महात्मा गांधी के देश के प्रति योगदान को कम करके राम को ऊपर करेंगे? इन्होंने इस योजना का नाम VB-G RAM G रख दिया। वैसे तो ये अंग्रेजी से नफरत करते हैं लेकिन इनके सारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस विचारधारा के लोगों के बच्चे इंग्लैंड और यू0एस0ए0 में पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए जबकि इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने पहली कक्षा से अंग्रेजी को शुरू किया है। इन्होंने 'VB' यानी विकसित भारत के बाद डैश लगा दिया। क्या शब्दों में ऐसा कभी होता है? इस एक्ट में डैश लगा हुआ है यानी आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। उसके बाद 'G' आएगा और फिर बीच में थोड़ी जगह छोड़ने के बाद 'RAM' आएगा क्योंकि इन्होंने कहीं-न-कहीं 'राम' शब्द को जोड़ना था। अंत में थोड़ा पॉज़ करके 'G' शब्द लिखा गया है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1305/बी.एस./ए.एस.-1

राजस्व मंत्री जारी...

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, अंग्रेजी शब्द आ गया। अब अंग्रेजी के तो आप दुश्मन हो, फिर क्या कहा गया, गारंटी फॉर रोजगार फिर एण्ड आजीविका मिशन लगा दिया। आप बताइए कि रोजगार और आजीविका में क्या फर्क है? इनके दिमाग में तो कुछ डाल दिया गया है ये अंध भक्त हो गए हैं। इन्होंने कर दिया आजीविका मिशन, फिर उसमें बीच में ग्रामीण डाल दिया, तब जाकर बना। मेरे हिसाब से अगर इसको आप पढ़ेंगे तो वी0बी0 तो ठीक है, उसके आगे जी, आर, ए, एम, जी है। तो यह गरम जी बन रहा है। इसे "गरम जी" बनाना पड़ेगा। इन्होंने राम जी को गरम जी बना दिया। सर, ये कर क्या रहे हैं? "महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना" वर्ष 2005, उस शख्सियत की सोच थी जो बोलते कम थे, मन की बात भी नहीं करते थे और काम की बात करते थे। वे थे स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी और आज उन्होंने महात्मा गांधी को नीचे करने के लिए और बना दिया और "मनरेगा" खत्म। आज आप 125 दिन की बात करते हैं, हम 150 दिन का रोजगार देते थे, रोजगार की गारंटी हम देते थे। जिसको काम चाहिए वह जाकर वहां काम कर लेता था।

आज केंद्र सरकार ने इसमें सारी पावर अपने पास ले ली है। दिल्ली में बैठकर यह डिसाइड करेंगे कि कितने दिन साल में काम मिलेगा। यह डिसाइड करेंगे कि कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करनेहैं? इस देश में क्या हो रहा है? इस तरह तो यह देश एक रहने वाला नहीं है। इससे भविष्य में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है ...(घंटी)... सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सर, गांधी जी को क्यों याद करते हैं? (***)...(व्यवधान) गांधी जी को इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने राजनीति को सेवा और नैतिकता से जोड़ा। आज जब राजनीति पर कई सवाल उठते हैं, ...(व्यवधान)...तब गांधी जी का संदेश समाज को जोड़ने का काम करता है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : (***)। ...(Interruption) This is also a part of the Budget.

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

25.03.2025/1305/बी.एस./ए.एस.-2

राजस्व मंत्री : उन्होंने हमेशा कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और यही विचार हमें आगे ले जाएगा। गांधी जी केवल इतिहास नहीं हैं, वे भारत की आत्मा हैं। उन्हें इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही एक मजबूत समरस और एकजुट भारत का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी का विचार अमर है और जब तक भारत है तब तक गांधी जी का नाम और उनका मार्ग हमें प्रेरित करता रहेगा।

अध्यक्ष : यह मोहनदास करमचंद गांधी जी का जिक्र है, आदरणीय इन्द्र सिंह गांधी जी का जिक्र नहीं है, आप समझ रहे हैं कि आपका जिक्र हो रहा है भाई, आपका नहीं है।

राजस्व मंत्री : सर, अभी यहां पर ड्रेस कोड की बात हो रही थी। महात्मा गांधी जी वह महापुरुष थे, जो धोती और एक कपड़ा पहनकर चप्पल में रहते थे। इनसे कुछ सीखिए, कुछ शर्म कीजिए, उन लोगों का सम्मान कीजिए जिन्होंने आपको आजाद कराया। आपको शर्म नहीं है। आप अंध भक्त हो चुके हो आपकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। सर, ये इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में गए। उस समय इंग्लैंड की महारानी के राज में सूरज नहीं डूबता था और जब ये वहां गए तो इन्हीं कपड़ों को पहन कर गए। वह चाहते तो सूट-बूट पहनकर और टाई लगाकर जा सकते थे। उन्होंने लंदन से बैरिस्टरी की थी। परंतु उन्होंने अपना सूट-बूट इस देश की आजादी और गरीब जनता के लिए त्याग दिया और हिम्मत देखिए कि महारानी के सामने भी उसी सादगी में जाकर एक संदेश दिया दुनिया को कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। आज देश के प्रधान मंत्री की बात करें। ...(व्यवधान)...

Speaker : Please maintain Order in the House. These are the very important references which have been made by the Hon'ble Revenue Minister because

this House has witnessed the Vithalbhai Patel, Mahatma Gandhi, Moti Lal Nehru & Pandit Jawahar Lal Nehru's speeches here in this House.

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1310/DT/DC-1

राजस्व मंत्रीः सर, आपने सही फरमाया कि इसी माननीय सदन में स्वर्गीय श्री मोती लाल नेहरू ने सन् 1925 में इसी काउंसिल चैम्बर में पहली बार महिलाओं को वोट देने के अधिकार की बात की थी। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि जब ये महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के लिए हल्के शब्दों में बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि इनकी सोच कहां से कहां पहुंच गई? यह विचारधारा आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाली है। यहां पर जो महात्मा गांधी के बारे में बात की गई मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आज मनरेगा योजना भी हमारे बजट का भाग है। पहले मनरेगा योजना सौ प्रतिशत सेंट्रल फंडिड थी लेकिन अब इन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 90:10 के अनुपात में राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार इस तरह से भी हमें तंग कर रही है। केंद्र सरकार हमारा सारा बजट अपने पास रख रही है फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? केंद्र सरकार ने हमारी आर0डी0जी0 बंद कर दी। फिर ये कहते हैं कि केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा में भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। फिर हम किस चीज का धन्यवाद करें? हमने पानी और जमीन पर जो सैस लगाया था उसे भी केंद्र सरकार ने रोक दिया है। क्या हम इनका इसलिए धन्यवाद करें कि इन्होंने हमें 15-15 लाख और दो करोड़ नौकरियां प्रदेश के लोगों को दे दी हैं? आज 400 का गैस सिलेंडर 1200 रुपये से ऊपर मिल रहा है और वह भी 45 दिन के बाद मिलेगा। क्या हम इन चीजों के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करें? पेट्रोल पहले 55 रुपये था और अब इसकी कीमत 100 रुपये हो गई है क्या इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। हम इनका धन्यवाद किस चीज का करें? जब डॉलर ऊपर जाता है तो रुपये की कीमत नीचे गिर जाती है। हमारे समय एक डॉलर की कीमत 55 रुपये थी परंतु अब 95 रुपये हो गई है। फिर हम इनका धन्यवाद किस चीज का करें? इन्होंने जो देश में हिन्दू-मुसलमान करके दंगे-फसाद करवाए क्या उसके लिए हम इनका धन्यवाद करें? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी आप इन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें, उसके बाद मैं आपको अलाउ करुंगा। वे अपनी बात शेयर के साथ समाप्त करना चाह रहे हैं।...(व्यवधान)

25.03.2026/1310/DT/DC-2

राजस्व मंत्री : सर, मुझे एक चीज और कहनी है। मैं यह बात नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना चाहता हूं। श्री जय राम ठाकुर जी बजट में चर्चा करते हुए एक बात कह रहे थे लेकिन उस बात पर इनको किसी ने नहीं टोका। ...(व्यवधान) मेरे पास इनका पूरा भाषण है। अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि 'मुख्य मंत्री जी चले जाते हैं, कभी रुक भी लिया करो। इनका दिल तो खास तौर पर अध्यक्ष महोदय के साथ लगा हुआ है। बजट के समय नदौन और देहरा ही चलता रहा। ये बीच में डिस्टरबेंस के लिए कह रहे थे कि I am not yielding.' 'ये कह रहे थे कि जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में कोई न बोलें। ये कह रहे हैं कि जब मुख्य मंत्री ने जवाब देना हो तब बोलें या मेरे वक्तव्य के बाद बोलें। यह इन्हीं के शब्द हैं। आप कह रहे थे कि I am not yielding, I am not yielding'. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं यील्ड कर रहा हूं। आप मुझे बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। रूल 299 मेरे पास पड़ा है। मैं श्री जय राम ठाकुर जी को रूल-299 की कॉपी भेज देता हूं, आप इस रूल को पढ़ लेना। इसके बाद इनका पारा भी कम चढ़ेगा और यह इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगाः-

दुनिया के सारे पैमाने बदल जाते हैं,
जब बात खुद के हक में नहीं होती।

यही हाल श्री जय राम ठाकुर और इनकी पार्टी के सभी सदस्यों का है। ये मनचाहा बोलते हैं। अगर इनको मनचाह बोलना हो तो अनचाह सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.03.2026/1315/डी.सी.-एन.जी./1

राजस्व मंत्री..... जारी

हम तो इनको डिस्टर्ब करते नहीं हैं।...(व्यवधान) ये इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नियम-299 को स्ट्रीक्ली लागू कीजिए। अगर स्ट्रीक्ली लागू करेंगे तो इनकी (***) हो जाएगी।

अध्यक्ष : यह (***) शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों के ऊपर हनन कर रहे हैं। ये सबसे आफत की बात है। वैसे कुछ अगली बार के लिए भी रख लेते हैं। मैं एक बात पूछता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी इतना बड़ा बस्ता लेकर आए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या उठा के लाए हैं लेकिन जब ये बोलने लगे तो वर्ष 2010 से शुरू हो गए कि बजट का ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, फलाँ होना चाहिए था या ढ़िमका होना चाहिए था। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जब आप 5 साल सत्ता में थे, तब आपको 86,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिला, वह कहां डाल दिया? क्या आपने घी पीने में लगा दिया? क्या आपने उसे लंच मंच (जन मंच कार्यक्रम के लिए उपयोग किया) में डाल दिया? आपने जो पद यात्राएं की थीं, क्या उनमें डाल दिया? आप कहते थे कि अमृत काल है, अमृत काल कैसे हो गया? जल शक्ति विभाग की योजना के तहत रेस्ट हाउस व इंस्पेक्शन हट बनाए जाते हैं और इन्होंने जो रेस्ट हाउसिस बनाए गए, वे तो आपने महल बना दिए। एक जगह पर तीन-तीन मंज़िल, 18-18 कमरे और बड़े-बड़े हॉल बना दिए। क्या वे इंस्पेक्शन हट थे? क्या जल शक्ति विभाग वाले इतने बड़े महल में इंस्पेक्शन करते हैं?...(घण्टी)... इन्होंने इस प्रकार से सारा पैसा लुटा दिया। इनके पास इतना बड़ा मौका था क्योंकि डबल इंजन की सरकार

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

25.03.2026/1315/डी.सी.-एन.जी./2

थी और केन्द्र सरकार से भरपूर पैसा भी मिल रहा था, ये लोन भी बेहिसाब ले रहे थे, तो ये हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते थे। लेकिन इनकी सोच केवल मिशन रिपीट की थी और ये बाकी सब कुछ भूल गए थे। हिमाचल को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाना है या स्वावलम्बन बनाना है, यह तो इनकी सोच ही नहीं थी। इनकी सोच केवल इतनी थी कि 5 साल का सत्ता सुख मिल गया और 5 साल मिशन रिपीट हो जाएगा। हम रिवाज बदलेंगे, फलां करेंगे और ये उसी पर सारा धन लुटाते रहे। इनके कारण आज ये परिस्थिति खड़ी हुई है कि हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं खासकर नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि :-

तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा?

मुझे रहजनों से गिला तो है, मुझे चोर-लुटेरों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी पर सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, ये तो चौकीदार थे और क्या करते रहते हैं? इन्होंने प्रदेश का पैसा कैसे लूटा दिया? मैं इनसे यह सब पूछना चाहता हूं। मैं अन्य सदस्यों का टाइम न लेते हुए इतना कह सकता हूं कि यह बजट एक दूरदर्शी बजट है। हिमाचल को स्वावलंबन बनाने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से कमजोर वर्ग को पहली बार मौका दिया गया है। किसान, बागवान, मछुआरे, भेड़पालक आदि सभी का कल्याण इस बजट में हो रहा है। साथ में एम्प्लॉइज़ का भी कल्याण हो रहा है। सभी कर्मचारियों/अधिकारियों ने सैलरी के डिफरमैंट में जो सहयोग किया है, उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। एक चीज़ रह गई है कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का Happiest State है। पिछले तीन सान से नम्बर एक के स्थान पर है। भारत देश Happiness Index Graph में 121वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश में सब हैप्पी हैं—सिर्फ श्री जय राम ठाकुर जी के साथी हैप्पी नहीं हैं। ये लोग हैप्पी हो भी नहीं

सकते और उसका कारण आप हर रोज देख ही रहे हैं। मैं अंत में बस इतना कहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच हैः-

25.03.2026/1315/डी.सी.-एन.जी./3

हम तो वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं,

हम तो वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं,

शेर की तरह जीने का शौक है हमें, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

25.03.2026/1315/डी.सी.-एन.जी./4

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक शेर सुनाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी, केवल शेर ही सुनाना, नहीं तो माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती का समय 2 बजे के लिए चला जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय राजस्व मंत्री ने बहुत पुरानी-पुरानी शायरी सुनाई है।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, स्वर्गीय श्री सत महाजन जी इस शेर को लगातार पढ़ते थे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूंः-

मेरे हालात पर न कर मेरे किरदार का फैसला,

मेरे हालात पर न कर मेरे किरदार का फैसला,

तेरा वजूद मिट जाएगा, मुझे मिटाते-मिटाते।

अध्यक्ष : अच्छा शेर था। अब मैं माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती से आग्रह करूंगा की वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले की मैं दोपहर के भोजन के लिए सदन की बैठक को स्थगित करूं, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपना वक्तव्य 15-20 मिनट में समाप्त कर दें। माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती ने मुझ से आग्रह किया था कि इन्होंने 2:00 बजे कहीं जाना है इसलिए इनका वक्तव्य दोपहर के भोजन से पहले करवा दिया जाए और मैं इनके आग्रह पर थोड़ी देर बाद बैठक को स्थगित करूंगा।

श्री सतपाल सिंह सत्ती.....श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1320/एच0के0/ए0पी0/-01

श्री सत्तपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 21 मार्च, 2026 को बजट पेश किया था। उसके ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बजट के ऊपर अपना विषय रखा, अपने विचार रखे कि बजट में क्या खामियां हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने, माननीय मंत्रियों ने उस बजट पर अपने विचार रखे और बजट की विशेषताएं को बताया है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस समय आदमी बजट पर ऊपर बोलता है। अभी प्रदेश के माननीय राजस्व मंत्री बोले रहे थे। उनके द्वारा इस बजट अभिभाषण की शुरूआत पचास-सौ साल पुराने समय से शुरू की गई। उन्होंने बजट बुक पर बात शुरू नहीं की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट में उन्होंने जो भी पढ़ा है वह शायद बोलने के लायक नहीं था। इसलिए वह इतिहास की बाते करने लगे। देश में आजादी की बात करने लगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और यह मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। हर व्यक्ति की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं। हर व्यक्ति के अलग-अलग माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बातें की हैं वो शायद ऐसी बातें हैं जैसे कि वे रिकोंग पिओ के चौक पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हो। उनको ऐसा लगा जैसे वोट की कोई रैली चल रही है। माननीय मंत्री जी पढ़े-लिखे आदमी है, वकील है और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। मुझे

बार-बार हैरानी होती है कि विपक्ष के नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर जी उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं और अभी इनके थोड़े से रिलेशन ठीक भी हुए थे। एक दूसरे के लिए फूलों का गुलदस्ता भी लेकर के गए थे। हमें लगा कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी पर ही वह बार-बार बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक मंत्री को तथ्यों पर आधारित बातचीत करनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें लगभग 136 पेज का हिंदी संस्करण में है और इंग्लिश वाला छोटा है। उसके ऊपर बहुत-सी बातें बोलने की हो सकती हैं।

25.03.2026/1320/एच0के0/ए0पी0/-02

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह रहेगा कि वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, उसके अंदर जो खामियां हैं उसमें विपक्ष का काम यही है कि उसके बारे में हम लोगों को सदन के माध्यम से अवगत करवाएं। इसलिए विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है। जो लोकतंत्र प्रिय लोग हैं और जो लोकतंत्र को मानते हैं, वे ऐसा कहते हैं। माननीय नेगी जी ने विषय आज़ादी का रखा। अब मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। मेरा इरादा था कि 10-15 मिनट बोलकर चला जाउं। अभी भी इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा श्री जगत सिंह नेगी जी आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसमें कोई दोहराय नहीं है कि महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में थे, उस समय उन्होंने आज़ादी का प्रण लिया था। क्योंकि उनको वहां एक ट्रेन से निकाल दिया गया था। जब महात्मा गांधी जी वहां पर बैरिस्टर का काम करते थे। उनको ट्रेन के डिब्बे में से निकाल दिया गया था क्योंकि भारतीयों और कुत्तों को ट्रेन के डिब्बे में चढ़ना अलाउड नहीं था। इसलिए आप नीचे उतरो, ऐसा मैंने जो पढ़ा है।

अध्यक्ष : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को धक्के मारकर गिरा दिया था।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, हां, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। उसी समय महात्मा गांधी जी ने निर्णय लिया था कि जब तक इन अंग्रेजों को मैं भारत से निकाल नहीं देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, मैं एडवोकेट नहीं बनूंगा, मैं बैरिस्टर का काम नहीं करूंगा। उसके बाद वह भारत लौट आए। महात्मा जी ने वहां से यह विषय उठाया

और उनके साथ-साथ, जैसे कहते हैं, कारवां बढ़ता गया, हिंदुस्तान बसता गया, ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। ऐसे ही गांधी जी ने भी विषय उठाया और लोग उनके साथ जुटते गए। उसमें सभी दलों के लोग थे, जो आज के समय में अलग-अलग दल हैं। उस समय दल नहीं थे क्योंकि देश इकट्ठा था और हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। इसलिए राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें चुनाव में वोट देने का अधिकार ही नहीं था। राजा बाहर से चुनकर आ जाते थे। उस समय गर्म दल के लोग, जो आज के वामपंथी होंगे, जिसको आप लोग हमारी विचारधारा के बोलते हैं, जिन्हें आप दक्षिणपंथी बोल सकते हैं, जिनको आप लोग आर0एस0एस0 बोल

25.03.2026/1320/एच0के0/ए0पी0/-03

सकते हैं या राष्ट्र भक्त बोल सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। उसी तरह से उसमें कांग्रेस के लोग भी थे और कांग्रेस उसका नाम था।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

25.03.2026/1325/AT/HK/01

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि एक समूह के रूप में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इस आज़ादी की लड़ाई में सरदार भगत सिंह जी ने भी कुर्बानी दी, लाला लाजपत राय जी ने भी बलिदान दिया, मंगल पांडे ने भी अपनी जान दी और झांसी की रानी ने भी लड़ाई लड़ी। उसमें महात्मा गांधी जी के साथ-साथ चाचा नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी जैसे बड़े और पढ़े-लिखे परिवारों के लोग भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने अपने करियर की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी शुरु की। लड़ाई लड़ते-लड़ते देश को आज़ादी मिली और इसमें बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। इसलिए मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह है कि कई बार आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोगों को ही बड़ा मान लेते हैं। जैसे एक फिल्म होती है, उसमें हीरो के साथ-साथ कई लोग काम करते हैं, कोई मशीनरी संभालता है, कोई अन्य भूमिका निभाता है और विलेन का भी

अपना रोल होता है। फिल्म की सफलता में सबका योगदान होता है। लेकिन वाहवाही केवल हीरो को ही मिलती है। इसी तरह देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत से लोगों का योगदान था, जिनका नाम इतिहास में नहीं आया।

उत्तर प्रदेश में आज भी एक ऐसा पेड़ है, जहां एक ही पेड़ की अलग-अलग शाखाओं पर 53 लोगों को मार कर लटका दिया गया था, अगर आप इनके खिलाफ बोंलेंगे तो आपकी भी यही स्थिति होगी। ताकि लोगों में डर फैलाया जा सके। अगर हम पूछें कि वे लोग किस पार्टी के थे तो क्या उनकी कांग्रेस की सदस्यता थी?

अगर हम भगत सिंह जी की बात करें तो क्या उनकी कोई सदस्यता थी और उन्होंने तो च्इंकलाब ज़िंदाबादछ का नारा दिया। क्या वे इस पार्टी से जुड़े थे? जब आप महात्मा गांधी जी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि जितना बोलना है उतना बोलो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो राष्ट्रपिता है, उनको जितना सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और सरदार पटेल जी को दिया है, उसके नाते वे हम सब के प्रिय हैं, तो जब आप ज्यादा उसके ऊपर बोलते हैं, तो हमें भी फिर बोलना ही पड़ता है कि क्या केवल चरखा कातने से आज़ादी मिल सकती थी? गांव की बहुत सी

25.03.2026/1325/AT/HK/02

महिलाएं भी सूत कातती थीं। चरखा एक प्रतीक था स्वदेशी का और आज़ादी की लड़ाई का। जिस स्वदेशी के लिए आज भी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी च्वोकल फॉर लोकलछ की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने चरखा दिया उसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी ने च्वोकल फॉर लोकलछ दिया। यह सबकी स्वदेशी की लड़ाई है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों को कहेंगे कि आपका आजादी के अंदर कोई रोल नहीं रहा है तो मुझे लगता है वो शायद अच्छा नहीं होगा, वो लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। जो हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेश जी, बैठिए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : सुरेश जी, आप भी हमारे यूनिवर्सिटी फेलो हैं। इसलिए आज़ादी का विरोध वही करते थे जो प्रस्ताव लिखकर के अंग्रेजों को कहते थे ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आप लोगों के परिवार में से कोई भी काला पानी में नहीं रहा है लेकिन वीर सावरकर के तीनों भाई काला पानी में रहे हैं। आपको उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ...(व्यवधान) मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो जिसको काला पानी की सजा हुई हो या फांसी हुई ?...(व्यवधान)

अध्यक्षः सतपाल सिंह सत्ती जी, आप आगे बढ़िए। ...(व्यवधान)

श्री सतपाल सिंह सत्ती : एक भी renowned leader का नाम मुझे बता दो, जिसको कांग्रेस के लीडर को फांसी हुई हो और काला पानी की सजा हुई हो।...(व्यवधान)

25.03.2026/1325/AT/HK/03

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्तपाल सिंह जी, अगर इस पर डिबेट होगी तो हाउस एडजर्न हो जाना है ।...(व्यवधान)

श्री सतपाल सिंह सत्ती : इसलिए ज्यादा बातें करने की आदत नहीं हैं। इसलिए किसी एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्तपाल सिंह जी आपका रेफरेंस आ गया है।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : ...(व्यवधान) आप लोग हमें बार-बार बोलते हैं कि (***)

अध्यक्ष : सत्ती जी ये नेगी जी ने नहीं बोला है। उन्होंने बोला छाती पर गोलियां खाई। उनकी छाती 55 इंच की नहीं थी, फिर भी छोटी छाती पर तीन गोलियां खाई। ये बोला है उन्होंने, ये नहीं बोला है। It is not a part of the record. सत्ती जी आप अरे परे मत जाओ नहीं तो हाउस एडजर्न हो जाना है।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : महात्मा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। ...(व्यवधान)

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1330/केएस/वाईके/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी --

क्या आपके मुंह से कभी राम राज्य की बात निकली? (***) महात्मा गांधी जी ने शराब का विरोध किया था कि इस देश के अंदर शराब के ऊपर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

25.03.2026/1435/av/ag/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.35 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती से आग्रह करता हूं कि आप अपना बचा हुआ भाषण पुनः प्रस्तुत करें।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुनः समय दिया, आपका धन्यवाद। वैसे उसी समय शायद मेरा भाषण दस मिनट्स में समाप्त हो जाता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सदन आपके दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलता है और चलना भी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के ऊपर बातचीत कर रहा था। यह जो बजट की चर्चा शुरू हुई है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। बीच में कई ऐसे तल्खी के विषय भी आए जैसे यहां सत्ता पक्ष के बहुत सारे साथियों ने 'मनरेगा' का नाम बदलने के संदर्भ में प्रश्न उठाए। हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह योजना

काफी लम्बे समय से अलग-अलग नामों से चलती रही है। यहां तक कि 'नरेगा' में भी बाद में ही स्व0 श्री महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया और फिर इसका नाम मनरेगा पड़ा। उसी प्रकार से आगे इस स्कीम के नाम पर कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके अनुसार अब मनरेगा का नाम 'विकसित भारत-जी राम जी' कर दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग महात्मा गांधी जी का अनादर करते हैं। अगर इस स्कीम से महात्मा गांधी जी का नाम हटा है तो इसमें उनसे बड़े व्यक्ति का ही नाम आया है जिनको हम 'भगवान राम' मानते हैं और महात्मा गांधी जी खुद भी राम राज्य की कल्पना करते थे। इसलिए इसमें अनादर का विषय कोई नहीं है।

टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1440/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती .... जारी

दूसरा, उन्होंने अंत में उस समय पर भी जैसा कहा गया या लिखा गया है कि जब उनको गोली लगी तो उन्होंने उस समय भी 'हे राम' कहा था। इसलिए किसी का अनादर करने का विषय नहीं है। उसमें पहले रोजगार का विषय था और अब जीविका मिशन का विषय जुड़ा है। रोजगार का मतलब होता है कि चंद लोगों को रोजगार देना और रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता। लेकिन आजीविका मिशन का मतलब है पूरे समाज के जीवों को चलाने के लिए आधार प्रदान करना। मुझे लगता है कि यह भावना विकसित भारत की भावना है और सबको रोजगार देने की भावना है। जीवन को चलाने के लिए साधन और आधार देने का मामला है। इसलिए बार-बार इस विषय को शायद यहां नहीं लाना चाहिए क्योंकि बहुत बार इस विषय पर लोग बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, ओ0पी0एस0 का मुद्दा यहां बार-बार आता है। कई बार जबरदस्ती ये हम लोगों पर थोपते हैं कि हमने इसे बंद किया। ओ0पी0एस0 कांग्रेस के ही शासन काल में बंद हुई थी और कांग्रेस ने ही 15—20 वर्षों के बाद ओ0पी0एस0 को फिर से शुरू कर दिया । इसमें न तो कोई क्रेडिट लेने की बात है और न डिस्क्रेडिट की बात है । आपकी स्कीम अगर उस समय गलत थी तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को अपने मुख्य मंत्री जी

का विरोध करना चाहिए था लेकिन उस समय आप लोग चुप रहे। सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने इसे लागू किया और यह लागू हो गई तो यह अच्छी बात है। लेकिन हमने इसमें कभी कोई अपोज नहीं किया। इसी तरह से बार-बार हम लोग कई बातें एक-दूसरे पर थोपने की जरूरत करते।

अध्यक्ष महोदय, हमें इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। सबसे बड़ा विषय यह है कि सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार कितनी ताकत से काम कर रही है क्योंकि इस सरकार का कैबिनेट ही 5 साल में पूर्ण नहीं हुआ । यहां डिप्टी स्पीकर और एक मंत्री की पोस्ट अभी भी खाली है। माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी का नाम भी सुक्खू जी ने फाइनल कर दिया था और इनको श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने कहा कि ये कभी मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर उनके कहने पर सुक्खू

जी ने नाम फाइनल कर दिया लेकिन आप दोनों रिश्तेदार हैं, हमें ऐसा पता नहीं था। हमारे विपक्ष के नेता श्री जय राम जी ने बताया कि हमारी भतीजी इनके परिवार में है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि कुछ बातें हम लोग अच्छी करेंगे तो हिमाचल आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस पर मैं पहले भी कई बार विस्तार से बोल चुका हूं और दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। यह गन कल्चर, नशे का कल्चर, भ्रष्टाचार ये सारे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए विषय हैं। भ्रष्टाचार इस स्तर पर पहुंच गया है कि हिमाचल प्रदेश में भू-माफिया बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय है। श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने बड़े ऑफिसों के बारे में बताया भी था। शायद इन्होंने किसी प्रदेश का नाम ले लिया था उसके कारण गलत लगा हो लेकिन इन्होंने बात बिल्कुल सही कही थी क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग ईमानदार और शांतिप्रिय हैं। ईमानदारी से जीने वाले लोगों है और उन्हें बहुत ज्यादा धन-संपदा इकट्ठी करने की आदत भी नहीं होती है। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि पूरे देश के लोग भी ऐसे ही ईमानदार है। कई बार पड़ोसी के कल्चर का भी फर्क पड़ता है। अब यहां कुछ ऐसे अधिकारी आ गए हैं जिनके नाम पर चेस्टर हिल टू एंड

फोर करके सोलन में 274 बीघा का प्रोजैक्ट है। उसके बारे में किसी ने डी0सी0, सोलन को शिकायत की और जिलाधीश, सोलन ने एस0डी0एम0 को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसकी रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें धारा 118 का उल्लंघन हुआ है और साथ ही शैडो वायर्ज के नाम से यह जमीन खरीदी गई है यानी जिसकी हैसियत नहीं थी उसके नाम पर यह जमीन ली गई है और वहां बड़े-बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जिसने भूमि खरीदी है उसके पास इतनी भूमि खरीदने की हैसियत नहीं थी। यह एस0डी0एम0, सोलन की रिपोर्ट है। लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय ह प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति तक यह रिपोर्ट जाती है और उन्होंने उस सारी रिपोर्ट को रोकने की कोशिश की। जबकि एस0डी0एम0 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस केस को ई0डी0, सी0बी0आई0 या आयकर विभाग को देना चाहिए लेकिन नहीं दिया

एन0एस0 द्वारा .... जारी

25-3-2026/1445/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती----जारी

उसके बाद उस रिपोर्ट को वहीं पर दबा दिया गया। इस तरह की बातों के ऊपर हमें निर्णय लेने की जरूरत है। इसी तरह से उस व्यक्ति ने मुझे एक रिपोर्ट और दी कि प्रदेश के ही एक बहुत बड़े अधिकारी ने जमीन ली है। हम सबको पता है कि मोहाली और चंडीगढ़ में जमीनें कितनी महंगी हैं? 5 एकड़ जमीन खरड़ और मोहाली के बीच में 1.30 करोड़ रुपये की मिल गई। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं आपको उसका नाम बता दूंगा और आप उस अधिकारी से बात करें। आप उसको दोगुना पैसा देकर वहां 5 एकड़ में एक बड़ा हिमाचल भवन बनाएं क्योंकि हमें हिमाचल भवन, चंडीगढ़ में कई बार कमरे नहीं मिलते हैं और न ही हमें इतना बड़ा भवन बनाने के लिए कहीं और जगह मिलेगी। आप उसको कहें कि हम आपको डबल पैसा दे रहे हैं अगर आपने इतने में यह जगह ली है। आप खुद

सोचिए, 5 एकड़ जमीन 1.30 करोड़ रुपये की मिली है तो उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। वे कोई छोटे अधिकारी नहीं है। मेरे से कई बार सच बोला जाता है। जब वे बिजली बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने बिजली विभाग को खम्भे सप्लाई करने वालों से कमीशन ली थी। मैंने यह बात सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाई कि आपका नाम लेकर वे पैसे मांग रहे हैं और क्या आपने इनको पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला है? उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अखिर उस ठेकेदार को पेमैंट पैसे देकर ही मिली। मैंने आपके राजनैत्तिक व्यक्तियों से भी बातचीत की। मैंने बड़े अधिकारियों से भी बातचीत की। मैंने उनको स्वयं फोन नहीं किया लेकिन बाकी लोगों से फोन करवाए लेकिन वहां पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने जिस कल्चर के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया है, यह कल्चर हमारे लोगों, अधिकारियों और नेताओं को बिगाड़ने का कल्चर है। हम सब लोग बड़े सीमित साधनों में रहने वाले लोग हैं और उसके नाते इन बातों के ऊपर हम लोग यहां पर खुले में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर आरोप-प्रत्यारोप होंगे लेकिन कभी अलग से बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए कि हमें प्रदेश को कहां लेकर जाना है? लोग इतनी जमीनें खरीद रहे हैं, इतनी सम्पत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। मैंने परसों ही प्रश्न लगाया था कि जे0एस0वी0 और लोक निर्माण विभाग में ऊना डिवीजन के अंदर कितने ऑफलाइन टेंडर लगे हैं? अब आप इससे कल्पना कर सकते

25-3-2026/1445/एन0एस0-ए0एस0/2

हैं कि पूरे प्रदेश में कितने लगे होंगे? मैं यह नहीं कहता कि सब जगहों पर लगे होंगे। जहां ईमानदार नेता बैठे हैं वहां नहीं लगे होंगे क्योंकि हमारे वहां पर राजनीति के अंदर एक गिरोह रूपी वर्किंग हो रही है जिसके कारण गैंगवार भी हुआ, जिसके कारण नालागढ़ में क्रशर लगाने के लिए महिलाओं को भी पीटा गया और दूसरा क्रशर भी लगाया गया तथा बिना परमिशन 3 किलोमीटर पहाड़ी काट कर रोपड़ को सड़क भी निकाल दी गई, यह अखबारों में कहा गया है, मैं वहां नहीं गया हूं। यह दैनिक भास्कर अखबार की न्यूज थी।

अध्यक्ष महोदय, ऊना अस्पताल के अंदर दो दलाल रूपी व्यक्ति बैठा दिए गए कि आपने किसकी दवाई लिखनी है? यहां तक कि आर0टी0ओ0 में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वहां पर जितने भी एजैंटस काम करते हैं और हम ज्यादातर लोग एजैंटों के थ्रू ही कागज बनवाते हैं जोकि लीगल नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। वे 500 रुपये लेकर आपके कागज बनवा देते हैं और वहां भी एक व्यक्ति बैठा दिया गया कि जितने एजैंटों के पैसे होंगे तो उनमें से 1000 रुपये उसको देना होगा तथा उसके बाद आप सबके कागज पास होंगे। इसके बारे में आर0टी0ओ0 को भी कहा गया है। वन विभाग में भी लोग बिठाए गए हैं। मैहतपुर के अंदर लॉटरी का भी एक हैड है और वह दो बार पकड़ा गया तथा उसके बाद ऊना से पूरी पुलिस बदल दी गई। मिलट्री से आए हुए व्यक्ति डी0एस0पी0 की बदली ऊना से रिकांगपियो को करवा दी गई। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी को बताया कि उसने 3.30 बजे रेड मारी और 5.47 लाख रुपये पकड़े तो क्या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? वहां पर 14 लोग पंजाब के पकड़े गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग फिल्लौर, जालंधर, आनंदपुर साहब से लॉटरी (जुआ) खेलने आए थे? वे आती बार पता नहीं चिट्टा लेकर आए या भुक्की लेकर आए या वहां पर कुछ और धंधे करके गए तथा जाती बार जुआ खेल रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई। माननीय मुकेश जी, ऊना डिवीजन में जे0एस0वी0 में 3262 ऑफलाइन टेंडर लगे हैं। वहां पर 99 हजार रुपये, 98 हजार रुपये, 92 हजार रुपये के टेंडर लगे हैं। मैं अब उन कार्यों की वीडीयो बनाऊंगा कि ये काम कहां-कहां हुए हैं? मैंने आर0टी0आई0 में सूचना मांगी है। मैंने आपको इसकी डिटेल दे दी है। पंप हाउस के आसपास घास काटना है। मान लो, मैं वहां पर पंप ऑपरेटर हूं तो उस चार दीवारी के अंदर घास को

25-3-2026/1445/एन0एस0-ए0एस0/3

काटने के लिए मैंने एस0ई0 व एक्सिअन को कहा कि आप घास काटने का 50 हजार रुपये का टेंडर लगा रहे हैं, बारिश होने के बाद फिर 25 दिनों में और घास हो जाएगा। आप इसके लिए पंप ऑपरेटर को दराटी दे दें और कहें कि आप यहां पर मोटर चलाने के बाद घास भी काट लेना। एक बटन दबाना फिर मोटर चलती रहती है। वहां पंप ऑपरेटर का

और क्या काम है, क्या वह घास नहीं काट सकता? घास काटने के लिए 99 हजार रुपये के टेंडर हुए। आप हमारे जिला के मंत्री हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसा बोला जाता है कि बड़े प्रभावशाली हैं तथा ऐसा माना भी जाता है लेकिन आप थोड़े डीले पढ़ गए हैं। आप थोड़ा दम दिखाएं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं जिन्होंने कल कहा कि विभाग के अंदर जीरो टोलरैंस है। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, ऊना डिवीजन में 1134 ऑफलाइन टेंडर लगे हैं

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.03.2026/1450/RKS/As-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

लगभग 4-5 करोड़ रुपये के इन ऑफ-लाइन टेंडरों में टपोरी टाइप के ठेकेदारों को काम मिला है। इनको काम करवाना नहीं आता लेकिन यही लोग ठेके लेते हैं। आपने उनको 4 करोड़ रुपये के टेंडर दे दिए हैं। इनके ऊपर भी यहां पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। माननीय राजस्व मंत्री जी भी यहां इतिहास की बातें कर रहे थे। इसके कारण तो यह स्थिति हुई है कि आप लोगों को कर्मचारियों की पेंशन और विधायकों के वेतन काटने पड़े। कर्मचारियों के मेडिकल रिइम्बर्समेंट बिल तीन वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं। मैं उन लोगों के कई बार नाम बता चुका हूं। एक हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं जिनकी धर्मपत्नी काफी समय से बीमार है और उन्हें कैंसर है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी इस बारे में लिखकर देना चाहता हूं। उनका एक माह का लगभग सवा लाख रुपये खर्च आ रहा है। रिटायर्ड प्रिंसिपल को इतनी तो पेंशन नहीं मिलती है। उनके 22 लाख रुपये के बिल पेंडिंग पड़े हैं लेकिन यह सरकार उन बिलों का भुगतान करने में असमर्थ है। यह स्थितियां हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों पैदा हुईं? आज उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। सोशल वेलफेयर के अंतर्गत विधवा, अपंग और वृद्धजनों की पेंशन 7-7 महीनों से नहीं मिल पा रही है। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने सहारा योजना चलाई थी लेकिन जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें 7-7 महीने से इस योजना के तहत पैसे नहीं मिले हैं। मैंने उन लोगों का कई बार जिक्र किया। मैंने भोरंज और देहला के व्यक्ति का नाम बताया था। वे कहते हैं कि हमारी दवाई 12 या 15

सौ रुपये की आती है और पैसे न मिलने की वजह से उन्हें दवाई लेने में दिक्कत आ रही है। उनके घरवाले भी परेशान हैं। हमें इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें इस तरह की नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए ताकि भविष्य में उन लोगों को परेशान न होना पड़े। पहले भी पी0टी0ए0 पर लोग रखे गए थे। आप कभी शिक्षक मित्र, कभी रोगी मित्र, कभी वन मित्र, कभी पशु मित्र, कभी मल्टी टास्क वर्कर, कभी पैरा-फिटर, कभी पैरा-पंप ऑपरेटर और शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर लगा रहे हैं। ये सारे लोग थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह में अपना काम कर रहे हैं। इनके लिए सरकार द्वारा कोई स्कीम नहीं बनाई जा रही है कि इनको पक्का कैसे करना है।

25.03.2026/1450/RKS/As-2

ये लोग इस आश में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं कि हम कल पक्के हो जाएंगे। अगर आप 15 साल बाद इन लोगों को पार्ट टाइम में लेंगेया 10 साल के बाद डेलीवेज कर देंगे या फिर 12 साल के बाद इन लोगों को पक्का कर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट में ले आएंगे तो उनकी शादियां तो हो जाएंगी या वे अपने परिवार को किसी तरह चला लेंगे। वे 10 साल तो किसी सहारे से काट देंगे लेकिन अगर आप उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? इसलिए इन सब चीजों के ऊपर बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर ऐसी टेम्परेरी स्कीमें बनाना बंद करनी चाहिए। आज बी0 टेक किए हुए लोग 12 हजार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। वे अपना परिवार कैसे चला रहे हैं, यह कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश के भीतर बहुत-सी आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्टरियां हैं। यहां पर माननीय यादविंद्र गोमा जी उपस्थित नहीं हैं। पिछले तीन सालों में एक भी दवाई उन फैक्टरियों से नहीं खरीदी गई। यह जो पंजाब वालों का लेनदेन होता है, उसके चक्कर में अधिकारी फंस जाते हैं। मंत्रियों का काम तो चौकीदारी करना है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जनता है क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे हैं। इसलिए ऑफिसर्स के ऊपर चेक रखना हमारा काम है। अगर आप उन फैक्टरियों से दवाइयां ही नहीं खरीद रहे हैं तो वे फैक्टरियां कैसे चलेंगी? मैं उनकी यूनियन की कई बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर, आयुर्वेद से बात करवा चुका हूंलेकिन समस्या यह है कि 6 महीने बाद सेक्रेटरी और डायरेक्टर बदल जाते हैं। फिर हमें नए सेक्रेटरी और डायरेक्टर को पूरी कहानी बतानी पड़ती है। लेकिन मंत्री जी तो पांच साल के लिए होते हैं। इसलिए मेरा

माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे इन चीजों पर विचार करें। अगर कोई अधिकारी घाल-मोल कर रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। लोगों को यह लगता है कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत हमें पैसा मिलता है। इसलिए इसमें लोगों की सहानुभूति नहीं है कि यह निधि क्यों काटी गई। इस निधि से लोगों के लिए रास्ते और डंगे इत्यादि लगाने का काम होता है। जब हम इन चीजों के लिए पैसा देने से इंकार करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि सुक्खू जी ने हमारे अधिकारों पर आघात कर दिया है। मुख्य मंत्री जी को इस निधि को काटने की बजाय आगे बढ़ाना चाहिए था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भीतर 6 टोल टैक्स बैरियर लगे हुए हैं। आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने ज्यादा टोल टैक्स नहीं बढ़ाया है। जिस कार का टोल टैक्स श्री जय राम ठाकुर के समय 40 रुपये था उसे 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये और अब 70 से 170 रुपये कर दिया गया है। क्या यह टोल टैक्स ज्यादा नहीं है?

25.03.2026/1450/RKS/As-3

मैहतपुर में ट्रक वालों को 900 रुपये टोल टैक्स देना पड़ेगा। जब लोग टैक्सी में चिंतपूर्णी, नैना देवी जी, ज्वाला जी या आनंदपुर साहिब माथा टेकने जाते हैं तो जो टैक्सी 900 रुपये में मिलती थी उसका किराया अब 1200 रुपये कर दिया गया है क्योंकि 300 रुपये वापसी आते समय टोल टैक्स लगता है। इसलिए इस टोल टैक्स के ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऊना जिला इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? वहां पर 33 टोल टैक्स बैरियर में से 6 मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1455/बी.एस./ए.एस.-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

और बाकी 5 पूरे जिले के अंदर हैं। कुल 11 टोल टैक्स बैरियर ऊना के अंदर हैं। आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने जो विषय उठाया था, गढ़ा-मोड़ा के पास आदरणीय धर्माणी साहब

दीपावली से दो दिन पहले मैं वहां से गुजरा तो जो हमारा अपना बैरियर और जो नेशनल हाईवे का बैरियर है, दोनों तरफ की गाड़ियां इस तरह फंस गईं कि गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। लगभग 40 मिनट तक मैं वहां रुका रहा। बाद में पंजाब और दिल्ली के कुछ लोग और हिमाचल के लोग भी गाड़ियों से डंडे ले करके उतरे। उन्होंने बैरियर खोल दिए और कहा कि हम कोई पैसा नहीं देंगे। हम एक घंटे से फंसे हुए हैं। हम लोग घर जा रहे हैं और दिल्ली से भी हमारे ही लोग दिवाली के लिए घर आ रहे थे। उनसे हम 170 रुपये लेंगे, दिवाली पर 99 प्रतिशत लोग हिमाचल आते हैं। कोई दिल्ली से, कोई चंडीगढ़ से, कोई हरियाणा से और कोई पंजाब से हैं। उनकी गाड़ियों के नंबर भी बाहर के होते हैं। तो वे कहेंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया? मेरा आग्रह रहेगा कि टोल टैक्स बैरियर के मुद्दे पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। पेट्रोल-डीजल महंगा करेंगे, तो महंगाई और बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो गलत हुआ है, उस पर भी मैं धीरे-धीरे बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें, थोड़ी अपनी गति बढ़ाइए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने दूध के रेट बढ़ा दिए। लेकिन जिन लोगों ने दूध दिया है, उन्हें तीन महीने से पैसे नहीं मिले हैं। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं। दूसरी बात, अब लोगों से दूध लेना भी बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 20 लीटर ही लिया जाएगा। लोगों ने पैसे लगाकर पशु खरीदे थे। लेकिन अब दूध का क्या होगा? यह स्पष्ट नहीं है। जो टैक्स आपने विधवा और अनाथ के ऊपर टैक्स लगाया है, वह कहां जाएगा, इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मैं अपने को सही करता हूं जैसा आदरणीय अवस्थी जी ने कहा कि उनके नाम से टैक्स लगाया है।

25.03.2025/1455/बी.एस./ए.एस.-2

अध्यक्ष महोदय, छोटे रोजगार करने वाले, जैसे थ्री-व्हीलर चालक हैं उनके साथ भी समस्या है। आपके क्षेत्र में भी होंगे। शायद भटियात में नहीं तो चम्बा में तो होंगे ही। पिछले 4-5 सालों से थ्री-व्हीलर के परमिट ही नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों ने थ्री-व्हीलर खरीद लिए लेकिन परमिट नहीं मिले, फिर पुलिस उन्हें पकड़ती है कि तुम्हारा परमिट नहीं है। जबकि परमिट सरकार ने ही बंद किए हुए हैं। यह विषय मैंने आदरणीय बाली साहब के समय और

आदरणीय किशन कपूर जी के समय भी उठाया था। फिर लोगों को परमिट दिलवाये थे। उस समय कहा गया कि सी0एस0 की नाराजगी के कारण परमिट बंद कर दिए गए। अगर ऐसा है तो आप कारें खरीदना बंद कर दीजिए अगर आपमें हिम्मत है तो बड़े लोगों की गाड़ियां भी बंद करनी चाहिए। गरीब आदमी के थ्री-व्हीलर क्यों बंद किए जा रहे हैं? इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कई और बातें भी हैं। जैसे हमारे प्रदेश में आई0डी0पी0 प्रोजेक्ट चलात है जिसमें लगभग 300 कर्मचारी 20-25 साल से काम कर रहे हैं। अब वह 31 मार्च को बंद हो रहा है। यह सोचना चाहिए कि उन कर्मचारियों का क्या होगा? उन्हें कहां समायोजित किया जाएगा। वे अब उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं बताई गई है। ...(घटी)... इसी तरह गांव के चौकीदार हैं, जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं। न वे दिहाड़ी पर हैं और न कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और कम वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिन पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और कैबिनेट मंत्रियों को इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। परंतु राजस्व मंत्री महोदय, तो जा करके आजादी के आंदोलन में घुस गए। अगर आप लोगों का भला करेंगे तो उन बातो को याद रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरा आग्रह है कि हम एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय इन मुद्दों की सूची बनाएं और उनके समाधान के लिए ठोस निर्णय लें। ताकि जनता के बीच हमारी छवि बेहतर बने और लोग कहें कि उनके प्रतिनिधियों ने काम किया है।

मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन करप्शन और गुंडागर्दी के बारे मुद्दे पर रहेगा कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अच्छे अधिकारियों को लगाने से होगा और जो अधिकारी गलत हैं, उनको सजा देने से होगा। वरना जंगल भी कट जाएंगे, नशा भी फैल

25.03.2025/1455/बी.एस./ए.एस.-3

जाएगा और उसके बाद हम केवल व्याख्यान करते रह जाएंगे। हम नारे भी लगाएंगे और अच्छे कार्य के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। उसमें ठाकुर जय राम जी ने भी कहा है कि

आप लोग हमें भी बुलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। यह लड़ाई किसी एक पार्टी या एक नेता की नहीं है। यह लड़ाई हम सबके भविष्य की है। आने वाली पीढ़ी की है। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप सब लोग चीजों को ठीक करें। अगर ठीक करेंगे, तो आपको मान-सम्मान मिलेगा। वरना लोग यही कहेंगे कि बहुत सी बातें करके आए थे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो हम आपके साथ हैं। अगर आप गलत काम करेंगे, तो हम आपका डटकर विरोध करेंगे। यही हमारा धर्म है और यही हमारा फर्ज है। इसी निवेदन के साथ, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1500/DT/DC-1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी आपका धन्यवाद। Today Mrs. Kamlesh Thakur is delivering her maiden speech and will be replying to Shri Satpal Singh Satti.

श्रीमती कमलेश ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय,आज आपने इस सदन में मुझे बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका और इस मान्य सदन का धन्यवाद करती हूं। आज इस मान्य सदन में मेरी पहली स्पीच है। मैंने भी सोचा, क्योंकि आजकल नवरात्रे चले हुए हैं, इसलिए मैं भी इस शुभ मुहूर्त में सदन में हो रही चर्चा में हिस्सा लूं।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए प्रस्तुत किए गये बजट अनुमानों में प्रदेश के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं मान्य सदन को बताना चाहती हूं कि प्रदेश में वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में भंयकर बाड़ आई उन परिस्थितयों का समाना करते हुए हमारी सरकार ने सभी प्रदेश वासियों का ध्यान रखते हुए 21 मार्च, 2026 को जो बजट पेश किया गया उसमें महिलाओं, बच्चों, बेरोजगार युवाओं, बुजुर्ग एवं बेसहारा यानी सभी वर्गो के लोगों का ध्यान रखा गया है। बजट अनुमानों मे के आंकड़ों में समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, बजट की प्रस्तुति दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने समाज के हर व्यक्ति को समाज के भीतर आत्मविश्वास एवं आत्म निर्भरता प्रदान करने की ओर यह बजट पेश किया है। यह बजट आम आदमी की नीजि और रोजमर्रा जिंदगी से संबंधित है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बात और कहना चाहती हूं। प्रदेश में ऐसी भंयकर आर्थिक परिस्थिति में इस बजट को पेश किया गया है और उसमें हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखा गया है । ऐसा वर्ग जिसके बारे में पूर्व में कभी भी सोचा नहीं गया, उस ओर भी सरकार ने कदम उठाया है, उसमें चाहें महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों। हमारी सरकार ने वर्ष 2022 से लेकर आज तक महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं। हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी सरकार के समय या पूर्व सरकारों के समय आउटसोर्स में लगे कर्मचारी सभी के वेतन बढ़ाये हैं। इस बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कि और आशावर्कर के वेतन में 1000 रुपये की बढौतरी की गई है। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम लोग हैं उनकी समाजिक पेंशन को 1700 से बढ़ाकर 3000/- रुपये कर दिया गया है। मैं

25.03.2026/1500/DT/DC-2

यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने एकल नारी की चिंता भी की है ताकि समाज में उसका जीवन सुरक्षित हो।

हमारी सरकार ने प्रदेश के गरीब लोगों के लिए 300 युनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का भी निर्णय लिया है-जो लोग पात्र होंगे उनको यह सुविधा मिलेगी। हमारे प्रदेश के किसान, हमारी ग्रामीण महिलाएं जो अपने गांव में छोटा-मोटा काम करती हैं, उनको भी ख्याल रखा गया है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती की ओर विशेष ध्यान दे रही है। जिन लोगों ने घर पर गाय-भैंस पाली है हमारी सरकार उन लोगों से उनके घरद्वार में जाकर दूध खरीदने का काम भी कर रही है। गरीब लोग जिन्होंने गाय-भैंस रखी है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

25.03.2026/1505/एच.के.-एन.जी./1

श्रीमती कमलेश ठाकुर..... जारी

हम सब जानते हैं कि पहले के समय में एक परिवार में आठ या दस लोग होते थे तो मिल-जुलकर काम हो जाता था। आज परिवार में एक-दो ही लोग रह गए हैं। अगर हमारा कोई

भाई-बहन या किसान व्यक्ति गाय-भैंस पालता है तो उसे गाय-भैंस के चारे के लिए मशीनरी खरीदनी पड़ती है, कृषि के लिए तरह-तरह के उपकरण रखने पड़ते हैं और ये सब चीज़ें बिजली पर ही निर्भर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे-छोटे कार्य करने वाली हमारी महिलाएं, जैसे सिलाई-कढ़ाई करने वाली महिलाएं या ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं या कोई महिला लिफाफे बनाती है या हमारे समाज में जो युवा बेरोजगार पढ़े-लिखे बच्चे हैं परंतु नौकरी न होने के कारण वे साथ-साथ पढ़ भी रहे होते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अगर उन बच्चों, महिलाओं या किसानों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाए तो यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा कदम है। बिजली की 300 यूनिट एक आम व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। हम जानते हैं कि आज चाहे देश हो या प्रदेश, एल0पी0जी0, मनरेगा जिसको केन्द्र सरकार ने VB-G-RAM-G बना दिया है और तीसरे नंबर पर हमारी आर0डी0जी0—इन तीनों की स्थिति खराब नहीं बल्कि तीनों ही वेंटिलेटर पर हैं और जिसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बहन आर0डी0जी0, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी VB-G-RAM-G और तीसरे पर एल0पी0जी0—इन तीनों बहनों की स्थिति खराब है। आर0डी0जी0 का प्रदेश पर और एल0पी0जी0 व VB-G-RAM-G का असर देश की आम जनता पर पड़ रहा है।

25.03.2026/1505/एच.के.-एन.जी./2

अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया ने बताया कि पिछले कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और एल0पी0जी0 के ऊपर एक नया नियम बनाया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी और पात्र महिलाओं को उसके तहत गैस कनेक्शन मिले थे, लेकिन उनके लिए सिलेंडर बुक करवाने हेतु 45 दिन की कंडीशन रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि एक समय था जब गांव के लोग जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठी कर लेते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि होटल हॉलिडे होम में भी खाना लकड़ी की भट्ठी पर बन रहा है। यहां तक कि स्थिति ऐसी हो गई है कि विधान सभा के अंदर भी लकड़ी की भट्ठी पर खाना बनाने की परिस्थिति बन गई है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम पात्र महिलाओं या व्यक्तियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, जैसा कि बजट में दर्शाया गया है, तो यह लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि लकड़ी लेने के लिए जंगलों में जाने का समय किसी के पास नहीं है और परिस्थितियां बदल गई हैं। आज अगर किसी घर में दो लड़कियां या एक लड़की-लड़का है, तो उसे घर से बाहर भेजने का समय बहुत दूर चला गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर शिक्षा के लिए स्पेशल बजट दिया है। इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके विभाग के लिए विशेष बजट दिया गया है और यह जरूरी भी है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज गरीब आदमी का बच्चा गवर्नमैंट स्कूल में पढ़ता है, नहीं तो आमतौर पर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही जाते हैं। यहां पर विरोध किया गया कि सी0बी0एस0ई0 स्कूल किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हर मां-बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी-से-अच्छी शिक्षा ग्रहण करे।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1510/एच0के0/ए0पी0/-01

श्रीमती कमलेश ठाकुर जारी .....

अध्यक्ष महोदय, हमारा मकसद हिमाचल बोर्ड का विरोध करना नहीं है, हिमाचल बोर्ड को पीछे करना नहीं है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड को भी उसी तरह आगे लाना चाहता है जिस तरह हमारी सरकार सी0बी0एस0ई0 बोर्ड पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने कई बार देखा है कि कई गरीब परिवारों के बच्चे हिमाचल शिक्षा बोर्ड से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन जब वह बच्चे प्रदेश से बाहर, पंजाब या दिल्ली

यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो उनके एडमिशन के समय एक-दो पॉइंट्स को कम गिना जाता है। क्योंकि जितने भी राज्य बोर्ड हैं उनके अंक दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में कम कर दिए जाते हैं। इस तरह से हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। हम यह चाहते हैं और हमारी सरकार का भी यही उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से गरीब भाई-बहनों के बच्चे, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन्हें भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सक। उनके बच्चे भी उसी तरह से शिक्षा ग्रहण करें। उसी उद्देश्य से प्रदेश की 68 विधान सभा क्षेत्रों में सी0बी0एस0ई0 स्कूल खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है। मैं यह भी कहती हूं कि किसी भी चीज़ को धरातल पर लाने के लिए समय लगता है और समय के साथ-साथ सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, जैसे इस बजट में दर्शाया गया है कि जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है, उन्हें बंद किया जा रहा है। इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र देहरा का एक कॉलेज भी है। जिसे हमारे माननीय पूर्व उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी ने अपने समय में खोला था। किसी कारणवश वहां बच्चों की गणना बहुत कम है और उसे बंद करना पड़ रहा है। मैंने भी अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में तीन-चार अध्यापकों/प्रोफेसरों/लेक्चररों के लिए डी0ओ0 नोट लगाए, लेकिन वे अध्यापक/प्रोफेसर/लेक्चरर कहीं दूसरी जगह जाकर उन्हें रद्द करवा देते थे। जहां पर कॉलेज स्थापित है, वहां न तो शिक्षक जाते हैं और वह बहुत दुर्गम क्षेत्र में भी पड़ता है। किसी कारणवश उस कॉलेज को बंद करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने बजट में यह प्रावधान किया है कि जो छात्र उस कॉलेज से टी0सी0 लेकर दूसरी जगह एडमिशन लेता है, उसे पांच हज़ार रुपये दिए जाएंगे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस कदम का स्वागत

25.03.2026/1510/एच0के0/ए0पी0/-02

करती हूं। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी पर इस बजट में एक अलग से प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते है कि किसानों के लिए अदरक, गेहूं, मक्की, दूध, हल्दी आदि इन सभी के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है। जिसका सीधा लाभ किसानों को हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की इन नीतियों से प्रभावित होकर लोगों अपनी बंजर पड़ी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपनी जमीन को

संभालना शुरू कर दिया है। आज कल खेती न करने का एक कारण यह भी है कि पशुओं या अन्य जानवरों द्वारा खेती का उजाड़ बहुत अधिक हो गया है। देहरा, प्रागपुर, नदौन, ज्वालाजी आदि निचले पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली गाय, सूअर और अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। जानवरों से फसलों को बचाने के लिए सरकार द्वारा मुख्य मंत्री खेत बाड़बन्दी योजना लाई गई है, मैं इस योजना का भी स्वागत करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र देहरा में ज्यादा नहीं तो 5-6 लोग जो खेती करते हैं उनको विधायक निधि से खेती के लिए सहायता की थी। विधायक निधि में एक परमिशन दी गई थी कि आप अपनी विधायक निधि से बाड़बन्दी के लिये पैसे दे सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से उनकी सहायता करने का प्रयास किया है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1515/AT/YK/01

श्रीमती कमलेश ठाकुर जारी....

जैसे कि विधायक निधि में एक अनुमति दी गई थी कि आप अपनी विधायक निधि से बाड़बंदी के लिए पैसे दे सकते हैं, तो मैंने उनकी इस तरह से सहायता भी की है। आज वे लोग ज़्यादा नहीं तो दस-बारह क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए चिल्ड्रन ऑफ स्टेट की योजना बनाई है और उन्हें गोद लिया है। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम अनाथ आश्रम में जाते थे या यहां बैठे आप सभी लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं, हमारा और हमारी सरकार का मकसद उन अनाथ बच्चों को गोद लेने का ही था। क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चा 12वीं कक्षा तक उस अनाथ आश्रम में रहता है तो वह पूरी तरह अपनी आया या केयरटेकर पर निर्भर रहता है। जो भी व्यक्ति वहां जाता है, वह अक्सर जन्मदिन या किसी बड़े दिन जैसे दिवाली या अन्य त्यौहार पर वहां पर जाकर कुछ-न-कुछ बांटकर आता है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें उन्हें हर त्यौहार पर सरकार की तरफ से पांच सौ से एक हजार रुपये दिए जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ यही है कि वे बच्चे, जो 18-20 साल की उम्र तक बाजार में सौ या पांच सौ का नोट भी ठीक से नहीं देख पाते थे, उन्हें यह समझ आए कि बाजार में जाकर खरीदारी कैसे करनी है और मोलभाव कैसे किया जाता है, कौन-सी चीज कहां मिलती है। अध्यक्ष महोदय, उन्हें exploitation से बचाने के लिए यह योजना बनाई गई है।

मैं सरकार की इस योजना का भी सम्मान करती हूं। इसके साथ-साथ हमने जनजातीय क्षेत्र के लोगों की संस्कृति जैसे पांगी और लाहौल में एकलव्य आवासीय स्कूल का भी विवरण है। जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे हमारे गद्दी भाई हैं, जिनकी आय का मुख्य साधन भेड़-बकरियां थी और वे साल के लगभग आठ महीने बाहर रहते थे। कई बार उनके साथ कई दुर्घटनाएं भी होती थी और उनकी आय का साधन भी बहुत सीमित होता था।

25.03.2026/1515/AT/YK/02

इसलिए इस बजट में उनकी ऊन के दाम बढ़ाए गए हैं। साथ ही उन्हें बीमा इंश्योरेंस की सुविधा और मेडिकल सहायता भी दी गई है। इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देना चाहती हूं और इस बजट की भी सराहना करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और इस बजट का समर्थन भी करती हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आंकड़ों की बात मेरे से पहले वक्ताओं ने कर ली है। लेकिन इस सदन में मुझसे अधिक अनुभवी, वरिष्ठ, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, कानूनविद और राजनेता इस सदन में सभी बैठे हुए हैं। मैं तो एक आम महिला हूं। इसलिए मैं आंकड़ों पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि इस बजट में पहले ही अच्छे तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह बजट बुक बहुत भारी इसलिए है क्योंकि इसमें आंकड़ें बहुत ध्यान से लिखे हुए है। और कहते हैं कि गीता एक बुक नहीं हैं। इसी तरह यह जो बजट बुक है, यह बुक नहीं है बल्कि यह बजट सार समझा जाए। अध्यक्ष

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं और बजट का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

Speaker : Wonderful speech by Smt. Kamlesh Thakur. Though, it was her median speech but it was a wonderful speech. Madam, I must congratulate you. अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1520/केएस/वाईके/1

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो 21 मार्च, 2026 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान इस सदन में रखा है। उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं कमलेश ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने आज इस माननीय सदन में मेडन स्पीच रखी है और आपको देखकर मुझे भी कुछ याद आ रहा है। जैसे आप राजनीति में आए, वैसे ही मैं भी आया था। कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे परंतु राजनीति में आए और लम्बे समय तक चलते रहे। यह ठीक है कि परिवार का साथ मिलता है, परिवार का नाम मिलता है परंतु साथ में अपने काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे हमारे बहुत से साथी यहां पर हैं जैसे हषवर्धन चौहान जी है, विक्रमादित्य सिंह जी हैं। सभी को काम करने का मौका मिलता है परंतु एक परिवार से आने का फायदा यह होता है कि हमने उस परिवार में अपने बुजुर्गों का काम देखा होता है और लम्बे समय से हम यह देखते आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पक्ष बजट का समर्थन करता है और विपक्ष उसकी कमियों को उजागर करता है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई बजट परफेक्ट नहीं हो सकता। ये एक बात कहते हैं कि 16वें वित्तायोग ने आर0डी0जी0 बंद कर दी । मैं मार्ग से नहीं भटकना चाहता, यहां पर आजादी से पहले और बाद की बातें की गईं। हमारे जो बुजुर्ग चले गए, जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, उन्होंने कहा था कि हमने अपना काम कर लिया, आगे आपको काम करना है। नेगी जी ने कहा कि आप आर0डी0जी0 बंद होने का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। हम विरोध क्यों करेंगे? हम भी हिमाचल के हित

की बात करेंगे परंतु आप यह भी देखिए कि देश के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां आर0डी0जी0 दी जा रही है और हिमाचल को अछूता छोड़ा गया है? लड़ाई तो यहां से शुरू होती है। जब 16वें वित्तायोग ने इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दिया, अब वित्तीय संकट से हम कैसे निकले, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। आर0डी0जी0 पर बहस करते रहने से कुछ नहीं होगा। यह तो आने वाली नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। हमें इस प्रदेश को अब किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत करना है उसके ऊपर चर्चा करनी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो यहां पर बजट अनुमान प्रस्तुत किए वे 54 हजार 928 करोड़ रुपये के थे। बजट के आंकड़ों के हिसाब से कहना चाहूंगा कि आपकी ही बजट बुक में लिखा गया है कि पिछले साल जो हमारा बजट था वह 58 हजार 514

25.03.2025/1520/केएस/वाईके/2

करोड़ रुपये का था जो लगभग 3586 करोड़ रुपये कम हुआ है। कहां हमें आगे की तरफ जाना चाहिए था और हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारा बजट घाटा है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करुंगा परंतु सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज हम इस प्रदेश को आगे कैसे ले जाएं? हमारी आय के साधन क्या हैं और उनके बाद हम इस प्रदेश में क्या खर्चा कर सकते हैं? सरकार के माध्यम से जो कुछ स्कीमें लाईं जाती हैं उसका हम हमेशा समर्थन भी करते हैं और बात भी करते हैं। बहुत से आंकड़े श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष ने रख दिए, रणधीर शर्मा जी ने रख दिए जो बजट बुक के अंदर ही थे परंतु कुछ आंकड़ों पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम जा कहां रहे हैं? यह प्रदेश कहां जा रहा है? अभी मैं पालमपुर की तरफ से आ रहा था, रास्ते में एक जगह बड़े-बड़े शब्दों में लिखा था कि प्रदेश में हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां दीं जाएंगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वे फट्टे अभी भी लगे हुए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में तो मिट गए हैं लेकिन कई जगह हाईवे पर वे फट्टे लगे हुए हैं। कम से कम उनको तो उतार दो। अब तो सवा या डेढ़ साल का सरकार का समय रह गया है। हमें पता है कि यह आपसे होने वाला नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। मैं गारंटियों की बात करना चाहता हूं। मैं कर्मचारियों की बात करना चाहता हूं। हम उनके विरोधी नहीं हैं परंतु आपने जो गारंटी दी, मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1525/av/ag/1

श्री अनिल शर्मा------- जारी

वर्ष 2021-22 में 46990 करोड़ रुपये का बजट था और उस वक्त हमने कर्मचारियों को 10907 करोड़ रुपये तनख्वाह में दिए। आज यह स्थिति है क्योंकि अभी तो बजट ऐस्टिमेशन पर है, वास्तव में नहीं है। हम बजट ऐस्टिमेशन में आज 14721 करोड़ रुपये कर्मचारियों को तनख्वाह के रूप में देने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम 5 वर्षों में कर्मचारियों को 7939 करोड़ रुपये अधिक दे रहे हैं। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जब पेंशन या ग्रेच्युटी की तरफ जाते हैं। जय राम ठाकुर जी ने इसलिए यह नहीं कहा कि हम ओ0पी0एस0 लागू करेंगे, इनको मालूम था कि ओ0पी0एस0 के माध्यम से प्रदेश के अंदर विकास रुक जाएगा और हम प्रदेश के विकास को गति नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपने तो करना था क्योंकि आपने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद इसे कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे। हम वर्ष 2021-22 में 6358 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में दे रहे थे। आज वह बढ़कर 11765 करोड़ रुपये हो गई जो हम पेंशन के रूप में दे रहे हैं। आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन पांच वर्षों में हमारी पेंशन की देनदारियों में कम-से-कम 5366 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इसमें सैलरी और पेंशन में कुल मिलाकर 9180 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मैंने पहले भी कहा कि हम कर्मचारियों के विरोध में नहीं हैं। परंतु क्या सरकार को अपने को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाना चाहिए था?

आप यहां बार-बार आर0डी0जी0 की बात करते हैं। मैं प्रदेश की आय की बात करना चाहूंगा। हमें प्रदेश की आय यानी हमें मिलने वाले राजस्व या नॉन टैक्स की चर्चा करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट एक्साइज के अंदर हमने 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि के रूप में कमाये हैं। मैं आपके ही आंकड़े पढ़ रहा हूं। आप इन आंकड़ों को खुद देखिए कि वर्ष 2023-24 का जो बजट ऐस्टिमेट है उसके अंदर आपने 2216 करोड़ रुपये की एवज में 2692 करोड़ रुपये अर्जित किए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने शराब के ठेकों में 475 करोड़ रुपये कमाये जिसका जिक्र मुख्य

मंत्री जी कर रहे थे। मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि श्री जय राम ठाकुर की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में उतना राजस्व नहीं कमाया

25.03.2026/1525/av/ag/2

जितना कि हमने एक वर्ष में कमा दिया। हम मानते हैं कि हमारी सरकार 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाती रही। अब आप वर्ष 2024-25 के असैस्मैंट के आंकड़े देखिए। वर्ष 2024-25 में पूर्व के अतिरिक्त 5.90 करोड़ रुपये की राशि ही अर्जित की है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की बात करें तो मात्र 957 करोड़ रुपये और वह भी दो वर्षों का बजट ऐस्टिमेशन है, अभी आपके पास फाइनल फिगर नहीं आई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम बातें तो बड़ी-बड़ी कर लेते हैं कि हम इस प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने जा रहे हैं। अगर आप इस प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने जा रहे हैं तो इसके लिए कोई रोड मैप तो होना चाहिए। यह सभी को पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से करने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्टेट गुड्ज टैक्स में भी मात्र 1395 करोड़ रुपये और वैट में 911 करोड़ रुपये की बढ़त हुई है। अगर हम इसका पूरा आंकड़ा देखें और नॉन टैक्स की बात भी करें तो उसमें भी हमारे कोई बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं।

हम पावर सेक्टर की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारे पावर सेक्टर में 1428 करोड़ रुपये थे और इस बार वित्तीय वर्ष 2026-27 में हमने बजट ऐस्टिमेशन में 2191 करोड़ रुपये लिए हैं। मेरे बोलने का मतलब यह है कि हम पांच वर्षों में मात्र 762 करोड़ रुपये ही अर्जित करने जा रहे हैं। हम पावर सेक्टर के विरोधी नहीं हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री सुख राम ने बहुत अच्छा कह दिया है और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि पावर मिनिस्टर ये भी रहे हैं और मैं भी रहा हूं। हम प्रदेश के हित की बात करते थे।

टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1530/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री अनिल शर्मा... जारी

हमारा लक्ष्य यह था कि पावर जनरेशन होनी चाहिए लेकिन लिटिगेशन से नहीं। उत्तराखंड हमारे साथ है। आप उत्तराखंड की पॉलिसी देखिए। ऐसा न हो कि प्रदेश की पॉलिसी के साथ लोग उत्तराखंड ही चले जाएं, वे 12 प्रतिशत लेते थे यानी 12, 18 और 20 प्रतिशत तक लेते थे, हम 12, 18, 30 प्रतिशत तक जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम इनके साथ हैं नेगोशिएशन करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ऊहल का पावर प्रोजैक्ट है उसमें 3000 करोड़ रुपये 100 मेगावाट के लिए लगे हैं और वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। रुपये आपकी जनरेशन कॉस्ट प्रति मेगावाट 30 करोड़ पहुंच गई। आप कहां बिजली पैदा कर रहे हैं? प्रदेश में बिजली के बहुत-सारे प्रोजैक्ट्स हैं, चाहे लारजी हो, ऊहल पावर प्रोजैक्ट हो या अन्य पावर प्रोजैक्ट्स हो। मेरे बोलने का मतलब है कि यदि हम स्टेट टैक्स की बात करें और अपने टैक्स की बात करें तो मात्र 5765 करोड़ की हमारी आय होती है, जबकि सैलरी और पेंशन में हमारी 9180 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मैं सरकार के सामने यह भी रखना चाहता हूं कि आपके पास सैलरी और पेंशन के खर्चे ज्यादा है और आपकी आय कम है। राज्य के अपने टैक्सिज केवल 5765 करोड़ रुपये हैं, जिसकी आप बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे? आपके सैलरी और पेंशन के खर्चे 9180 करोड़ रुपये हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप 3415 करोड़ रुपये डेफिसिट में चले गए। मेरे बोलने का मतलब है कि आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति अलग है।

अब मैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 22-23 में आप 4149 करोड़ रुपये रसीव करते हैं और 3190 करोड़ रुपये खर्चा होता है। आप वर्ष 23-24 में 4917 करोड़ रुपये रिसीव करते हैं और मात्र 3642 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। अगर आप इन वर्षों के फिगर देखें तो आप लगभग 5745 करोड़ रुपये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के खर्च नहीं कर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आ रहा है, वह भी पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है।

25.03.2026/1530/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना लाई है। मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पशुपालन विभाग मेरे पास भी रहा है। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। आपने कहा कि दूध का रेट 61 रुपये कर दिया परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी परिस्थिति क्या है? आपने कहा कि 4000 करोड़ से 8000 करोड़ तक कलेक्शन हो चुकी है। मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं और जानता हूं कि आज की परिस्थिति में एक लीटर पर लगभग 20 से 25 रुपये सरकार को वहन करना पड़ रहा है।, आपने वाइन की बोतन के ऊपर 10 रुपये सेस लगा दिया। आपको उससे 90 करोड़ से 140 करोड़ रुपये आमदनी हो सकती है । आप उसी से काम करना शुरू कर रहे हैं, परंतु आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके पास साधन नहीं हैं। चक्कर के प्लांट की जहां 50,000 लीटर क्षमता है, वहां 1 लाख लीटर से ज्यादा दूध आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्कीम को बुरा नहीं कह रहा हूं । दूध का रेट अगर आप 80 रुपये भी कर दे तो भी कम है क्योंकि दूध उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा है। परंतु हम इस लागत को किस तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह कोई हल्दी नहीं है, यह कोई सामान्य फसल नहीं है। जैसे ही दूध प्लांट में पहुंचेगा, अगर वह फट जाएगा तो उसका घाटा सोसाइटी को वहन करना पड़ेगा।

आज की परिस्थिति में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपने पिता जी का उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि वे वर्ष 1967 से 1972 तक इसी विभाग के मंत्री रहे। उन्होंने जो काम शुरू किए, उन्हें संचार क्रांति के लिए जाना जाता है। पंडित सुखराम जी को संचार क्रांति के मसीहा कहा जाता हैं

एन0एस0 द्वारा .... जारी

25-3-2026/1535/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री अनिल शर्मा----जारी

परन्तु उनके पास हमेशा जो विभाग रहे उनके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। वर्ष 1967 से वर्ष 1972 में इंडो जर्मन प्राजैक्ट के तहत जो चक्कर में प्लांट लगा था तो उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थीं तथा उस समय पहली बार जर्सी हॉस्टन गाय विदेशों से लाई गई थी। यहां पर पशुपालन मंत्री जी बैठे हैं और जब मैं स्वयं मंत्री था तो मैंने बड़े टाइम के बाद पालमपुर में जर्सी गाय और बैल इम्पोर्ट किए थे। एक प्रथा चली थी कि हमारे पास हाई यील्ड कहां से होगी? उसके लिए उन्होंने गांव-गांव में रोजगार के साधन पैदा करने की बात की। जैसे आप बात कर रहें हैं और मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में रोजगार कैसे पैदा हो, उन्होंने उसके लिए कार्यक्रम शुरू किया था। हमारे प्रदेश में उस समय केबल, ऑप्टिकल फाइबर बिछती थी और 100 किलोमीटर के लिए बाहर से ठेकेदार आते थे तो वहां उन्होंने हमारे नौजवानों को काम दिया। उन्होंने 2-2 किलोमीटर तक का काम नौजवानों को दिया और पी0सी0ओ0 बांट दिए। रोजगार के साधन पैदा करना सरकार का काम है। मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी भी शामिल हैं क्योंकि उस वक्त ये भी इसी लाइन में थे और पंडित सुख राम जी ने इनका पूरा समर्थन किया तथा जो इन्होंने कहा उसके लिए नौकरियों में भी प्रावधान किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने टेलीकॉम में काम किया तो उस वक्त भी वर्ष 1967 से 1972 तक इस लाइन के ऊपर काम किया। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं यहां पर दूध की बात कर रहा था कि हमारे 4 पार्लियामैंट हलके हैं। मैं इन हलकों की बात करना चाहता हूं। आप प्रोसैसिंग प्लांट कहां लगा रहे हैं? आप ढगवार में डेढ़ लाख लीटर केपेस्टिी का प्लांट लगा रहे हैं। वहां पर मात्र 21,000 लीटर की केपेस्टिी है। नाहन और नालागढ़ में 14,000 और 4,000 लीटर की केपेस्टिी है। आप कहां लगा रहे हैं? दत्तनगर में भी प्रोसैसिंग की केपेस्टिी 50,000 लीटर है। वहां 1.10 लाख लीटर कोलैक्शन हो रही है। हम कहते हैं कि आपने लाइन तो अच्छी चुन ली परन्तु आपको इस दूध को कहां ले जाना है। आप इसका पाउडर बनाने जा रहे हैं और पाउडर बना कर स्टॉक पड़ा रहेगा क्योंकि पाउडर नहीं बिकेगा और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस योजना को बड़े ध्यान से लागू किया जाए। यह

25-3-2026/1535/एन0एस0-ए0एस0/2

कोई लहसुन, प्याज या हल्दी नहीं है। It is a perishable commodity और इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप शराब पर सैस लगा कर कहते हैं कि हमने पैसे का प्रावधान कर दिया। आपने सैस 3 से 6 रुपये कर दिया और लोग सोसाटियां खुद चला रहे हैं तो 3 से 6 रुपये कर दिया। मैं कहता हूं कि आप उसको 15 रुपये कर दीजिए और 15 रुपये क्यों करें क्योंकि जब आप 25 रुपये लॉस पर जा रहे हैं तो सोसाइटी को ही 15 रुपये दे दें। उससे आपके पास दूध कम आएगा और उन सोसाइटियों के पास जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप इसकी कोस्ट उस तरफ दें। इससे आपका घाटा कम होगा। आप 25 रुपये लॉस की जगह यदि उसको 15 रुपये कर देंगे तो आपको ठीक रहेगा। यहां पर कहा जा रहा है कि हमने 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको 6 रुपये से 10-12 रुपये कर दो। दूध जितना कम आएगा उतना आपका घाटा होगा। जैसे मैंने कहा कि मण्डी पार्लियामैंट हलके में जहां हमारा चिलिंग प्लांट हैं वहां 2.10 लाख लीटर की कोलैक्शन है चाहे रामपुर के दत्तनगर और चाहे मण्डी के चक्कर की बात हो। कांगड़ा व हमीरपुर में 21,000 की कोलैक्शन है। शिमला में केवलमात्र 19,000 की कोलैक्शन है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हम मण्डी के लोगों को मुख्य मंत्री जी भूल गए हैं। मैं इस बजट बुक में देख रहा था कि इसमें केवल एक सेपू बड़ी का नाम आया है। मुझे लगा कि चलो कम-से-कम मण्डी का नाम तो आया चाहे सेपू बड़ी ही हो। हम सेपू बड़ी तक ही सीमित रहे।

अध्यक्ष : आप विकास की दृष्टि से पूरी तरह सेचुरेट हो गए हैं। इसलिए सेपू बड़ी रह गई है। मैं मानता हूं कि डवलपमैंट में सेचुरेशन कभी नहीं आती है। मैंने मान लिया और अपनी बात को विड्रो कर लिया।

श्री अनिल शर्माः मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब सत्ता आती है तो हम कुछ विधान सभा क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं। असली बात यह है। हम प्रदेश की तरफ नहीं देखते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो । यह दिखती बात है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.03.2026/1540/RKS/As-1

श्री अनिल शर्मा जारी.....

मैं इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। मैं यह बात सभी के लिए बोल रहा हूं। हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। प्रदेश में जहां जरूरत है, हम उसकी तरफ नहीं देखना चाहते। अभी माननीय खेल मंत्री जी यहां से उठकर चले गए। मैं भी खेल मंत्री रहा हूं। आप sports hub बना रहे हैं और हमें इसका कोई विरोध नहीं है। आप इसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च कर दीजिए, हमें कोई विरोध नहीं है। मैं तीन सालों से आपके पीछे पड़ा रहा। धर्मशाला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बिलासपुर और हमीरपुर में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। केंद्र में श्री अनुराग ठाकुर जी राज्य खेल मंत्री रहे हैं। मंडी के पड्डल मैदान में शिवरात्रि का मेला आयोजित किया जाता है। लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी आपकी बात सुनते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं तीन सालों से उनके पीछे पड़ा हूं। हमने लैंड भी ट्रांसफर करवा दी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फाइल मुख्य मंत्री को चली गई है। मैं वहां फाइल ढूंढता रह गया। मुख्य मंत्री कार्यालय से वह फाइल कहां गई, मुझे कहीं नहीं मिली। माननीय मंत्री के पास भी मुझे वह फाइल नहीं मिली। आपने कहा कि लैंड ट्रांसफर करेंगे, उसकी DPR बनेगी और फिर हम उसमें पैसा दे देंगे। मैंने इसकी DPR भी बना दी और लैंड भी ट्रांसफर करवा दी। मैं तीन साल इसी काम में धक्के खाता रहा लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि हम युवाओं को नशे से दूर ले जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नशा हमीरपुर और कांगड़ा में ही प्रचलित है? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि यह मैंने अपने पिता जी से सीखा है और उन्होंने कभी विकास में मतभेद नहीं किया। यह उनकी सोच थी। उनके पास डिफेंस प्रोडक्शन में काम था। वे राजा साहब के पास गए कि मुझे जमीन दे दो और मैं यहां फैक्टरी लगाना चाहता हूं परंतु कई बार राजनीति आड़े आ जाती है। राजनीति के दबाव में यदि हमें वह जमीन मिल जाती तो बहुत बड़ी फैक्टरी वहां पर लग सकती थी। उनकी सोच अलग थी। वह प्रदेश को हिस्सों में नहीं बांटते थे। जब संचार क्रांति की बात आई तो उन्होंने यह नहीं देखा कि घंटी मंडी में ही बजेगी। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उठकर बाहर चले गए हैं। वे उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की

बात करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम मंडी जोन हॉस्पिटल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे लेकिन हमारे वहां पर एक रेडियोलोजिस्ट तक नहीं है। फिर वह अस्पताल उत्कृष्ट कैसे हो गया? क्योंकि मैं जानता हूं वहां एक नेत्री

25.03.2026/1540/RKS/As-2

है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसी के कारण रेडियोलोजिस्ट वहां आते और बदलते रहते हैं। यह कैसी सरकार है? क्या इस सरकार में हम यह देखते रहेंगे कि किसी एक को फायदा देने के लिए कभी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगा दी जाए और कभी उसका ट्रांसफर कर दिया जाए? क्या यह सरकार इसी तरीके से चलेगी? उन्होंने अपनी दो-तीन लैब्स खोली हैं। हमें इस बात का गम नहीं है लेकिन अध्यक्ष जी, हमें दुःख इस बात का होता है कि लोगों ने हमें भी चुनकर यहां भेजा है। मैं वर्ष 1993 से राज्य सभा और विधान सभा में बैठा हूं। लोग हमें काम से जानते हैं। मैंने यहां पर कई लोग देखे हैं जो बड़े-बड़े भाषण देते थे। वे बड़ी-बड़ी बातें करते थे लेकिन अगली बार यहां नहीं पहुंचे। वे वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लोग आपकी पहचान आपके काम से करते हैं। माननीय खेल मंत्री जी यहां आ गए हैं। आप नौजवान मंत्री हैंलेकिन आपने मुझे नचा-नचा कर बुरा हाल कर दिया है। मैं वर्ष 1993 में यंग मंत्री बन गया था। तब मेरे सिर पर बाल थे लेकिन आपके सिर में बाल नहीं हैं पर यह अलग बात है। माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी यहीं बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम हर शहर के अंदर vending zone बनाएंगे। यह अच्छी बात है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत मैंने की है। मैंने पार्किंग और वेंडिंग जोन के ऊपर काम किया है। मैं आभारी हूं ठाकुर जय राम जी का कि इन्होंने इस काम की शुरुआत की। उस वक्त किसी कारण से यह कार्य बंद रहा परंतु मैंने अब मुख्य मंत्री से बात करके दो करोड़ रुपये लाकर एक शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था और वेंडिंग जोन पर काम शुरू करवाया है। जैसे चंडीगढ़ में व्यवस्था है उसी तर्ज पर हम अपने शहरों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम शहरों के अंदर इस दिशा में प्रयास करें क्योंकि लोग गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करते हैं। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात कर रहा था। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोटली स्वास्थ्य संस्थान को भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान घोषित कर दिया है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1545/बी.एस./ए.एस.-1

श्री अनिल शर्मा जारी...

मैंने कहा कि जोनल हॉस्पिटल कोटली में बना दो। उन्होंने कहा कि बना दिया। अब यह पूछा जा रहा था कि डॉक्टर कितने हैं। बताया कि आपके डॉक्टर्ज की संख्या 6 है, पर लगे कितने हैं, बोले कि चार हैं। मैंने ये उत्कृष्ट वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगे कहां-कहां कृपया बता तो दीजिए। फाइलों में पता नहीं ये काम कहां अटक जाते हैं। नोटिफिकेशन के बाद भी इस सरकार में कागज ढूंढने का काम बड़ा खतरनाक है। कई बार मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि बुरा लगता है, अभी आपकी बहुत सी चीजें हैं इसलिए मैं अचीवमेंट की बात करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी जो कह रहे थे, उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य यह होना चाहिए कि पावर जेनरेशन समय पर हो। हम पावर जेनरेशन पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास इसके बहुत साधन हैं।

यहां टूरिज्म की भी बात हुई है और कई विषय हैं। आदरणीय बिक्रम जी इस पर अपनी बात रखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट दिशाहीन लगता है, खोखला है क्योंकि आय के साधन नहीं हैं और आप गारंटियां पूरी करने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम 1500 रुपये देंगे। किसको देंगे, एक लाख लोगों को, अरे भाई, मत दो इसका क्या फायदा है। आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास साधन हैं। यहां साधनों की कमी है और जनता में वही बात कही जाए जो वास्तव में काम पूरे हो सकें। हमने भी 125 यूनिट बिजली दी। हमने पानी भी फ्री कर दिया। इसलिए इन बिंदुओं को देखते हुए, मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, कुमारी अनुराधा राणा जी चर्चा में भाग लेंगी। It is up to me to decide कि कौन सा स्पीकर कब बुलाना है। अभी तो और भी बोलने वाले माननीय सदस्य आने वाले हैं।

25.03.2025/1545/बी.एस./ए.एस.-2

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, जो बजट वर्ष 2026-27 के लिए मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 21 मार्च को पेश किया गया था। आपकी अनुमति से मैं उस बजट के संबंध में अपने विचार रखना चाहती हूं और इसमें मैं स्वयं को शामिल करती हूं, मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, लगभग 54,928 करोड़ रुपये का यह बजट इस पटल पर पेश किया है। यदि हम इससे पिछले बजट से तुलना करें, तो यह लगभग 3,500 करोड़ रुपये कम का बजट है। यह कम क्यों हुआ है, इसे सदन के सभी सदस्य और प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है। हमारा बजट समय के साथ बढ़ना चाहिए था लेकिन इसमें कटौती क्यों हुई है? आर0डी0जी0 पर पहले भी तीन दिन का विशेष सत्र आयोजित हो चुका है और उसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। यहां कहा गया कि आर0डी0जी0 17 राज्यों की बंद हुई है और यह कोई हमारा सवैंधानिक अधिकार नहीं है। मैं यह पूछना चाहूंगी कि आर0डी0जी0 की जो ग्रांट मिली थी इसका उल्लेख साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) में इसका स्पष्ट प्रावधान है। उस समय के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को हमें नमन करना चाहिए। उन्होंने यह समझ लिया था कि कुछ राज्य भौगोलिक दृष्टि से कठिन होंगे, जिनके राजस्व के साधन सीमित होंगे। उनके आय-व्यय की खाई कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसी को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहा जाता है नाम से ही स्पष्ट तौर पर जाहिर हो जाता है। आपके रेवेन्यू में जो डेफिसिट है उसके लिए ग्रांट का प्रावधान प्रथम वित्त आयोग 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग तक, यह ग्रांट लगातार 17 राज्यों को मिलती रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। लेकिन 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में इसे शून्य कर दिया गया। जब हम इसके प्रभाव की बात करते हैं 17 राज्यों में ज्यादातर प्रभावित राज्यों में नागालैंड के बाद दूसरे नम्बर पर हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है। हिमाचल के बजट पर इसका लगभग 12.7 प्रतिशत का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। जब हम बजट का 100 रुपये का

आकलन करते हैं, तो उसमें से लगभग 20 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च होता है। यदि इसमें भी 12.7 प्रतिशत की कटौती होगी तो हम विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। यह एक गंभीर प्रश्न है। आज हम कह रहे हैं कि आर0डी0जी0 17 राज्यों में बंद कर दी गई है,

Speaker: Please Order in the House. Hon'ble Members please take your seats.

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1550/DT/DC-1

कुमारी अनुराधा ठाकुर जारी....

यह मैं इस सदन के माध्यम से विपक्ष के से जरूर पूछना चाहूंगी क्या आज हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हो गई है; क्या राज्य का रेवेन्यू डेफेसिट बिल्कुल कम हो गया या जीरो हो गया है? फिर ऐसे क्या कारण है कि प्रदेश की आर0डी0जी0 बंद दी गई है? मुझे स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता है की एक टारगेट के रूप में हिमाचल प्रदेश की सरकार को निशाना बनाया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रस की सरकार है इसलिए हिमाचल प्रदेश से भेदभाव किया गया है और संविधान मं जिस संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया है कहीं-न-कहीं उसे बुरी तरह कमजोर करने का प्रयास किया गया है, ऐसा कहने में मुझे कोई अतिश्योक्ति भी नहीं है और यह मेरा निजी विचार भी है। पूरे प्रदेश की जनता भी केंद्र सरकार के इस बरताव को समझ रही है। इस प्रकार के आर्थिक संकट में भी मान्य मुख्यमंत्री महोदय जी ने जिस प्रकार का बजट यहां पेश किया है हम उनके विजन की सराहना करते और उनके नेतृत्व को सलाम करते हैं। इस पहाड़ी प्रदेश का मुख्य मंत्री होने के नाते उनका साहस भी पहाड़ जैसा है उनका साहस अक्सर उनके शब्दों में भी नजर आता है- वही साहस बजट बुक में भी नजर आ रहा है।

जब बजट बुक में किसान का उल्लेख होता है, पशुपालक का उल्लेख होता है, गरीब का उल्लेख होता है तो मन को एक तसल्ली मिलती है। क्योंकि हम भी ऐसे ही परिवेश से निकल कर आज विधायक के रूप में विधान सभा में बैठे हुए हैं। हमें खुशी मिलती है कि सरकार उस गरीब तबके के बारे में सोचती है जिसे पहले अनदेखा किया गया। हमारी सरकार समाज के समाज के उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है जिसके बारे में कोई

नहीं जानता और कोई उसकी समस्याओं को नहीं समझता। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अपने संबोधन में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हमें खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस दिशा में भी कदम उठाया और उसकी शुरूवात अपने आप से की। उन्होंने अपने वेतन में 50% और माननीय डिप्टी सीएम साहब के वेतन में 30 से 40% की कटौती और साथ ही साथ माननीय मंत्रीगणों विधायकगणों जितने भी अध्यक्ष है या जितने भी हमारे प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया दिया है आगे आने वाले समय में देंगे यह कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही इतिहास में लिखा जाएगा कि जब इस तरह की वित्तीय

25.03.2026/1550/DT/DC-2

परिस्थितियां थी तो सभी एक होकर इसमें सभी ने इसका समर्थन भी किया और हिमाचल के साथ खड़े रहे। आर0डी0जी0 को बंद करना, मुझे लगता है कि यह एक भेदभाव है जो हिमाचल के साथ किया गया है और इसका प्रभाव हम पूरे बजट में तो देख ही रहे साथ ही साथ जो ट्राइबल का हमारा टी0ढ0डी0पी0 के अंतर्गत जो बजट होता है उसमें भी हम इसका प्रभाव देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी जब से हमारी सरकार बनी है हम लगातार आपदाओं का सामना करें चाहे 2023 की आपदा हो चाहे 2025 की आपदा हो। हजारों करोड़ का नुकसान 2023 की आपदा में हुआ। केंद्र सरकार की जो टीम स्पेशल टीम जो आई थी उसी ने यहां के नुकसान का आकलन किया जो 10000 करोड़ से ज्यादा का था। उसमें जो हमें पी0डी0एन0ए0 ने के तौर जो सहायता राशि मिली है वह दो वर्ष बाद मिली है यानी 2025 में जाकर वह राशि मिली और उसमें भी सिर्फ 2000 करोड़ की जो है घोषणा हुई थी। 2000 करोड़ में 1500 करोड़ के अंदर सरकार ने देना था और 500 करोड़ जो है राज्य सरकार ने देना था हमें खुशी है वह मिल चुका है। लेकिन जब जख्म हरा होता है तभी मलहम लगाया जाए तो ठीक रहता है और जख्म नासूर बन जाए तो उस मलहम का कोई फायदा नहीं होता। जब 2025 में प्रदेश में आपदा आई तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं हिमाचल का दौरा किया। उन्होंने प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये के विशेष राहत

पैकेज की घोषणा भी की। लेकिन यह बहुत दर्भायपूर्ण है कि अभी तक भी वह पैसा प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री जी बात पत्थर पर लकीर के समान होना चाहिए पर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक वह राशि प्रदेश के लिए जारी नहीं की गई है। मेरा इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? आजकल इस प्रकार की भेदभाव की राजनीति हमारे सिस्टम में हावी हो गई है। आज कई प्रदेशों में चुनी हुई दूसरी विचारधारा की सरकारों को टारगेट बनाया जा रहा है। केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है-प्रदेश में रोटेशन में भाजपा-कांग्रेस की सरकार बनती रही है पर इतिहास में इस तरह का भेदभाव कभी नहीं किया गया।

बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है चाहे वह महिला वर्ग है, चाहे हमारा किसान वर्ग है, चाहे वह गरीब वर्ग है या अनाथ बच्चों की हम बात करें- यह सोच मंख्य मंत्री जी मुख्य मंत्री पर की शपथ लेने के बाद ही दिखा दिया था। मैं समझती हूं कि आने वाले समय में उन्हें स्टेट्समेंन का दर्जा दिया जायेगा। क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चों के बारे में सोचा जिनका कोई नहीं था और राज्य ही उसकी माता-राज्य उसका

25.03.2026/1550/DT/DC-3

पिता, यह एक बहुत बड़ा वाक्या है जो इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा कि मुख्य मंत्री के द्वारा किस प्रकार की सोच अनाथ बच्चों के प्रति रखी गई थी। यदि मैं लाहौल स्पिति के परिपेक्ष्य में बात करूं और जब हम आपदा की बात करते हैं, आपदा में वर्ष 2023 व वर्ष 2025 में हजरों-करोड़ का नुकसान हुआ। इससे पहले घर बनाने के मुआवजा राशि एक से डेढ़ लाख तक मिलती थी। इसमें भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई और राज्य सरकार ने अपने स्पैशल पैकेज के रूप में 4500 करोड़ रुपये का पैकेज प्रभावित लोगों को दिया और प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 से 8 लाख रुपये की राशि दी ।
श्री0एन0जी0द्वारा जारी..

25.03.2026/1555/एच.के.-एन.जी./1

कुमारी अनुराधा राणा..... जारी

यह पहली बार हुआ कि जिन लोगों के घर चले गए, उन्हें किराये पर रहने के लिए भी स्पेशल किराये का प्रावधान किया गया। हमारे करपट गांव के निवासी, जहां पर बाढ़ का बहुत खतरा था, उन्हें टेंट्स में रहने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें भी किराये के लिए 5-5 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलने थे, वह मिल चुके हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने हर पहलू से इस चीज़ को समझा कि अगर कोई किराये पर रह रहा है तो हम उसकी मदद कैसे करें। हमने देखा कि सरकार की यह भी घोषणा थी कि जिन लोगों के घर तबाह हो गए, जिनकी जमीन चली गई, उन्हें हम 2 व 3 बिस्वा जमीन देंगे। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि उसमें सुधार क्यों नहीं हो पाया है। जहां पर सरकार के पास अपनी गवर्नमेंट लैंड है, वहां पर तो लोगों को घर बनाने के लिए जमीन दे दी गई है। परंतु हिमाचल का अधिकांश क्षेत्र फॉरेस्ट लैंड है। मैं पहले भी कहती रही हूं कि पहाड़ हमारा, जंगल हमारा, लेकिन कानून हमारा नहीं है। जब हम राजस्व की बात करते हैं, तो हमारे पास है क्या? हमारे पास बहता हुआ सोना— जिसे हम पानी कहते हैं और दूसरा हमारे जंगल व पहाड़ हैं। लेकिन उनमें हमारा अपना कोई कानून और अधिकार नहीं है। किसी भी जमीन को अगर हमें डायवर्ट करना है, चाहे फॉरेस्ट रिजर्व से बाहर या नॉन-फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए, तो हमें एफ0सी0ए0 में जाना पड़ता है। इस माननीय सदन में इस एक्ट में संशोधन करने हेतु एक सरकारी विधेयक लाया गया था और इसे सदन से पारित भी किया गया था। लेकिन यह भी दुःख की बात है कि आज तक इसमें संशोधन नहीं हुआ है। हमारे हिमाचल से सात सांसद चुने जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी इस विषय पर अपने विचार रखने चाहिए कि वे हिमाचल के हितों के कितने हितैषी हैं।

25.03.2026/1555/एच.के.-एन.जी./2

हमारा आर0डी0जी0 जीरो हो गया और हमें बाकी राज्यों से क्या लेना है? बाकी राज्यों का अपना राजस्व है। वे इंडस्ट्रियल और प्लेन स्टेट हैं, वहां पर उनके राजस्व पर

आर0डी0जी0 का असर केवल 2 या 3 प्रतिशत पड़ता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में लगभग 13 प्रतिशत असर पड़ रहा है। इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे सांसद महोदय को भी संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ऐसे लोग जिनकी जमीन चली गई, जिनके घर चले गए, जिनके पास कुछ नहीं बचा और जो टेंट्स में रहने को मजबूर हो गए, आज भी उन्हें हम जमीन नहीं दे पा रहे हैं। यह इतनी बड़ी बात नहीं है और इसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन इस विषय पर संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे सके।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं लाहौल-स्पीति के लिए बजट की बात करूं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करती हूं क्योंकि लाहौल-स्पीति के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उल्लेख बजट में किया गया है। खास तौर पर मौथभावा सड़क, जो स्पीति और किन्नौर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, उसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई है। हेलीपोर्ट्स की बात की गई है और इनके बनने से जनजातीय क्षेत्रों को बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही हर्बल गार्डन और म्यूज़ियम को अपग्रेड करने की भी बात हुई है। इन सभी के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करती हूं। पर्यटन क्षेत्र में लाहौल-स्पीति क्षेत्र को आगे ले जाने की बात भी हुई है। मैं यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ हो गया है, क्योंकि यह सब चीजें रातों-रात नहीं होतीं। यह सामूहिक प्रयास (कलेक्टिव एफर्ट) से ही संभव होता है। मुझे भी लगभग डेढ़ साल का समय पूरा हो चुका है और मुख्य मंत्री जी तथा माननीय मंत्रिगणों के आशीर्वाद से कई प्रोजैक्ट्स को लागू करने में हम सफल हुए हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख जरूर करना चाहूंगी।

25.03.2026/1555/एच.के.-एन.जी./3

हमारे स्पिति में लगभग 75 करोड़ रुपये की राशि से इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। यह माइनॉरिटी डिपार्टमैंट की स्कीम के तहत हुआ है। इसकी अंतिम स्वीकृति केंद्र

सरकार से मिलती है लेकिन जिला व राज्य के माध्यम से ही इसका प्रपोज़ल बन कर केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और खेल मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर आगे भेजा और हमें इसकी स्वीकृति मिली। इसका कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्पिति व काजा के क्षेत्र में 8 करोड़ रुपये की राशि से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होना है। केलांग टाउन की सीवरेज स्कीम, जोकि लगभग 30 वर्ष पुरानी योजना है, उसके लिए 26 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसका कार्य टेंडरिंग स्टेज में है और जल्द ही शुरू हो जाएगा। टाबो व काजा के लिए भी सीवरेज स्कीम की धनराशि स्वीकृत हुई है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और कारगा मार्केटिंग यार्ड का कार्य भी लंबे समय से लंबित था। इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। नाबार्ड के अंतर्गत मेरी तीन योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनकी लागत लगभग 30—40 करोड़ रुपये है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। नाबार्ड की सीलिंग की सीमा 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री का विशेष धन्यवाद करती हूं। स्पीति के लिए 25 करोड़ रुपये पर्यटन की दृष्टि से स्वीकृत हुए हैं, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की जब हम कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की बात सबसे प्रमुखता से होती है। चाहे हम डिबेट की बात करें या प्रैस रिपोर्टर हमसे कोई सवाल करें या किसी भी राज्य व जिले की स्थिति का आंकलन करना हो, तो हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही चर्चा करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री व माननीय मंत्रिगणों का धन्यवाद करती हूं कि हैल्थ व एजुकेशन सिस्टम के बारे में विस्तार से सोचा गया। इसको सबसे

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1600/एच0के0/ए0पी0/-01

कुमारी अनुराधा राणा जारी .....

सुप्रीम प्रायोरिटी के रूप में आगे रखा गया। हम देखते हैं कि ट्राइबल जिला में पहले, ट्राइबल जनजातीय ज़िलों को कैसे आंका जाता था। जनजातीय जिला तो ऐसे होते थे जैसे मान लो वहां पर कुछ नहीं है, न आपके पास शिक्षा की सुविधाएं हैं और न ही आपके पास हेल्थ सुविधाएं हैं। पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक भी डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट या कोई डॉक्टर, हमारे ज़िले में तैनात नहीं था। आज के समय में पांच से छः स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाहौल-स्पिति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अल्ट्रासाउंड भी पहली बार हमारे जिले में हो रहा है नहीं तो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए भी दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। स्पिति वालों को शिमला आना पड़ता था, लाहौल वालों को कुल्लू या अन्य ज़िलों में जाना पड़ता था। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। एजुकेशन की दृष्टि में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुए हैं। इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मेरे लाहौल-स्पिति जिले के लिए भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में से तीन स्कूल सैंक्शन हुए हैं। इसके अलावा दो स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड घोषित किया गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसके कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफ़ी चेंजेज़ आएंगे और मुझे लगता है कि गरीब लोगों के बच्चे हैं भी अब अच्छे स्कूल और अच्छे इनवायरनमेंट में पढ़ाई कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा जब हम पॉलिसी की बात करते हैं। ट्राइबल में एफ0आर0ए0 और नोतोड़ की बात होती है। जिसके लिए माननीय जनजातीय विकास मंत्री जी ने अपने संबोधन में भी आज नोतोड़ की बात कही है। एफ0आर0ए0 में एक साल में बहुत बेहतरीन कार्य हुआ। पिछले पांच सालों में पांच-से-दस पट्टे जहां मिले थे, आज एक साल के भीतर लगभग सौ-से-डेढ़ सौ पट्टे लाहौल-स्पिति ज़िला के अंतर्गत लोगों को मिले हैं। एफ0आर0ए0 हमारे लोगों का सबसे बड़ा अधिकार है। जिससे ज़मीनों का अधिकार डायरेक्टली हमारे लोगों को मिलता है। नोतोड़ के लिए भी माननीय मंत्री महोदय जी ने बहुत प्रयास किए। आठ बार वे स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय से मिले। इस बीच हमें भी

उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु किसी कारणवश, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोतोड़ नियम बहाल नहीं हो पाया। जबकि राज्यपाल महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोतोड़ नियम को बहाल कर सकते थे। वर्तमान में प्रदेश के नये राज्यपाल महोदय आए हैं। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि नोतोड़ नियमों को भी बहाल किया जाए और नोतोड़ की वजह से आज हमारे लोगों को ज़मीन का अधिकार मिला है वह वर्ष 1968 के नोतोड़ नियम के तहत मिला है। अगर यह नियम भी बहाल होगा तो इसमें हमारे लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। साथ-ही-साथ मैं यह नहीं कहूंगी कि हमने सब कुछ कर दिया है या हमने एक साल में, डेढ़ साल में सब कुछ कर दिया। जितना भी हम कलेक्टिव एफर्ट से कार्य करते हैं, उसमें सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रीगणों का आशीर्वाद रहता है तो उसको हम अमलीजामा ज़रूर पहना सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बजट बुक में अच्छी लगी कि इसमें क्लाइमेट चेंज के विषय पर बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लाइमेट चेंज के लिए या जो हम डिजास्टर मिटिगेशन की बात करते हैं किसी भी तरह के डिजास्टर में इसकी स्टडी के लिए स्पेशल बजट का, स्पेशल यूनिट का, इस बार बजट बुक में उल्लेख किया गया है कि सभी 12 जिलों के लिए किया जाएगा और इसमें क्लाइमेट चेंज को स्टडी किया जाएगा। ये शायद पहली बार है, जब क्लाइमेट चेंज के लिए भी इतना सीरियसनेस दिखाया गया है। आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज है। जिसकी वजह से इतनी आपदाएं आ रही हैं। हम देख रहे हैं हर वर्ष आपदा आ रही है। आप देखिये किसानों के माथे पर शिकन अभी से है कि वर्ष 2026 की बरसात न जाने क्या लेकर आए? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की आपदा न आए। परंतु इस तरह जो हम बजट में हम देख रहे हैं कि यह एक संतुलित बजट है और हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं इसमें भी कुछ एक मांगें ज़रूर रखना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हम देखते हैं कि हेल्थ में डायलिसिस यूनिट या केमोथेरापिक यूनिट नहीं है और यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किडनी के पेशेंट हर जिले में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूगी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री महोदय

जी इसमें ध्यान दें और साथ ही साथ इसके लिए प्रयास करें। हमारे जनजाति जिला में जनसंख्या कम होने के

25.03.2026/1600/एच0के0/ए0पी0/-03

कारण तीन नई पंचायते बनी हैं, इसके लिए भी मैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। मेरी कुछ मांगे है माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं चाहूंगी कि इन पर पुनः विचार किया जाए। हम देख रहे है कि विधायक निधि में कटौती हुई है।

अध्यक्ष : मांगे नहीं सुझाव।

कुमारी अनुराधा राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगी क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि विधायक निधि विधायक के अपने खर्चों के लिए नहीं है। वह निधि हमारे लोगों के लिए है जिनके लिए हम कोई भी छोटा या बड़ा काम करते हैं। चाहे वे रास्तें, ढंगे या युवक मण्डल के कार्य हो, यह पैसा उसके लिए खर्च किया जाता है। इसमें जो कटौती हुई है, इसके लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए। अगर विधायक निधि में भी कटौती होती है तो विधायकों को भी लोगों के बीच काफी संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात जो ट्राईबल के लिए हमारा न्यूकिलस बजट होता है, जो हमें सब-डिविजन वाईज दिया जाता है। इसमें मेजर वर्क का 45:15 का एक विजिट होता है। इसमें भी मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और जनजातिय विकास मंत्री जी से विशेष निवेदन रहेगा कि इसमें भी किसी प्रकार की कोई कटौती न हो, क्योंकि हमारे सभी कार्य इन्हीं के माध्यम से होते हैं। हम जैसा देख रहे हैं कि मेजर हैड्स में काफी ज्यादा कटौती होने वाली है। परन्तु यह कुछ हैड्स हैं जिससे हमारे कई कार्य हो पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूं आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। अंत में, मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और यह कहना चाहूंगी कि यह बजट सभी वर्गों के लिए सोचा गया बजट है। आने वाले समय में हमने कैसे आत्मनिर्भर बनना है, रातों रात तो हम आत्मनिर्भर बन नहीं पाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1605/AT/YK/01

कुमारी अनुराधा राणा जारी...

कलेक्टिव एफर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात करनी चाहिए, यह अत्यावश्यक है।

मैं माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने जो बात कही कि हमें अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन करना चाहिए और उसमें एक्सपर्टीज को शामिल करके इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए क्योंकि अभी जो हालत है, जो विकट परिस्थितियां हैं, उन्हें संभालने के लिए हम सबको, जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा गया है, हमारा दायित्व बनता है कि हमें हर चीज़ को साइड में रखकर हिमाचल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस बारे में सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी कि वे भी थोड़ा दिल बड़ा रखें हमारे हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जह हिन्द।

Speaker : Thank you very much. After listening to some of the young MLAs, the first term and the second term MLAs, I am thinking to revive the Best Parliamentarian Award from this year. That is for the best parliamentary debate by the first term and second term MLAs and the presence in the House. The best presence will also be awarded as the second prize. The Best Reporting, the Press Gallery, which is usually vacant, the best reporting award will also be given and revived because I am the recipient of the Best Parliamentarian Award, Shri Mukesh Agnihotri ji, is the recipient of the Best Reporting, and Smt. Asha Kumari, was the Best Attendance Awardees. So, I

25.03.2026/1605/AT/YK/02

am thinking to revive this award. In view of the discussions and in view of some of the members' debate, which are very reasoned debate, which I have seen. Anuradha ji, you could have requested the Government of India, if you don't want to revive the RDG for the whole of the state, at least for the tribal area, which is a part of that constitutional provision. अब कुमारी अनुराधा राणा जी के बाद माननीय सदस्य बिक्रम जी, आप बोलना चाहेंगे या फिर माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार को बुला लूं? अगर आप मुख्य मंत्री जी से पहले बोल लें तो बेहतर है।

25.03.2026/1605/AT/YK/03

अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री लोकेन्द्र कुमार जी।

श्री लोकेन्दर कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 मार्च, 2026 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान यहां प्रस्तुत किया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

Speaker : Let us be very brief and be specific.

श्री लोकेन्दर कुमार : जी सर। जब आदरणीय मुख्य मंत्री जी बजट को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने दूध को लेकर बात कही थी और कहा था कि आनी में बहुत दूध उत्पादन होता है और वास्तव में होता भी है। लगभग एक लाख लीटर दूध हमारा जो दतनगर का प्लांट है, वहां पर करसोग, आनी, रामपुर, ठियोग, गरोड़ू, सिराज, रिकोंगपियो आदि क्षेत्रों से करीब 94,600 लीटर दूध आता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना है और यहां से अपनी बात रखनी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का, उन मातृशक्ति का, उन महिलाओं का, उन किसान महिलाओं का, जिन्होंने उस दौर के अंदर उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। जब आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार रही और जब दतनगर प्लांट की क्षमता बढ़ाने

के लिए पैसे दिए गए, मंडी के चक्कर प्लांट के लिए पैसे दिए गए। आज दतनगर का प्लांट 50,000 लीटर क्षमता का बना हुआ है। लेकिन वहां पर लगभग एक लाख लीटर दूध आता है। अभी आदरणीय अनिल शर्मा जी ने भी यह बात कही कि उस प्लांट की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया जाए और साथ-ही-साथ प्लांट पर जो रिक्त पद चल रहे हैं, उन्हें भी भरा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि जो इस बजट में कहा गया है कि दूध पर एम0एस0पी0 61 रुपये हुआ है और 51 रुपये की बात पहले की गई है। बिल्कुल ठीक है कि 61 और 51 रुपये की बात हुई है। लेकिन मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं कि अगर दूध की फैट 3.3 है और एस0एन0एफ0 7.3 होगी, तो आपको दूध का रेट मिलेगा 30.57 रुपये। और अगर आपकी दूध की फैट

25.03.2026/1605/AT/YK/04

4.7 होती है और अगर आपका एस0एन0एफ0 7.8 होता है तब आपको 51.18 रुपये का रेट मिलेगा। जो दूध की फैट है ...(व्यवधान) सुन लीजिए, मैं काम की बात कर रहा हूं। जिसमें 51.18 रुपये रेट मिलेगा, यह जो एम0एस0पी0 (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) की बात हो रही है, जैसे हम बात करते हैं कि किसान सेब की फसल का रेट खुद तय करेगा।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1610/केएस/वाईके/1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी ---

महिला किसान खुद रेट तय करेगी। अब यह एम0एस0पी0 मुझे किस पर मिलेगा? यह मुझे 5.5 फैट पर मिलेगा या एस0एन0एफ0 का 8.5 पर मिलेगा? ये दोनों अलग-अलग हैं। मुझे बताएं कि किस तरह से वह 5.5 आपका फैट रहेगा? इसमें नीचे बहुत दिक्कत है। मैं

आपको आपके जनवरी का रेट बता देता हूं। मेरे आनी के इलाके में रेट 41 रुपये से ऊपर नहीं गया है। सबसे कम रेट 35.77 रुपये सेरी पनेओ सोसायटी को मिला है । आप स्पष्ट रूप में बताएं कि अगर आपकी डिग्री और फैट इतने-इतने होंगे, तब आपको 61 रुपये रेट मिलेगा। बजट में घोषणा हुई है कि 61 रुपये मिलेगा परंतु मिलेगा किसको? क्योंकि महिला किसान दिन-रात मेहनत करती हैं, इस बात को भी देखना पड़ेगा। वे सुबह से शाम तक, बरसात और बर्फ में गाय की सेवा में लगी रहती हैं और उनको हर परिस्थिति में घास लाना ही पड़ता है। उनको गाय को चोकर भी और फीड भी खिलानी पड़ेगी। आपको यह क्लीयर करना पड़ेगा कि ये 61 रुपये के हिसाब से रेट किन लोगों को मिलेगा?

दूसरे, जितना मैंने इसको पढ़ा, स्टडी किया, चोकर के ऊपर आपकी सब्सिडी नहीं है। चोकर आपको पशुपालन विभाग की ओर से इन सोसायटियों को देनी चाहिए। आपके पास गाय का एस0एन0एफ0 कैसे बैढ़ेगा, डिग्री कैसे बढ़ेगी? उनको कैल्श्यिम भी खिलाना पड़ेगा, कुछ और चीजें भी देनी पड़ेंगी, प्रोटीन भी खिलानी पड़ेगी केवल घास खिलाकर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। इन चीजों के ऊपर भी आपको ग्रामीण स्तर पर काम करना पड़ेगा और गांव-गांव के अंदर केम्प शुरू करने पड़ेंगे। जब मैं जिला परिषद में था, मैं तब से दूध के रेट के लिए लड़ रहा हूं। पूरे निरमंड ब्लॉक के अंदर हमारे यहां सिर्फ खरगा ऐसी सोसायटी है जहां पर सैक्रेटरी ने गाड़ी के अंदर ही एनालाइज़र लगाया हुआ है। वे हर दिन के रेट को बताते हैं कि इतना रेट है और वहां की महिला किसानों को सही रेट मिल रहा है परंतु और जगह दिक्कत है। मैं यहां से यह भी मांग करना चाहता हूं कि सभी सोसायटियों को एनालाइज़र दिया जाए और प्रतिदिन का रेट किसानों को बताया जाए कि आज का आपको इतना रेट मिला है। उसकी पर्ची मिलनी चाहिए। हो क्या रहा है कि दत्तनगर से रेट आनी, जहां उनका मिल्क कलैक्शन सैंटर है वहां पर आ रहा है। वहां से जब सोसायटी वाले पैसे को

25.03.2025/1610/केएस/वाईके/2

डिस्ट्रिब्यूट करते हैं फिर वह किसानों को एवरेज रेट लगा रहे हैं। इसीलिए मेरी मांग है कि प्रत्येक सोसायटी को एनालाइज़र मिलना चाहिए और उसका सही उपयोग होना चाहिए।

साथ ही साथ महिलाओं की सहायता के लिए केम्प शुरू होने चाहिए कि किस तरह से गाय के दूध में गुणवत्ता आएगी। अध्यक्ष महोदय, पिछली जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय दत्तनगर में जो दूध बच जाता था उसकी दही बनाई जाती थी। आज दही बनना बंद हो गया है। हमें उत्पाद के ऊपर भी जाना पड़ेगा। नहीं तो दूध ज्यादा हो जाएगा तो किसानों को फेंकना पड़ेगा। उसको फेंकना नहीं है, उसका उत्पाद बनाना चाहिए। विभाग ने मेरे प्रश्न के एक जवाब में बताया था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह शायद वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट है, मुझे बताया गया था कि चम्बा, इंदौरा, जसवां-प्रागपुर, बैजनाथ, कांगड़ा, धर्मशाला, शाहपुर, सुलह, नदौन, कुटलैहड़, हरोली, चिंतपुरनी, गगरेट में 18,227 लीटर दूध आता है। वहां पर 200 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट लगाया गया है। वह लगना चाहिए अच्छी बात है। लोग आत्मनिर्भर होने चाहिए तभी हम यहां पर जीतकर आएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे आनी को या शिमला जिला का जो हमारा इलाका है जहां से दूध आता है, किन्नौर, सिराज या करसोग से भी दूध आता है, वहां पर भी इस तरीके का प्रोजैक्ट लगे जहां पर प्रोडक्शन बने, मिठाइयां बने, दही बने, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा था, उसके ऊपर स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि आदरणीय चेयरमैन साहब ने आनी में भाषण दिया कि किसानों से 20 लीटर से ज्यादा दूध नहीं लिया जाएगा। आप इसको भी स्पष्ट करें क्योंकि जब से सरकार ने 61 रुपये अनाउंस किए हैं, तभी से नहीं, मेरे आनी में बहुत पहले से लोग दूध के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको क्लीयर करना होगा कि आप 20 से ज्यादा लीटर दूध भी पैदा कर सकते हैं और उसको मिल्क फैड में बेच सकते हैं क्योंकि दूसरी प्राइवेट एजेंसियां भी आनी के अंदर लगभग 1 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1615/av/ag/1

श्री लोकेन्दर कुमार------- जारी

अभी विचार किया जा रहा है कि महिला किसान जो दिन-रात मेहनत कर रही हैं उनके खाते में डायरैक्ट पैसा जाए ताकि बीच में सचिव इत्यादि जो गलत काम कर रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। महिला किसानों को उनका मेहनताना मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने स्पेसिफिक बोलने के लिए कहा तो मैं स्पेसिफिक ही बोलूंगा। मैं इस बजट के बारे में बहुत कुछ लिख कर लाया हूं परंतु अभी बोलने के लिए समय नहीं है। यहां पर जैसे माननीय सदस्या सुश्री अनुराधा राणा कह रही थी कि हमें भी ट्राइब्ल इलाकों में प्रभाव पड़ा है। मैं अनुसूचित जाति के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर जैसे कि कहा गया था कि नौतोड़ दिए गए थे। वर्ष 1972 में नौतोड़ दिए गए थे, अच्छी बात है उस समय सही लोगों को मिले होंगे। यहां पर सत्ता पक्ष से माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू कह रहे थे कि 10-10 कनाल भूमि भी मिली है। लेकिन मुझे अभी भी पिछली बरसात के दौरान हुए नुकसान के बारे में एक फोन आया था। मैंने पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ तो उसने कहा कि मेरे पास केवल 7 बिस्वा जमीन है और घर के अंदर दरारें हैं। मैंने पूछा कि इसके अलावा आपके पास कितनी जमीन है तो उसने बताया कि केवल एक बीघा जमीन है और हम दो भाई हैं। इसलिए ये नौतोड़ किन लोगों को मिली, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उस समय कौन लोग थे और कौन बड़े लोग भूमि के मालिक बने हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट से अनुसूचित जाति के लोगों को भी धक्का लगा है और उनके लिए शुरू की गई योजनाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी के अंदर पहले सौर ऊर्जा की सौ-दो सौ लाइट्स आती थीं परंतु वह अभी तक हमें नहीं मिली है। पिछले विधायक ने वह बांटी हैं इसलिए अब लोग हमसे उसके बारे में पूछते हैं। उसका कारण यही है कि हमें पहले से कम बजट दिया गया।

मैंने पशु पालन विभाग के बारे में पहले बात कर दी है कि इस विभाग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? मेरे विधान सभा क्षेत्र के पजेन्डा नामक स्थान पर श्री जय राम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में वेटरनेरी होस्पिटल खोला और उसका काम भी

शुरू हो गया था। निरमण्ड ब्लॉक के अंतर्गत वहां सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं। वह पजेन्डा गांव बागीपुल के साथ है। अस्पताल का कार्य वहां बिल्कुल रोड के साथ शुरू हो गया था लेकिन आज वह बंद है। यदि आज गाय, भेड़-बकरियां बीमार होती हैं तो उनको चैक करवाने की वहां कोई सुविधा नहीं है। पिछली बरसात में वहां बहुत सारी भेड़-बकरियों और दूसरे पशुओं की खरोग बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। हमारे बांशा के वेटरनेरी होस्पिटल को बंद कर दिया गया। वहां पर जाबू और बांडी डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसके बारे में एक बार अवश्य विचार करें कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश तथा आउटर सिराज़ को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है तो बाकी चीजों के साथ-साथ प्रदेश में पशु पालन पर भी ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में भी बात की गई है। मैंने कल भी जीरो आवर के माध्यम से अपना विषय उठाया था कि पर्यटन में क्या-क्या दिक्कते हैं। हमारे बागीपुल-बागसराहन एक बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे पास शरशाह-मरगी और टक्करासी है। कल मेरे से मंत्री जी बात भी कर रहे थे। शोजा, सरयोल्सर और पनेऊ है। ये सब स्थान हैं परंतु कुछ लोग वहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा केवल तीर्थन वैली से बशल्यो जोत होते हुए सिर्फ बागसराहन के लिए दिया जाए। मैं यहां से मांग करना चाहता हूं कि हमारी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। हमारे नेशनल हाईवे 305 की हालत खराब है। यहां पर आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं। इनका आनी और बंजार के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। नेशनल हाईवे 305 की डी0पी0आर0 इन सब लोगों ने बनाई है और वह सब्मिट हुई है, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी काम किया जाए ताकि हमारा पर्यटन जो बंजार से जीभी तक आता है। जीभी में रहने के लिए सिर्फ होम स्टे हैं परंतु वहां पर्यटक सरयोल्सर झील, माता बूढ़ी नागिन का मंदिर, रघुपुर गढ़ के अंदर पांडू रोपा, टक्करासी और पनेऊ देखने को आते हैं। पण्यो रैस्ट हाउस में हमारे स्व0 प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु भी ठहरे हैं। यह रैस्ट हाउस उस दौर का है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर उन चीजों को भी जोड़ा जाए।

टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1620/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री लोकेन्दर कुमार... जारी

सिर्फ टूरिज्म के नाम तक ही बात सीमित न रहे। मेरे वहां पर रघुपुर गढ़ में जो मेरे युवा साथी हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने रघुकुल जलोड़ी के नाम से कार्य शुरू किया है। मैं माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी की बातों से सहमत हूं कि वहां पर कुछ नीले-पीले कलर के तिरपाल लगाए गए हैं लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि कुछ अनुदान दिया जाए। वहां के युवाओं को ही वहां पर काम करने के लिए प्राथमिकता दी जाए। कोई बड़ी पार्टी आकर इस तरीके का काम न करे, पहले स्थानीय लोग रोजगार दिया जाए और हमारे लोगों को बेरोजगार न किया जाए, यह मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं एक-दो इम्पोर्टेंट बातें रखना चाहता हूं। मैं आंकड़े इसलिए रख रहा हूं सर, क्योंकि मैंने बार-बार इस हाउस में यह विषय उठाया है। आज फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 10 लोगों को अभी तक वह पैसा नहीं मिला है सर, जिनके घर के सदस्य की मृत्यु हो गई, उन्हें भी भुगतान नहीं हुआ। ग्रीन गो कंपनी के तहत शिमला डिस्ट्रिक्ट के 33 लोगों को पैसा मिल गया है और उपायुक्त, शिमला उस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन आनी के लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन लोगों को भी जल्द-से जल्द भुगतान किया जाए क्योंकि वे अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, नशे का विषय बहुत गंभीर है। कुल्लू और आनी विधान सभा क्षेत्र में यह बड़ी समस्या बन चुकी है। अभी वॉकथॉन चल रहा है और सरकार प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रही हैं। बच्चों को भी इससे जोड़ जा रहा है। यह अच्छी पहल है लेकिन जब तक महिला मण्डल और सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक जमीनी स्तर पर उनके बीच जाकर काम नहीं होगा तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। मैं विधायक बनने के बाद से लगातार चिट्टे के खिलाफ बोल रहा हूं। मेरे क्षेत्र में एक युवक अरेस्ट हुआ और एक युवक जिसकी इसमें संलिप्तता थी, उसकी ओवरडोज

से मृत्यु हो गई। यह सबको पता है कि इसका धंधा कहां से चल रहा है, यहां तक कि पुलिस को भी इसकी जानकारी है।

25.03.2026/1620/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नशे को लेकर जो एस0आई0यू0 बनाई गई है उसमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। एस0आई0यू0 में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत लंबा हो गया है। 6-7 वर्षों से वे लोग उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। एस0आई0यू0 में बदलाव जरूरी है क्योंकि यह कहीं-न-कहीं भ्रष्टाचार का माध्यम भी बनता जा रहा है। जिन लोगों को संरक्षण दिया गया है, उनमें से भी कुछ लोग खुद संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। वे भांग, चिट्टा और लकड़ी बेचने व मर्डर के केस में जेल गए हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए और नई टीम बनाई जाए। साथ ही सर, वर्दी पर जो विश्वास जनता का होता है, उसी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आनी विधान सभा क्षेत्र में आउटर सिराज के अंदर 'लोकल न्यूज ऑफ इंडिया' के 3 पत्रकारों में से सर्व दयाल जी के साथ मारपीट की गई। इसका कारण यह था कि उन्होंने डी0एस0पी0 की वीडियो बनाई जिसमें डी0एस0पी0 सरकारी बाढ़बंदी की तारें अपने घर ले जाते हुए दिखाई दिए। जब रामपुर में केस चला तो उस को भी दबाने का प्रयास किया गया । आज तक उस डी0एस0पी0 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि पत्रकारों को ही प्रताड़ित किया गया। मैं आग्रह करता हूं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आउटर सिराज, आनी विधान सभा क्षेत्र जिसकी छाती को चीरकर 2-2 बड़े प्रोजैक्ट बने हैं। जिनमें लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट 210 मेगावाट और रामपुर हाइड्रो प्रोजैक्ट 412 मेगावाट का है। ये सारे प्रोजैक्ट्स आउटर सिरज के अंदर लगे हैं और सिर्फ मिट्टी शिमला जिला में रखी गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शिमला जिला को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए लेकिन जहां नुकसान हुआ है, वहां के लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। इसके आउटर सिराज के पहाड़ों को काटा गया। वहां के पानी का उपयोग किया जा रहा है और नुकसान स्थानीय लोगों का नुकसान भी हुआ है लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से यह भी

कहना चाहूंगा कि लूरी हाइड्रो प्रोजैक्ट की टनल दोबारा बैठ गई, टनल फट गई और इसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। इतना समय बीत जाने के बावजूद भी कार्य आगे नहीं बढ़ रहा। यह कहा जा रहा है कि बरसात आ गई और इस

25.03.2026/1620/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

तरह के बहाने लगाकर काम डैफर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है जिन लागों की जमीनें गई उन्हें भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।

अंत में अध्यक्ष महोदय, एक कविता सुनाना चाहूंगा जो इस प्रकार से है :-

आउटलेट की घाटियों में इतिहास आज भी गाता है।
शांगरी के राजा रघुबीर सिंह जी की गूंज हर पत्थर दोहराता है।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

25-3-2026/1625/एन0एस0-ए0एस0/1
श्री लोकेन्दर कुमार----जारी

देवभूमि की इस धरती पर, आस्था का सागर बहता है,
जहां श्रीखंड महादेव का धाम, हर मन को पावन करता है,
जलोड़ी जोत की ठंडी हवाएं, रघुपुर गढ़ की ऊंची छांव,
देश-विदेश से लोग यहां आते हैं,
पर सुविधाओं का आज भी अभाव पाते हैं,
माता बुढी नागिन मंदिर की पावन छाया में,
आने को आतुर है यात्री अनेक,
देश-विदेश से लोग कदम बढ़ाते,
भक्ति का दीप जलाते,
पर टूटी-फूटी, संकरी इन सड़को को देख,
उनके हौंसले डगमगाते।
आउटर सिराज की धरती दूध उगाए,

प्रदेश का हिस्सा 30 प्रतिशत लाए,
पर मेहनत करने वाली माताएं,
अपने हक के पैसे को तरस जाएं,
पनेऊ की वादियों में गुंजती यादें,
जब जवाहर लाल नेहरु जी भी यहां आए,
विकास के सपने संजोए इस धरती ने,
पर आज भी वो सपने अधूरे रह गए।
इतिहास समृद्ध, संस्कृति महान,
फिर भी क्यों पिछड़ा आउटर सिराज
सरकार की अनदेखी पर दबा,
आउटर सिराज का हर अरमान
उठेगी एक दिन यह आवाज जरूर,
गूंजेगी पहाड़ो से भरपूर,
जो हक है मेरे आउटर सिराज आनी की धरती का
वो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा जरूर।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, जय आउटर सिराज।

25-3-2026/1625/एन0एस0-ए0एस0/2

Speaker : Thank you very much. Shri Lokender Kumar ji, good speech. You have to improve your rhythm little bit. राजस्व मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हर विधान सभा सत्र में अपने इलाके की बात उठाते हैं, अच्छी बात है लेकिन ये जो 10 लोग बता रहे हैं जिनको घर क्षतिग्रस्त होने के पैसे नहीं मिले हैं तो इन्होंने कभी सप्लीमेंटरी में नहीं कहा कि मेरे क्षेत्र के 10 लोग भी हैं। यह अभी कहना और सप्लीमेंटरी में नहीं कहना तो यह बात कुछ ठीक नहीं लगी।

25-3-2026/1625/एन0एस0-ए0एस0/3

अध्यक्ष : माननीय लोकेन्दर कुमार जी आप राजस्व मंत्री जी को पूरी सूचना दे देना। अब श्री मलेन्द्र राजन जी चर्चा में भाग लेंगे। मैंने Best Parliamentarian award की घोषणा कर दी है इसलिए अब यह कंपीटिशन है this between the first term and second term MLAs. I am also hearing it and first and second term MLAs will be considered for the award.

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर जी द्वारा पहला भाषण इस विधान सभा में दिया गया, मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2026-27 का बजट यहां प्रस्तुत किया, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। हमें यह आजादी एक दिन में नहीं मिली, लाखों-करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, उन्होंने संघर्ष किया तब जाकर मिली। हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन वर्ष 1857 में शुरू हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में एक फैसला लिया गया और पूरे देश के लाखों देशवासियों ने उसका समर्थन किया और महात्मा गांधी जी के पीछे चले। अल्टीमेटली 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, अगर आज के परिपेक्ष्य में हम बात करें तो बहुत से हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनको अलग-अलग योगदान के लिए जाना जाता है। अगर हम आज

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.03.2026/1630/RKS/As-1

श्री मलेन्द्र राजन... जारी

भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो आजादी के बाद हमारे देश में बहुत से निर्वाचन आयुक्त रहे हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हमारी आज की युवा पीढ़ी को इसका पूरा ज्ञान नहीं है। उन लोगों को उनके फैसलों के कारण जाना जाता है। आज अगर टी0एन0 शेषन का नाम आता है तो उन्हें सब लोग जानते हैं। आजादी के बाद इस देश में बहुत से निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इसी संदर्भ में अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जब से हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया यहां पर भी इस आसन को बहुत से माननीय अध्यक्षों ने सुशोभित किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो फैसला वर्ष 2024 में इस विधान सभा में लिया, मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां आपको युगों-युगों तक याद रखेंगी कि आपने किस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा की थी। जब वर्ष 2024 में इतनी बड़ी राजनीतिक आपदा प्रदेश के अंदर आई तो आपने अपने फैसलों से लोकतंत्र की रक्षा की और इस बात को हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सी बातें हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा कही गईं। हमारे सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने भी काफी बातों का जिक्र किया है। मैं आपके समक्ष इस बजट पर बोल रहा हूं। मैंने अपने देश की बात की, आजादी के आंदोलन की बात की। हमारे विपक्ष के साथी जिस विचारधारा के लोग हैं इन्होंने हमेशा विरोध करने का काम किया है। चाहे हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रहा हो या हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने का समय, इस विचारधारा के लोग इसके विरोध में खड़े रहे। इस विधान सभा के अंदर ही यह जिक्र हुआ कि 'स्टेटहुड मारो ठुड'। इस विचारधारा के लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। आज हमारे ऊपर केंद्र सरकार द्वारा जो कट लगाए जा रहे हैं, हमारी जो आर0डी0जी0 बंद की जा रही है उसमें मैं समझता हूं कि ये लोग हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति दोषी बनते जा रहे हैं। विपक्ष का काम सरकार के फैसलों के लिए सकारात्मक सुझाव देना होता है। यह कहना कि यह सारा

25.03.2026/1630/RKS/As-2

बजट झूठ का आंकड़ा है, आंकड़ों का मायाजाल है, तर्कसंगत बात नहीं है। यह बात हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हजम नहीं होगी। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना तर्कसंगत नहीं है। हमारे विपक्ष के साथियों को इस बात को समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की यह धरती देवी-देवताओं की धरती है। यहां के लोग भोले-भाले जरूर हैं लेकिन हर बात को बड़ी बारीकी से परखते हैं, जांचते हैं और समझते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया है उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बहुत सी योजनाएं आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। विशेषकर समाज के उस कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो निर्णय लिया है उसके परिणाम आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक होंगे। युगों-युगों तक उनके इन निर्णयों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जैसे महात्मा गांधी जी ने उस समय 'भारत छोड़ो आंदोलन' चलाया तब उन्होंने यह नहीं सोचा था कि हम सफल होंगे या असफल लेकिन उन्होंने इसका निर्णय लिया। उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और हम सफल हुए। उसी प्रकार आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो निर्णय प्रदेश की आम जनता और कमजोर वर्गों के लिए इस बजट के माध्यम से लिया उसके परिणाम भी आने वाले समय में निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरे देश का एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, वे निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1635/बी.एस./ए.एस.-1

श्री मलेन्द्र राजन जारी...

आज की तारीख में मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किए हैं वे सराहनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया। अगर दूध की बात की जाए, कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, दूध के बारे में यहां पर जिक्र आया। निश्चित रूप से हमारा जो इंदौर विधान सभा क्षेत्र है वह किसानी पर आधारित क्षेत्र है। लोग अपनी मेहनत करके, चाहे दूध का कारोबार है, चाहे फसल का कारोबार है, चाहे गेहूं का कारोबार है, चाहे धान का कारोबार है और गन्ने का कारोबार है। फतेहपुर से भाई भवानी जी यहां पर बैठे हैं, चाहे फतेहपुर का विधान सभा क्षेत्र है और चाहे इंदौर का विधान सभा क्षेत्र है। आज इस बजट में गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया गया और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में यह आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इसमें मैं मुख्य मंत्री जी से और कृषि मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी यहां पर बताई गई है उसमें एक कैपिंग लगाई जाए। ऐसा भी न हो कि दूध का कारोबार कोई एक व्यक्ति बड़े स्तर पर कर रहा हो और अन्य व्यक्तियों को उसका फायदा न मिले। यदि एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा गाय और भैंसे रखी होंगी तो दूसरे व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसमें कैपिंग तय की जाए। जो दूध हमारे मिल्क फेडरेशन द्वारा लिया जाएगा यह निर्धारित हो। इससे अधिक से अधिक किसानों और दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा।

इसके अलावा यहां पर दूध का कलेक्शन बताया गया कि प्रदेश में 4 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 8 करोड़ लीटर हुआ है। मैं समझता हूं कि यह भी हमारे दूध उत्पादकों के लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए जिनका कार्य 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका उनके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

25.03.2025/1635/बी.एस./ए.एस.-2

भेड़पालकों के लिए 100 रुपये प्रति किलो ऊन की खरीद की जाएगी। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी काफी लोग इस

समुदाय से आते हैं। हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है और अदरक का न्यूनतम मूल्य पहली बार 30 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, हमारे इंदौर और फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में गन्ने की काफी फसल लगाई जाती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि गन्ने पर भी सब्सिडी दी जाए, ताकि हमारे किसानों को भी लाभ मिल सके। जैसे पंजाब के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में 60 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं वैसे ही हमारे किसानों को भी मिले। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गन्ना मिल नहीं है और हमारा गन्ना पंजाब जाता है। वहां के किसानों को 60 रुपये सब्सिडी ज्यादा मिलती है। मेरा अनुरोध है कि हमारे किसानों को भी इसमें सब्सिडी दी जाए।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, चिट्टे को लेकर प्रदेश में जागरूकता अभियान चल रहा है। हमारा विधान सभा क्षेत्र भी बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस अभियान को चलाया, जिसके सकारात्मक परिणाम प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले अगर मैं वर्ष 2017-22 की बात करूं तो लगातार वहां आये दिन वहां पर युवाओं की लाशें मिलती थी।

(सभापति श्री संजय रत्न जी पदासीन हुए।)

लेकिन उस पर मुख्य मंत्री जी ने पिछले 3 सालों में काफी अंकुश वहां पर लगाया है और वॉकोथोन के माध्यम से युवाओं को जागरुक किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका भी लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, इस बजट में विभिन्न कर्मचारियों, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के वेतन में वृद्धि की गई है। हेल्थ सेक्टर में भी वृद्धि की गई है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

25.03.2025/1635/बी.एस./ए.एस.-3

अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो वर्ष 2017-22 तक, मैं अपने इंदौर विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। हमारा सिविल अस्पताल इंदौरा और सिविल अस्पताल गंगथ है, सिविल अस्पताल इंदौरा में पांच साल

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1640/DT/DC-1

श्री मलेन्द्र राजन जारी...

पूर्व सरकार के समय सिविल हस्पताल इन्दौरा में अम्बुलैंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने अपने संबोधन में फतेहपुर हस्पताल का उल्लेख किया था। हमारे सिविल हस्पताल इन्दौरा को माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया है। आज 8 डाक्टर्ज वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें 6 स्पैशलिस्ट डाक्टर्ज हैं। इसका सीधा लाभ वहां के गरीब और आम आदमी को मिल रहा है। आज अम्बुलैंस की सुविधा वहां पर है। इस हस्पताल का नया भवन भी बनकर तैयार हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री के आगामी प्रवास के दौरान उसको जनता को समर्पित कर दिया जायेगा।

हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप-मुख्य मंत्री जी इस सदन में विराजमान हैं। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में शाह नहर सिंचाई परियोजना, जो एक बहुत बड़ी परियोजना है हमारे क्षेत्र को दी गई। पहले जो शाह नहर का डिवीजन कार्यालय था वह वहां से 50 किलो मीटर दूर संसारपुर टेरेस में था। उस डिवीजन को हमारी सरकार के द्वारा बडुखर में शिफ्ट किया गया जिसका सीधा लाभ श्री भवानी सिंह पठानिया जी के विधान सभा क्षेत्र को और इन्दौरा विधान सभा के लोगों को मिलेगा। इसके लिए भी मैं उप-माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने अपने संबोधन में स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी को बहुत याद किया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इनको उनकी याद आती है।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)

जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की बेटी, हमारी बहन, उनकी शादी थी तो इन्हीं की सरकार प्रदेश में थी और इन्हीं के लोगों के द्वारा उनके घर पर ई0डी0 का छापा डलवाया गया। यह ऐसा समय था जब स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज इनको वे बहुत याद आ रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति को प्रदेश की जनता भली-भांती समझती है।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र इन्दौरा की बात करूं इसका मैं समय-समय पर जिक्र करता भी रहता हूं कि वहां पर बाढ़ के कारण बहुत

नुकसान हुआ है। चाहे मैं वर्ष 2023 या वर्ष 2025 की बात करूं वहां पर प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता आया है। इसके संबंध में मैंने इस सदन में प्रश्न भी लगाया था तो मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि शाह नहर में प्रोटैक्शन का कार्य, अगर पूरी प्रोटैक्शन नहीं हो सकती तो कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करके जहां-जहां से पानी कि पेनिट्रेशन हो रही, उन स्थानों को प्रोटेक्ट किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जल जीवन मिशन के द्वारा बनाए गये रेस्ट हाउसिज का जिक्र आया। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश में चाहे वह सराज विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र हो, वहां पर बहुत से रेस्ट हाउसिज बनाए गये। मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जल जीवन मिशन में एक रेस्ट हाउस बनाया गया। यह रेस्ट हाउस शमशान घाट के अंदर बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ निजी तौर पर लाभ लेने के लिए उस रेस्ट हाउस को बनाया गया और आज वह रेस्ट हाउस एक सफेद हाथी पालने की तरह हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता भोली-भाली जरूर है लेकिन अंजान नहीं है। हिमाचल की जनता हर बात को भली-भांती समझती है और सच और झूठ का अंतर

जानती है और उसे पहचानती भी है। सियासत में शोर मचाना बहुत आसान होता है परंतु काम करके दिखाना बहुत मूश्किल होता है। आज एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति प्रदेश का मुख्य मंत्री है। हमारे मुख्य मंत्री को प्रदेश के लोगों के लिए काम करने की जिज्ञासा है और प्रदेश को आगे ले जाने की जिज्ञासा है पर हमारे विपक्ष के साथी उसमें लगातार अड़ंगा अड़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका नुकसान जो प्रदेश को हो रहा है वह तो ही रहा है लेकिन विपक्ष के साथियों को इसका ज्यादा नुकसान होगा। आज प्रदेश में सड़के बन रही हैं तो वे इसका विरोध कर रहे हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.03.2026/1645/एच.के.-एन.जी./1

श्री मलेन्द्र राजन..... जारी

आज हर एक चीज़ में इनका विरोध हो रहा है। आज अगर प्रदेश के अंदर सड़कें बन रही हैं, तब ये विरोध कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर अगर अस्पतालों का हेल्थ सिस्टम सुधर रहा है, तब इनका विरोध है। माननीय श्री रोहित ठाकुर, जोकि हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री हैं, आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार आगे आकर अच्छे कार्य कर रही है और क्रांतिकारी कदम उठा रही है, जिसका सीधा फायदा हमारे गांवों में बैठे गरीब लोगों तक पहुंचेगा, तब भी इनका विरोध है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र के भी तीन स्कूल सी0बी0एस0ई0 किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से यह भी कहना चाहता हूं कि जब इनकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रदेश की सारी समस्याएं वर्ष 2022 के बाद ही शुरू हुई हैं। उससे पहले तो पूरा प्रदेश जैसे स्वर्ग था और प्रदेश में कोई समस्या नहीं थी। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग प्रभु श्री राम का नाम जगह-जगह लेते हैं लेकिन कभी श्री राम जी के साथ सीता माता का नाम भी ले लिया कीजिए। ये

लोग श्री राम जी को सीता माता से अलग क्यों करते हैं? इनकी यह विचारधारा मुझे समझ में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका लास्ट पंच अच्छा था और अब समापन कीजिए।

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप लगातार समाप्त करने के लिए कह रहे हैं इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास के नए काम शुरू किए हैं, नई योजनाएं भी शुरू की हैं और लोगों को सुविधाएं देने का काम भी किया है।...(घण्टी)... लेकिन विपक्ष को हमारे इन तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किए गए विकास कार्य दिखाई नहीं देते, उन्हें केवल राजनीति दिखाई देती है।

25.03.2026/1645/एच.के.-एन.जी./2

मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हर बात का विरोध करना लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ राजनीति है। अगर विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो सरकार सुनने के लिए तैयार है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री बार-बार आग्रह भी करते हैं। लेकिन जनता को गुमराह करने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता भोली जरूर है, लेकिन समझदार है। वह काम करने वालों के साथ खड़ी है और केवल विरोध करने वालों को समय आने पर जवाब जरूर देगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे देर से ही सही लेकिन पूरा समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूरा 20 मिनट का समय दिया गया है। आपने अच्छी स्पीच दी है। अब मैं माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।

25.03.2026/1645/एच.के.-एन.जी./3

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 21 मार्च, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया है। मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विरोध क्यों कर रहा हूं, वह तथ्यों पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट सिकुड़ता हुआ बजट है और महंगाई के दौर में पीछे की चाल चल रहा है। वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान 58,514/- करोड़ रुपये का था और अब यह घटकर 54,928/- करोड़ रुपये हो गया है। यानी इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले 3,586/- करोड़ रुपये की कटौती की गई है। बजट उल्टा सिकुड़ता जा रहा है और माननीय मुख्य मंत्री इसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रोटी छोटी करके उसके डाइट प्लान कहना, सुधार नहीं

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1650/एच0के0/ए0पी0/-01

श्री बिक्रम सिंह जारी .....

यह मजबूरी है। अगर कोई घरवाला कम खाना खाने लगे तो पड़ोसी बोलते हैं कि बेचारा तंगी में है। कोई उसे लाइफस्टाइल चेंज नहीं कहता। यह बजट तंगी है और इसे कविताओं की चादर में, इस तंगी को लपेटकर पेश किया गया है। बार-बार कहा जाता है कि हमारा प्रदेश 90 हज़ार करोड़ की इकोलॉजिकल सर्विसेज देता है। जंगल कार्बन सोखते हैं,

नदियां उत्तर भारत को पानी देती हैं, हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में जो 90 हज़ार करोड़ की संपत्तियों की बात की जाती है, उसमें से क्या कभी एक प्रतिशत भी भुनाने की कोशिश की गई है; क्या कभी कोई राज्य स्तरीय कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग हुई है, नहीं हुई है; कोई ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, नहीं किया है; नीति आयोग को कोई पारिस्थितिक मुआवजा या फ्रेमवर्क भेजा है? नहीं भेजा है; अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के लिए कोई प्रयास किया है? नहीं किया है; और क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कोई स्टडी करवाई गई है? अगर करवाई भी गई है तो वह फाइलों में दबी है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास सोने की खदान है और उसके ऊपर बैठकर ग़ालिब पढ़ने लगते हैं "यह शासन नहीं है यह प्रकृति के नाम पर शिकायत चिट्ठी है।" राजस्व घाटा 6,577 करोड़ रुपये का है यानि राजस्व प्राप्ति 40,361 करोड़ रुपये है और खर्चा है 46,938 करोड़ रुपये और घाटा 6,577 करोड़ रुपये का है। हालात यह है कि बिना उधार के कुछ नहीं चल सकता और अब तो समस्या यह हो गई है कि हम उधार ले भी लें तो भी प्रदेश का गुजारा नहीं होता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में ‘डेब्ट ट्रैप’ की बात की है कि जो कर्ज की वापसी और जो उस पर ब्याज चुकाना अब सालाना उधार की सीमा से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब कर्ज चुकाने के लिए भी पूरा कर्ज हमें नहीं मिल रहा है। इस बजट में हमें कर्ज से बाहर निकलने के लिए कौन-सी ठोस योजना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। बीमारी तो बता दी गई है लेकिन दवाई कहां है? यह तो वैसा हाल है जैसे किसी मरीज को डॉक्टर कहे कि तुम्हें जानलेवा बीमारी है और जब मरीज ने डॉक्टर से पूछे कि इसका इलाज क्या है तो डॉक्टर साहब ने सामने से शेर सुना दिया। क्या शेर सुनाने से मरीज ठीक हो जाएगा? यह बीमारी

25.03.2026/1650/एच0के0/ए0पी0/-02

आपने अपने आप तैयार की है। आपने सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की भोली-भाली जनता को गारटिंयों के नाम पर ठगने का काम किया है। क्या तब आपको याद नहीं आया जब आप कहते थे कि 1500 रुपये हर महिला को दिये जाएगें, केबिनेट की पहली मिटिंग

में 5 लाख नोकिरयां दी जाएंगी। एक साल में एक लाख नौकरी और पांच सालों में पांच लाख नौकरियां दी जाएंगी। उस समय आपको नजरी नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शेर सुना कर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। यह बीमारियां हम सब लोगों ने अपने आप पैदा की हैं। वर्ष 1905 में भूकंप आया, वर्ष 2023 में आपदा से इतनी तबाही हुई। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो कर्मचारियों की तनख्वाह को रोक रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि 50 प्रतिशत उनका, 30 प्रतिशत मंत्रियों का, विधायको का भी 20 प्रतिशत तनख्वाह काट कर लगा दिया चुना। इसके अतिरिक्त ग्रुप-ए और ग्रप-बी के अधिकारियों को भी तीन प्रतिशत वेतन डेफर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमें बताइए कि माननीय मुख्य मंत्री जी तो चाहें सौ प्रतिशत न लें

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1655/AT/YK/01

श्री बिक्रम ठाकुर जारी....

गाड़ी सरकारी, मकान सरकारी, रोटी सरकारी आपको कुछ भी न मिले तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने जो किया है वह ठीक नहीं किया है। वह ठीक आपने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आर्टिकल-300A (संपत्ति का अधिकार) के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों ने यह स्पष्ट किया है कि सैलरी और पेंशन भी संपत्ति का अधिकार है जिसे किसी व्यक्ति से बिना कानूनी अधिकार के बिना नहीं छीना जा सकता।

आर्टिकल-21 के तहत आजीविका का अधिकार है और वेतन का स्थगन आजीविका के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद-360 के दौरान ही राष्ट्रपति को राज्यों को वेतन और भत्ते कम करने का निर्देश देने की विशेष शक्ति होती है। आपने कौन-सी शक्ति का प्रयोग किया? आपने तो संविधान का उल्लंघन किया है। आप किस कैपेसिटी में इन सब चीज़ों का एलान कर रहे हैं? यह हो नहीं सकता और यह संविधान का सरेआम वायलेशन है। आप कभी कहते हैं कि मैं प्रदेश को वर्ष 2027 में

आत्मनिर्भर कर दूंगा और आप इधर तनख्वाह देने में कटौतियों की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि प्रदेश को वर्ष 2032 तक सबसे अमीर राज्य बना दूंगा। आपके पास कौन-सी जादू की छड़ी है? क्यों आप लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं? मैं तो यह कहता हूं कि इस सदन के अंदर हमारा भी लंबा समय हो गया है। इस प्रकार से असत्य बोलते हुए हमने कभी कोई मुख्य मंत्री नहीं देखा होगा। सबसे ज्यादा असत्य बोलने वाले मुख्य मंत्री हैं ...(व्यवधान) अभी तक तो छोटी सी बात की है, टीका तो अभी लगना है, ठहरो तो सही अभी ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट बिक्रम जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री रह चुके हैं। क्या चीज़ असत्य बोली है, यह ज़रूर बताएं।

25.03.2026/1655/AT/YK/02

अध्यक्ष : असत्य कर दिया है।

मुख्य मंत्री : नहीं, असत्य भी क्या बोला? मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि हम प्रदेश को वर्ष 2032 तक समृद्धशाली प्रदेश और अमीर राज्य बनाएंगे तो यह सत्य है। कैसे सत्य है, यह मैं बताता हूं। पहले आपको 11,000 करोड़ रुपये आ0डी0जी0 मिलती थी, हमें वह आ0डी0जी0 3,200 करोड़ रुपये मिली। फिर भी प्रदेश चल रहा है, विकास की गति तेज हो रही है। विकास की गति आंखों से नज़र नहीं आ रही है, घूमकर देखने पर नज़र आएगी, विरोध करने से नज़र नहीं आएगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह कहना कि सबसे असत्य बोलने वाले मुख्य मंत्री हैं, यह शब्द इनका बोलना अच्छा नहीं लगता।

अध्यक्ष : मैंने वह शब्द बदल दिया है।

मुख्य मंत्री : निकाल तो दिया, पर मैं यह कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि हमने ये गलत काम किया, यह सत्य है और यह असत्य है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी।

श्री बिक्रम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, कैसी-कैसी बातें करते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आप अपनी बजट बुक्स खोलिए पिछले तीन वर्षों की और देखिए कि उन तीन वर्षों में आपने क्या-क्या बोला है। उसे पढ़ने के बाद आत्मचिंतन और मनन करिए कि उसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा आपने असत्य बोला है। ...(व्यवधान) आप पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को अंधकार में डाला है। आप पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने बजट में 3586 करोड़ रुपये की कटौती की है। आप पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सैलरी के ऊपर कटौती की है। आप पहले मुख्य मंत्री हैं जिनके समय में अपनी ही पार्टी के 6 विधायक भाग गए। आप पहले मुख्य मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में अपने ही बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट आप लोगों ने हारी हुई है। यह आपके कुप्रबंधन के कारण है। यह नासमझी के कारण है। ...(व्यवधान) यह आवेश नहीं है, यह सटाईल है, (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी, जो सैलरी कम हो गई है उसे आप त्याग कह रहे हैं। जब जेब खाली होती है और कोई चारा नहीं होता, तो उसे त्याग नहीं कहते, उसे मजबूरी कहते हैं।....**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....**

25.03.2025/1700/केएस/वाईके/1

श्री बिक्रम सिंह जारी ---

जो सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है वह 3349 करोड़ रुपये के हवाई अड्डे और 609 करोड़ रुपये के चिड़ियाघर की बात कर रही है? यह पैसा कहां से आएगा? सवाल यह है कि यह पूर्ण आर्थिक आपातकाल की शुरुआत तो नहीं है? अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर लिखा है कि 500 करोड़ रुपये अधूरे कार्यों के लिए। पिछली बार भी फीगर थी और इस बार भी फीगर है। आप पिछले तीन वर्षों से क्या कर रहे हैं? आपको क्या पता ही नहीं चल रहा है कि इतने कार्य अधूरे हैं, इनको रिफ्लेक्ट रिफलेक्ट करनी चाहिए थी कि इतना काम हुआ है लेकिन आप असत्य बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बोलता भी हूं कि आप असत्य बोलते हैं। ना वह 1 हजार रुपये और ना ये 500 करोड़ आएंगे। वर्ष 2023-24 और 2024-25 में क्या करते रहे आप? आपको चौथे बजट में पता चला कि अधूरे अस्पताल हैं, टूटी सड़कें हैं और यह 500 करोड़ रुपये कोई समाधान नहीं है। यह 3 साल के प्रशासनिक

लकवे का लिखित करार है। आप पहले भी और अब भी ऐसे ही बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी की बड़ी इज्जत करता हूं। आप करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको पता है कि आप मिले हुए हैं, कोई दो राय नहीं है लेकिन आप बोलते हैं कि इन्होंने 1 हजार करोड़ रुपये के खाली भवन छोड़ दिए। क्या यह आपको 3 वर्षों में याद नहीं आया? चौथे बजट के अंदर आपको याद आ रहा है। आपने इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा। आप या तो इन्हें किसी विभागों को ट्रांसफर कर देते या कोई एन0जी0ओ0 गोद ले लेते। आप तीन साल से सत्ता में हैं, इसका आपको कोई ध्यान नहीं आया। अगर ये तीन वर्षों से खाली हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? उनका उपयोग आपने नहीं किया और आप बार-बार बोलते हैं कि इन्होंने तो ठेकेदारों को खुश करने के लिए कर दिया। आप नदौन में टूरिज्म का फाइव स्टार होटल बना रहे हैं। उसके ऊपर 25 से 30 करोड़ रुपये खर्च आएगा। क्यों बना रहे हैं जब आपको पता है कि नदौन में टूरिज्म ही नहीं है। आप क्यों गलत काम कर रहे हैं? वहां पर मित्र टूरिज्म का होटल बना रहे हैं, यह किसके लिए है? आपने हेलीपोर्ट की बात की। आदरणीय जय राम ठाकुर ने उस समय ढाई करोड़ रुपये का टेंडर लगाया था लेकिन आज वही टेंडर आपका 16 से 17 करोड़ रुपये तक चला गया है। क्या कारण है और उसको कौन बना रहा है? इस

25.03.2025/1700/केएस/वाईके/2

काम के अंदर मित्र ही लगे हुए हैं। एक बाबा बालकनाथ में 50 से 60 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बन रही है। जब आपके पास पहले ही बिल्डिंगें खाली हैं, आप क्यों बना रहे हो? हमीरपुर बस स्टैंड का टेंडर 45 करोड़ रुपये का हुआ। वह 34 करोड़ रुपये में अवार्ड हुआ। डेविएशन 128 करोड़ रुपये हुई। अब इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं व्यवस्था परिवर्तन बोलूं या यह बोलूं कि सबसे अमीर स्टेट बनने जा रहा है? इतनी बड़ी डेविएशन और वह भी ठेकेदार काम कर रहा है। दोबारा से काम अवार्ड नहीं हुआ और 45 करोड़ रुपये से 34 करोड़ रुपये उसने लिए हैं। उसके बाद 128 करोड़ रुपये की डेविएशन है। उसकी अप्रूवल है और यह आपने अपने किसी मित्र को दिया होगा। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। आप नादौन में बोलते हैं, मैं मानता हूं कि अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए काम करना होता है

लेकिन आप वह काम कीजिए जो आंखों से नज़र आ रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं। ये साहब बोल रहे हैं कि 70 करोड़ रुपये के अंदर राफ्टिंग केम्पस वहां पर बनाया जाएगा। राफ्टिंग होती कहां है? कुल्लू-मनाली में जहां ग्रेडिएंट वाटर होता है। वहां ग्रेडिएंट वाटर कहां है? ये जो मैं आपको इतनी बातें बोल रहा हूं ये या तो भ्रष्टाचार है, भाई-भतीजावाद है। या मित्रों को खुश करने की कला है इसलिए बोलना कुछ, करना कुछ और बताना कुछ। आप कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बना दूंगा क्या ऐसे आत्मनिर्भर बनेगा? क्या 128 करोड़ रुपये की डेविएशन से आत्मनिर्भर बनेगा?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य वाइंड अप करें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.03.2026/1705/av/ag/1

अध्यक्ष जारी----------

माननीय सदस्य, मैं भी आपके भाषण में बह गया और समय हो चुका है। अभी आप और कितना समय लेंगे?

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, 10-12 मिनट्स लूंगा।

अध्यक्ष : आपके बाद मुख्य मंत्री जी भी उत्तर देंगे। इसलिए अब इस माननीय सदन की बैठक 06.15 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

माननीय सदस्य, 12 मिनट्स मतलब 12 मिनट्स ही होने चाहिए।

श्री बिक्रम सिंह : इकोनॉमिक सर्वे में हमने प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखा है कि यह 15 प्रतिशत ग्रोथ के साथ चला है और यह ग्रोथ वर्ष 2019-20 में 18.02 थी और वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 8.04 है। जबकि मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कहां से बनना दूध वाला डोलू लेकर खड़ा है। दूध डाला ही कहां क्योंकि दूध का बड़ा बर्तन तो भर चुका है। इसी तरीके से सेकेण्डरी सेक्टर इण्डस्ट्रीयल तथा मेनुफैक्चरिंग में वर्ष 2018-19 में जी0एस0डी0पी0

44.09 प्रतिशत थी और वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 39.04 प्रतिशत पर चली गई। आपका सर्विस सेक्टर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10.02 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 8.06 प्रतिशत पर चला गया है।

इसके अतिरिक्त मैं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन पर भी आंकड़े देना चाहता हूं। जिस समय भाजपा की सरकार थी तो हमारे पास 3100 बसिज थीं और कॉंग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये 2823 रह गई हैं। हमारी सरकार के समय में ई-बसिज 110 थीं और आज भी वे 110 ही हैं। हम तीन वर्षों से बजट के अंदर एक लम्बा-चौड़ा पैरा देख रहे हैं कि इलैक्ट्रिक बसिज आ रही हैं, राज्य को हरा कर दूंगा, वे सारी चीजें कहां पर हैं? मुख्य मंत्री जी, आपने जो अध्यक्ष महोदय के सामने शब्द कहे हैं कि 'मुझे मेरी एक असत्य बात तो बताइए'। परंतु आपकी इतनी ज्यादा असत्य बातें हैं कि एक किताब न भर जाए। आपकी उन असत्य बातों पर एक किताब बन जाएगी। इलैक्ट्रिक बसिज के बारे में

25.03.2026/1705/av/ag/2

आपने जो तीन वर्षों पहले बात की थी हम आज भी वहीं-के-वहीं पर खड़े हैं। रीयल एस्टेट के अंदर भाजपा के समय में 10.09 प्रतिशत ग्रोथ थी जोकि अभी 6.05 प्रतिशत है।

हिमाचल कौशल विकास निगम में भाजपा ने 434 नये यूनिट्स बनाएं और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्होंने केवल 174 नये यूनिट्स बनाएं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों की एनरोलमैंट जिसके बारे में यहां पर शिक्षा मंत्री जी भी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने सी0बी0एस0सी0 स्कूल्ज कर दिए। मेरा बेटा अब पैदा होते ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा या वैसा कर देगा, आपका यह हाल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी स्कूल्ज के अंदर 62.07 प्रतिशत बच्चे पढ़ते थे और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इनकी संख्या 56.03 प्रतिशत हो गई। यह आपका इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। आपके इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 65132 रजिस्ट्रेशन्ज हुईं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट जॉब 4559 तथा सरकारी जॉब 375 दी गईं जोकि कुल मिलाकर 5000 का आंकड़ा बनता है। आप तो एक वर्ष एक लाख और 5 वर्षों में 5 लाख जॉब्ज देने की बात करते थे जबकि आपने अपने एक

वर्ष के कार्यकाल में केवल 375 सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्य मंत्री जी, इससे ज्यादा असत्य आप और क्या बोलेंगे?

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बोलना चाहता हूं जिसकी कण्डीशन बहुत अलार्मिंग है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विभाग के अंदर सीरियस होकर काम करे। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की नेशनल एवरेज 12.04 प्रतिशत और हिमाचल में 13.02 प्रतिशत है। मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3042 लोगों को फायदा हुआ और उनको 72.18 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2801 लोगों को फायदा हुआ तथा 94.08 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। जबकि इनके राज में यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना का फायदा केवल 44 लोगों को मिला है और केवल 9.68 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। फिर ये कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश से बेरोज़गारी समाप्त कर देंगे और प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। इनकी इस प्रकार की हालत है।

इसके अतिरिक्त आपने फिश प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा बात की है

टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री बिक्रम सिंह... जारी

ऐसा लगा जैसे कोई क्रांति आ जाएगी। इसमें वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक लगातार बढ़ोतरी होती रही। लेकिन वर्ष 2025-26 के अंदर माइनस 34.6 प्रतिशत की गिरावट आई और ट्राउट में -56.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यह हाल है आपके प्रोडक्शन का।

न्यू इण्डस्ट्रियल पॉलिसी वर्ष 2019 में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने लागू की और कहा गया कि यह वर्ष 2022 तक चलेगी। आदरणीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी बार-बार पूर्व सरकार और उद्योग मंत्री की आलोचना करते हैं। यह पॉलिसी वर्ष 2022 में समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन इन्होंने उस पॉलिसी को वर्ष 2025 तक आगे बढ़ाया।

अगर इण्डस्ट्रियल पॉलिसी ठीक नहीं थी, अगर हमने गलत काम किया था, अगर ग्लोबल इनवैस्टमैंट मीट गलत थी, अगर जमीन का आबंटन गलत था, तो इस पॉलिसी को एक्सटेंड क्यों किया गया? अपने भाषण में यह स्पष्ट करें कि इसे एक्सटेंड करने का कारण क्या थे? मेरे साथी यहां बैठे हैं। मेरे नाड़ागढ़ के लोकप्रिय कल कह रहे थे कि जमीन सस्ती दे दी गई। अगर दे दी गई थी तो इसे सुधारिए, कैंसिल कीजिए या नई पॉलिसी लाइए। लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हुआ। आपने इसे बंद करने की कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हुए। यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी थाने या कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि नीति सुधार की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दो, तीन मिनट में अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मैंने कल भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि इतना भेदभाव ठीक नहीं है। आपके जिला में जो फंड जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा कमी हैं। एन0डी0आर0एफ0 के तहत ज्वाली को 172 लाख रुपये, लंबागांव को 112 लाख रुपये, देहरा को 148 लाख रुपये और देहरा को दूसरी बार 110 लाख रुपये दिए गए, जबकि देहरा को जीरो रुपये दिए गए।

25.03.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

इसी प्रकार डिसेंट्रलाइज्ड प्लान बैजनाथ को 63 लाख, देहरा 113 लाख, फतेहपुर 102 लाख, इंदौर 102 लाख और ज्सवां- परागपुर को 2.5 लाख रुपये दिए गए । इसी तरीके से एन0डी0आर0एफ0 के पेज पर मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र का नाम ही नहीं है लेकिन देहरा को 26.86 लाख रुपये, फिर देहरा 134.32 लाख रुपये और इसी तरीके से शाहपुर 1613 लाख रुपये, फतेहपुर 189 लाख रुपये दिए गए ।

इसी तरीके से हैल्थ और विकास में जन सहयोग सहित अन्य सभी मदों में जसवां - प्रागपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं कल भी माननीय सदन में बोला था, आज भी बोल रहा हूं। जो अफसर लोग हैं, वे कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, खास करके डी0सी0 कांगड़ा। अगर उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो व्यवहार उल्टे तरीके से ठीक किया जाएगा। मैं यह सदन में कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से

काम करना है, अगर हमारे विधान सभा क्षेत्रों के साथ इस प्रकार की हेराफेरी करनी है तो यह बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोगों पैसा मिलना था, हमें उससे वंचित कर रहे हैं। ये पैसा आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। यह प्रदेश का पैसा है।अभी प्लानिंग की मीटिंग हुई और उस प्लानिंग मीटिंग में मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आप प्लानिंग मीटिंग में नहीं आते। मैंने इनसे कहा कि जब आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम प्लानिंग मीटिंग में क्यों आएं? फिर भी हम आपके कहने पर प्लानिंग मीटिंग में गए और वहां बैठकर आपने कहा कि अपनी समस्याएं बताइए। मैं मुख्य मंत्री और पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर के बीच कोऑर्डिनेशन की बात करना चाहता हूं। मैंने वहां बताया कि सी0आर0एफ के अंतर्गत शांतला से लेकर रक्कड़ तक सड़क का मामला लंबे समय से लंबित है, इसे दिल्ली भेज दिया जाए, बाकी काम हम संभाल लेंगे। उस मीटिंग में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने संबंधित अफसर और सेक्रेटरी पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देश दिया कि इसे तुरंत दिल्ली भेजा जाए। लेकिन एक महीने पहले जब मैंने एक अफसर से बात की तो उन्होंने बताया कि आदरणीय पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर साहब ने फाइल रोक कर रखी है और कहा है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी ने मीटिंग में कह दिया, उसके बाद मैं दिल्ली गया लेकिन वहां पता लगा कि फाइल तो कभी पहुंची ही नहीं। यह लगभग 10 दिन पहले की बात है। इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन इस सरकार में देखने को मिल रही है। मैं केवल पी0डब्ल्यू0डी0 या एन0डी0आर0एफ की बात नहीं कर रहा हूं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

25-3-2026/1715/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री बिक्रम सिंह----जारी

आप हैल्थ या जल शक्ति विभाग का विषय ले लीजिए और जहां भी विपक्ष के सदस्य बैठे हैं उनके साथ इस प्रकार का काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सारे विषयों में सुधार करें और फिर आगे बढ़ाएं।

मैं अंतिम विषय के बारे में बोल कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इन्होंने इस बजट में 'सुखी परिवार योजना' का नाम लिया। इनको तीन वर्षों बाद या चुनाव से पहले गरीबों की याद

आई। इन्होंने कहा कि एक लाख गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है और बी0पी0एल में जो माताएं-बहनें 1000 में आएंगी उनको 1500-1500 रुपये देने हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कब कहा था और आज 'सुखी परिवार योजना' कहां से आ गई? आप यह बताइए कि गरीब व्यक्ति जिसका छोटा-सा मकान होता है, क्या वह 300 यूनिट बिजली जलाता है? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। जो आदमी 10 यूनिट या 50 यूनिट जला रहा है तो उसको 300 यूनिट फ्री बिजली देने से क्या फायदा होगा। आप उन महिलाओं के लिए 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, आपकी ये जितनी भी योजनाएं हैं ये इस बात का संकेत देती हैं कि सरकार की हालत बड़ी बदतर है, सरकार झूठी है, सरकार असत्य बोल रही है और सरकार आम जन मानस के साथ किए गए वायदों में फेल है तथा ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट सिकुड़ा है। अगर बजट सिकुड़ा है तो विकास भी सिकुड़ेगा। इस बजट बुक में जितनी भी योजनाएं दी गई हैं वे सब योजनाएं असत्य हैं। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

25-3-2026/1715/एन0एस0-ए0एस0/2

अध्यक्ष : अब वैसे तो मुख्य मंत्री जी ही जवाब देंगे। अगर अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी बोलेंगे तो विपक्ष से भी एक माननीय सदस्य बोलेंगे। मेरे पास लिस्ट में नाम आए है। The Congress Vidhayak Dal decide who is to speak now. If Shri Rajesh Dharmani wants to speak thereafter I will ask Shri Dalip Thakur to take part in the deliberations. Shri Ram Kumar is also there to speak. The Congress Vidhayak Dal must decide it what is to be done and what not. ...(Interruption) There is no need of interpretation. This is a question of coordination between the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Minister, this is what he referred to. ...(Interruption) No, I will not allow. There is no personal accusation. There is work coordination itself. The Hon'ble Chief Minister will reply to that. माननीय मुख्य मंत्री महोदय ।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा इण्डस्ट्रियल पैकेज कैंसिल क्यों किया? हमने क्या कैंसिल किया आपको बता देते हैं? हमने 1 रुपये स्कवेयर मीटर पर जो जगह दी गई थी उसके लिए कहा कि उसको बंद करें और मार्केट रेट पर जगह दी जाए। हमने यह किया। ...(व्यवधान) हमने इस पॉलिसी को इसलिए अमेंड किया कि मैंने देखा कि कस्टोमाइज पैकेज के नाम पर प्रदेश की संपदा को लुटा दिया गया। मैंने कहा कि जब तक नई इण्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आती तब तक कस्टोमाइज पैकेज के नाम पर प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देंगे, जो मार्केट रेट जगह का है उस मार्केट रेट पर जगह देंगे। मैंने यह अमेंड किया है। आप आज जो बसस्टैंड के ठेकेदार की बात कर रहे हैं तो आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन गलत दी है। तभी तो मैं आपको बोलता हूं कि आप पहले पूरा पता कर लिया करें। वह ठेकेदार मण्डी में कई बिल्डिंग्ज बना चुका है और वह मण्डी का है। ठेके देना मेरा काम नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको हमारी सरकार जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। तीसरा, इन्होंने कहा कि हमारा और लोक निर्माण मंत्री जी का को-ऑर्डिनेशन नहीं था। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा को-ऑर्डिनेशन था। इन्होंने एक मांग बड़े जोर के साथ रखी कि हमें विधायक क्षेत्रीय विकास निधि मिलनी

25-3-2026/1715/एन0एस0-ए0एस0/3

चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि हमारे प्रधान सचिव, वित्त प्रदेश की वित्तीय हालत पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और आप उसमें आना। इन्होंने कहा कि हम आएंगे और ये नहीं आए। हमने फिर भी इनकी बात मानते हुए कहा कि हम आपको विधायक क्षेत्रीय विकास निधि देंगे और उसकी किस्त हमने रिलीज भी की। यह को-ऑर्डिनेशन ही था जो हमने आपकी बात सुनी। ...(व्यवधान)

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.03.2026/1720/RKS/AS-1

मुख्य मंत्री जारी...

...(व्यवधान) जो हालात थे, मैंने उसके हिसाब से यह निधि दी है। आपने जो कहा था, हमने वह कर दिया है। मैं यह कह रहा हूं कि हमने ये चीजें की हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नगर एवं ग्राम एवं योजना मंत्री। ...(व्यवधान) धर्माणी जी कृपया एक मिनट बैठ जाइए। I am seeking the cooperation of the Hon'ble Members of both the sides. I am ready to sit after nine o'clock, ten o'clock, that is not the issue. I am sitting here since Eleven o'clock continuously because today's proceeding is important. Reason being the Hon'ble Chief Minister is to reply. That's why I am sitting here today throughout the day without giving a chance to my other fellow members. So, that is my concerned. You all please have a consensus in your *Dal*. This is a shocking state of affairs for me now to conduct the proceedings. माननीय नगर एवं ग्राम एवं योजना मंत्री जी।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। 21 मार्च, 2026 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां वित्तीय बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। बड़ी कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच में मुख्य मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार की अपेक्षाएं और अनुमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए थे उनकी इन आशाओं और अनुमानों पर पानी फिर गया है। क्योंकि इन्होंने सरकार को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का जो षड्यंत्र रचा था; जिस प्रकार से हमारी आर0डी0जी बंद कर दी गई इसमें इन्होंने यह अनुमान लगाया था कि इसका प्रभाव बजट में देखने को मिलेगा। इनका अनुमान था कि लोग जन आंदोलन में उतर जाएंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके विपरीत बजट पेश करके समाज के उन वर्गों का ध्यान रखा जिनके बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों, विधवाओं, अपंगों, अनाथों, युवाओं और यहां तक कि

25.03.2026/1720/RKS/AS-2

मछुआरों को भी इस बजट में राहत दी गई। प्रदेश के विकास को कैसे सुनिश्चित करना है इसके बारे में भी बजट में रेफरेंसिज दिए गए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर नाबार्ड की आवंटन राशि को बढ़ाकर 200 से 225 करोड़ रुपये किया गया है। इससे जहां हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं समाज के कमजोर वर्गों को भी बल मिलेगा। इस बजट को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाज के सबसे हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं शुरू कीं और उनके लिए वित्तीय प्रबंध भी किए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो नई योजनाएं आरंभ की हैं उनका विवरण भी अवश्य दें। इन योजनाओं पर हमारी सरकार ने कितना व्यय किया है और इसकी एवज में सरकार ने कितना राजस्व जनरेट किया है उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1725/बी.एस./ए.एस.-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

उसका आप जरूर विवरण दें कि इसके ऊपर कितना खर्चा हमारी सरकार ने किया है और उसकी एवज में कितना पैसा रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। अगर हम सिर्फ उन योजनाओं पर फोकस करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जितना पैसा हमने खर्च किया है उतने खर्चे के लिए रेवेन्यू का भी इंतजाम किया गया है। जो परिस्थिति खराब हुई है वह लिगेसी इश्यूज की वजह से खराब हुई है। जो कर्ज इस सरकार को विरासत में मिला, जो विरासत में कमिटेड लायबिलिटी मिली हैं उसकी वजह से है। आज अगर हम देखें तो लगभग 75 प्रतिशत बजट कमिटेड लायबिलिटी का है। लेकिन अगर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से देखें तो यह बहुत ज्यादा है। मैं यह कोट नहीं करना चाहता। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनीं? क्या यह परिस्थितियां आदरणीय सुखविन्दर सिंह जी की सरकार

द्वारा बनाई गई हैं? या पूर्व की सरकारों द्वारा बनाई गई हैं? हमें जो अनटाइड फंड मिला जिसका आदरणीय रणधीर शर्मा जी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने आर0डी0जी0 को बंद करने को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की, हालांकि दिल से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह इनकी मजबूरी है।

(सभापति श्री संजय रत्न जी पदासीन हुए।)

हमें अनटाइड फंड 17,000 करोड़ रुपये मिले जबकि आपके समय में 5 साल में अनटाइड फंड और जी0एस0टी0 कंपेनसेशन को मिलाकर 70,000 करोड़ रुपये मिले। उस 70,000 करोड़ रुपये का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए, जिसमें आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया हो और उससे प्रदेश की आय में इजाफा हुआ हो।

श्री जय राम ठाकुर : हमने उस पैसे को प्रदेश के विकास कार्यों में लगाया है।

25.03.2025/1725/बी.एस./ए.एस.-2

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि वह पैसा साइन ऑफ हुआ लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च नहीं हुआ। कोई ऐसा निवेश नहीं हुआ जिससे रेवेन्यू जनरेशन का एक कंटीन्यूअस सोर्स बन सका।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कल बड़ा दुःख हुआ जब नेशनल मीडिया में देखा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड कुछ मीडिया हाउसों ने हिमाचल सरकार को माध्यम बनाकर हिमाचल को बदनाम कर राजनीति करने की कोशिश की। इशू उठाया गया कि पेट्रोल-डीजल पर सैस लगा दिया गया।

श्री जय राम ठाकुर : यह फैक्ट है।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : बिल्कुल फैक्ट है यहां से बिल पास हुआ है, लेकिन क्या यह फैक्ट नहीं है आदणीय बिक्रम ठाकुर जी सी0आई0आर0एफ0 का जिक्र कर रहे थे। सी0आई0आर0एफ0 का जो पैसा आता है वह भी सैस का पैसा ही है। भारतीय जनता पार्टी

की जो दिल्ली में सरकार है जिसने इस साल वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है, उसमें कुल सैस और सरचार्ज को इकट्ठा किया जाए तो लगभग 5.91 करोड़ रुपये का है परंतु इस पर कोई चर्चा मीडिया में नहीं हुई लेकिन जब हमने 75,000 करोड़ रुपये का सैस लगाया और वह सैस कहां खर्च होना है। वे टारगेटेड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं orphan and widows, इनके कल्याण के ऊपर खर्च होना है परंतु इन्हें तकलीफ हो गई। नेशनल मीडिया में इस तरह से कैंपेन चलाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया गया हो। क्या भारत सरकार ने टैक्स नहीं लगाए हैं? टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू किसी भी सरकार के लिए स्कीमों को फाइनेंस करने का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्या ऐसा कोई काम किया गया है जो पहली बार हिमाचल सरकार ने किया हो? पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री बता दीजिए जहां बिना टैक्स लिए सरकार की स्कीमें चलती हों। इस तरह हिमाचल को बदनाम करने का अभियान, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो उसके ठीक पहले कोई न कोई मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि इनके पास और कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है और हमें हैरानी होती है कि हिमाचल प्रदेश के सांसद यहां से चुनकर गए उन्होंने कभी संसद के अंदर हिमाचल की वकालत नहीं की। **श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....**

25.03.2026/1730/DT/DC-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

उन्होंने कभी हिमाचल की वकालत संसद के अंदर नहीं की वहां पर सिर्फ वन पॉइंट प्रोग्राम है कि राहुल गांधी जी की किस तरह से निंदा करनी है, उनके खिलाफ क्या बोलना, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं। एक सांसद तो बोले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि महिलाएं असहज महसूस करती हैं। किस महिला ने असहज महसूस किया? जब वह महानुभाव सांसद बनी क्या वही असहज महसूस करने लगी? एक वन प्वाइंट एजेंडा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, इसके माध्यम से उसको बदनाम किया जाए। हमारे प्रदेश में अधिकारियों की एक फौज खड़ी है लगभग 15000 से ज्यादा अधिकारी हिमाचल प्रदेश में हैं। विपक्ष के हमारे साथी बताएं कि अधिकारियों के कितने पद वर्तमान सरकार द्वारा क्रिएट किए गए? अगर

हमारी सरकार ने पद क्रिएट किए हैं तो वह पद डॉक्टर्ज के किए हैं ताकि हमारे मेडिकल कॉलेज स्ट्रेन्थन हो। इसके अतिरिक्त कोई और राजपत्रित पद क्रिएट नहीं किया। अगर हमारी सरकार ने सीबीएसई स्कूल पैटर्न पर जाकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए तो उसके साथ में यह भी इंतजाम किया गया कि जो एक्सपेंडिचर हमारे कुछ ऐसे स्कूल में हुआ है जहां पर बच्चे कम थे और टीचर की संख्या भी ज्यादा थी, ऐसे स्कूल्ज को राशनालाइज भी किया गया। उनको मर्ज भी किया गया। अगर हमने खर्चा किया है तो उस खर्च की पूर्ति का प्रबंध भी किया है। कल माननीय सदस्या रीना कश्यप जी का एक प्रश्न लगा था कि इनके क्षेत्र में कितने आईटीआई हैं? इनके क्षेत्र में तीन आई0टी0आई0 हैं। वैसे तो बेहतर होता कि हम सब लोग आपस में विचार विमर्श करते क्योंकि एक विधान सभा क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 काफी थी। लेकिन आई0टी0आई0 ज्यादा खोल दी गई है। इनके क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 कोटि बढ़ोग है जिसमें केवल 11 बच्चे हैं और 18 कर्मचारी हैं। हमने उसको राशनालाइज किया है। ऐसी चीजों में कुछ लोगों के वेस्टिड इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए वह फाइल तीन-चार बार मेरे पास आई क्योंकि जो डिजायरड रिकोमेंडेशन होती है वह उसमें न हो तो हम दोबारा उस फाइल को भेज देते हैं। वह फाइल तब तक दोबारा नहीं आती जब तक उसको पुल न किया जाए। यह व्यवस्थाएं पहले से बिगड़ी हुई हैं। उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ही तो हम कदम उठा रहे हैं तभी तो हम इसे व्यवस्था परिवर्तन का नाम दे रहे हैं।

आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सर्विसिज ऑनलाइन मिलती हैं। आज हमारा सड़कों का नेटवर्क बड़ा, परिवहन की सुविधाएं बड़ी। आज हिमाचल

25.03.2026/1730/DT/DC-2

प्रदेश में 28 लाख से ज्यादा वाहन हैं। जब सड़के कम थी और इंटरनेट नहीं था और वाहन कम थे, तो हमारे पास दफ्तर कम थे, तहसीलें कम थी बी0डी0ओ0 के ऑफिस कम थे, एस0डी0एम0 के ऑफिस कम थे। सुविधाएं और संसाधन बढ़ने से इन सभी कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए लेकिन अभी भी एक्सपेंशन का दौर जारी है। इसलिए यह व्यवस्था बिगड़ गई है। यह व्यवस्था हाल ही में थोड़ी बिगड़ी है। प्रदेश में इतने कॉलेजिज खोल दिए और आज कई कॉलेज ऐसे हैं जहां 100 से भी कम बच्चे हैं। जो बच्चा जिस गांव में पैदा हुआ उसी गांव के स्कूल में पड़ेगा, उसी गांव के कॉलेज में पड़ेगा तो उसे एक्स्पोज़र कभी नहीं मिलेगा। वह वहीं का वहीं रह जाएगा। उससे किसी का कोई भला नहीं होने

वाला। तर्क के लिए जो मर्जी तर्क दे दो। यहां पर अभी विक्रम ठाकुर जी कह रहे थे की नदौन में ऐसा कर दिया, ठीक है मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन अगर आप उसके धरातल पर जाएंगे तो आपको समझ आयेगा कि वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। अगर स्पोर्टस सेंटर आफ एक्सीलेंस बनेगा तो उसका फायदा दूरगामी होगा। अगर होटल बना है तो होटल से रेवेन्यू आएगा। लेकिन इनके टाइम की एक बात मैं कोट करना चाहता हूं। इनके समय में हिमाचल कौशल विकास निगम बना। सरकार ने 600 करोड रुपए ए0डी0बी0 से फाइनेंस करवाया और उसे उसके ऊपर खर्च कर दिया। बिल्डिंग्ज बन गई कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं बनाया गया जिसमें यह उल्लेख हो कि इसे सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाना है। इसके जो जरूरी खर्चे होंगे उन्हें कहां से फाइनेंस करना है? उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इसकी पैरेलल तुलना मैं महाराष्ट्र से करना चाहता हूं। एच0पी0के0वी0एल0 की तरह महाराष्ट्र में एम0के0सी0एल0 बना यानी Maharashtra Knowledge Corporation Limited. सरकार ने इसमें दो करोड़ पर इन्वेस्ट किया दो करोड़ की एवज

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.03.2026/1735/एच.के.-एन.जी./1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री..... जारी

में एम0के0सी0एल0 (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड), महाराष्ट्र सरकार को 600 करोड़ रुपये का डिविडेंड दे चुकी है और हम 600 करोड़ रुपये खर्च करके भी उन बिल्डिंगों के रख-रखाव, बिजली और पानी के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। ये जो लायबिलिटीज़ हैं, ये किसने क्रिएट की हैं? आज जो यह लोन का बोझ बढ़ा है, इसे किसने क्रिएट किया? अगर पूर्व सरकार के समय 70,000 करोड़ रुपये का अनटाइड फंड मिला था और उससे अगर लोन वापस कर दिया जाता, तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट होता और आज हमारी लायबिलिटी कम होती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया और आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। आज विपक्ष के लोग जो बातें करते हैं, वे सही नहीं हैं। अगर आप देखेंगे कि बी0जे0पी0 के समय में अनेक संस्थान खोले गए थे,

जिनमें से अधिकतर की जरूरत ही नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी तो कहा गया कि हम इनको रिव्यू करेंगे और नीड बेस्ड संस्थान खोलेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वे सारे संस्थान फंक्शनल हो जाते, क्योंकि पूर्व सरकार ने तो उनके लिए स्टाफ भी नहीं भरा था तो आज की स्थिति इससे भी खराब हो जाती। अगर हम इसी तरह की सोच लेकर चलेंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला है। ...(घण्टी)... मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह विकट हालातों को देखते हुए पेश किया है। मुख्य मंत्री जी अभी सदन में मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं उनके बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगाः-

संघर्षों की आग में जो तपकर निकला है,

वही असली नेता बनकर चमका है।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू सिर्फ मुख्य मंत्री नहीं,

जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा है।

25.03.2026/1735/एच.के.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं बीच में एक और बात कहना चाहूंगा कि आज हमें आगे की तरफ सोचने की जरूरत है और एक बेहतर विरासत क्रिएट करनी चाहिए। जिस तरह से परिवार के स्तर पर हम सोचते हैं, उसी तरह से हमें राज्य और सरकार के स्तर पर भी सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। आज हमें कमिटेड एक्सपेंडिचर कम करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी Redundant Posts हैं जिन्हें रेशनेलाइज़ करने की जरूरत है लेकिन रेशनेलाइजेशन के नाम पर लोग भड़क जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भड़कने की क्या बात है? आज हमें वर्क कल्चर विकसित करने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वित्त विभाग या जी0ए0डी0 की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि सचिवालय में कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जहां पर वर्कलोड ज्यादा है और वहां काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। जो लोग काम कर रहे

हैं, वे ओवरबर्डन हैं क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रही। इसलिए उनके लिए अलग से इंसेंटिव दिया गया। यह इंसेंटिव कैपिटल अलाउंस और सैक्रेट्रिएट अलाउंस से अलग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिवालय की दो बिल्डिंगों के अंदर भी कुछ ब्रांचों में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। इसलिए आज हमें वर्क कल्चर बढ़ाने की जरूरत है। यहां पर जो बात कही गई कि सैलरी डैफर की गई, हालांकि कट नहीं लगाया गया है। माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह ने यहां पर बड़े-बड़े नियम और कानून पढ़ दिए। लेकिन जब गरीब की बात आती है तो नियम-कानून कहीं दिखाई नहीं देते और फिर नेशनल मीडिया में खबर चलती है कि यह सैस क्यों लगाया गया। क्या गरीब आदमी को आपके समय में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, वह तीन महीने बाद नहीं मिलती थी? तब कानून नजर नहीं आता था? क्या गरीब के लिए कानून नहीं होना चाहिए? मांग तो यह होनी चाहिए थी कि गरीब लोगों के लिए भी कानून बनाया जाए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका महीने का खर्च भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से चलता है। उन लोगों के बारे में भी तभी कुछ कर पाएंगे जब हम सब मिलकर सोचेंगे।

25.03.2026/1735/एच.के.-एन.जी./3

इसके अलावा हमें आज इंवेस्टमैंट बढ़ाने की जरूरत है। हमें ऐसे प्रोजैक्ट्स लाने की जरूरत है जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। हमें माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना है क्योंकि हमने शहरी विकास विभाग की तरफ से जो प्रपोज़ल बनाई थी, उसके अनुसार तीन नई सिटीज़ डवपल करने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इस प्रपोज़ल में माननीय सदस्य, श्री राम कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन तीन नए शहरों में— हिम-चंडीगढ़, हिम-पंचकुला और कांगड़ा वैली एयरोसिटी की परियोजनाएं शामिल हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम इस दिशा में सही तरीके से काम करें और इसमें कोई राजनीतिक बखेड़ा न खड़ा करें, क्योंकि यह एक दम से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि चुनावों से पहले सारा कुछ

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1740/एच0के0/ए0पी0/-01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी .....

तैयार हो जाएगा। शहर भी बस जाएगा और जैसे पहले इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि बेच भी दिया जाएगा। इसे आप दीर्घकालिक योजना के हिसाब से देखें। इन तीन शहरों के माध्यम से अच्छा-खासा राजस्व आ सकता है। केंद्र सरकार ने भी शहरों को ग्रोथ इंजन का नाम दिया है। कोई भी शहर अपने आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित करता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना इस प्रदेश पर कर्ज है उसे हम इन तीन शहरों को अच्छे तरीके से विकसित कर उस कर्ज को उतार सकते हैं। क्योंकि इन तीन शहरों का विकास एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी, जिससे प्रदेश में विकास और राजस्व आएगा। दूसरा हमें रेशनलाइजेशन, सरकारी सिस्टम के पुनर्गठन और मर्जर जैसे कार्यों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तभी हम आने वाली पीढ़ियों का भला कर पाएंगे। हम देखते हैं कि सरकारी सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे उदाहरण पेश करते हैं। मैं पासिंग रेफरेंस में एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे एक शिक्षक हैं जिनका नाम जोगिंदर सिंह जी है। उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। उनकी दो बेटियां हैं और वे दोनों नौकरी करती हैं और वे खुद भी घर से बाहर थे। मैंने उन्हें फॉन किया और कहा कि मैं आपकी ट्रांसफर आपके घर के नजदीक करवा रहा हूं, आप मुझे डिटेल लिखवा दो। उन्होंने जवाब दिया कि मिड-सेशन में अगर मेरी बदली हो गई तो मेरे बच्चों को दिक्कत होगी। वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला। अब जब सेशन पूरा हुआ तब जाकर हमने उन्हें एडजस्ट किया। दूसरा उदाहरण बिलासपुर का है, जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मैनेजर हैं। सभापति महोदय, उनका नाम तूलसी राम है। वे कूक

भर्ती हुए। श्री त्रिलोक जम्वाल जी आप भी शायद इन्हें जानते होंगे। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उनकी यूनिट आज प्रॉफिट में है। यह उसकी मेहनत है, इसमें उन्होंने काफी मेहनत की है। एक और उदाहरण हमारे एक डॉक्टर है जो कि चमियाणा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉ0 ब्रीज शर्मा है। प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपको सुबह 8.00 बजे एंडोस्कोपी करते हुए नजर आएंगे। जब उन्हें लगा कि स्पीति से बहुत सारे मरीज आ रहे हैं तो इन्होंने अपने स्तर पर काजा में एंडोस्कोपी लैब स्थापित

25.03.2026/1740/एच0के0/ए0पी0/-02

की और हर तीन महीने में वहां जाकर सेवाएं देते हैं। ये सभी हमारे प्रदेश के अनसंग हीरो हैं। इसी तरह, एक महिला हैं जो बिलासपुर सदर विधान सभा क्षेत्र में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं। उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिली थी। वे नबगांव में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर लगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हैंडवॉल की वजह से उन्हें नौकरी मिली है और वे सन्तुष्ट है। उन्होंने यह देखा कि खेल के माध्यम से मेरी जिंदगी बदली है तो क्यों न मैं अन्य लड़कियों की जिंदगी को भी बदलूं। आज नबगांव में लगभग 35 लड़कियां, जो गरीब परिवारों से थीं, उनकी छात्राएं रही हैं और उन्हें सरकारी नौकरी मिल चुकी है। आज के समय में वह मोरसिंघी में आपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके पढ़ाए हुए लगभग 80 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 100 इंटरनेशनल प्लेयर हैं और 300 के करीब नेशनल मेडलिस्ट हैं। उनका नाम स्नेह लता है और वे पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं। हमारे बीच में इस तरह के लोग भी हैं, इन्हें हमें आगे लाना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब हैंडबॉल का नेशनल टूर्नामेंट था, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये और उन्होंने अलग से एक स्पोर्ट्स हॉस्टल स्वीकृत किया है जोकि बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। इस तरह के जो लोग समाज में काम कर रहे हैं। चाहे वे प्राइवेट सेक्टर में हों। हमें उन सभी को आगे लाने की जरूरत है। वर्क कल्चर को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सिर्फ वही पुराना मॉडल अपनाते रहेंगे जो अब तक चलता आया है कि बिना सोचे-समझे पोस्ट क्रिएट करते रहें। यह सोचे बिना कि उन्हें चलाना कैसे है। बहुत से दफ्तरों को खोलते रहें चाहे उनकी जरूरत हो या नहीं। इससे काम नहीं चलेगा। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें इस जुगाड़ वाले

सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जो पी0एस0यूज0 हैं। वे पी0एस0यूज0सिक्ख संस्थान बन चुके हैं। इनके टर्नअराउंड के लिए हमें एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि इन पी0एस0यूज0 को सोच समझ के साथ बनाया गया था कि ये सभी पी0एस0यूज0 आपने आप में सस्टेनेबल होंगे और राज्य को मुनाफा भी देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनमें भी बहुत सारे हमारे

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1745/AT/YK/01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी....

रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

Chairman : Please wind-up.

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में वाइंड-अप कर रहा हूं। हमारी जितनी भी अर्बन बॉडीज़ हैं, हमारा बी0बी0एन0डी0ए0 भी प्रॉफिट में नहीं है। अगर वहां भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो काम कैसे चलेगा? हमारे साडा एरिया हैं, उन्हें सेल्फ-रिलायंट बनाने की ज़रूरत है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमें करप्शन खत्म करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े हैं और जिनके हाथ में निर्णय लेने की शक्ति है, अगर वे ईमानदारी से काम करें तो कुल लागत में 10 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। हर चीज़ में 10 प्रतिशत की बचत हो सकती है। जो भी हम प्रोक्योरमेंट या टेंडर करते हैं, उसमें हम 10 प्रतिशत पैसा बचा सकते हैं। इस तरीके से हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहां डैफरमेंट की बात हो रही है हालांकि कुछ सेक्शन की हुई है जैसे ग्रुप A और ग्रुप B क्लाल के अधिकारियों

की, उसके लिए भी मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं, जहां वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और भयंकर सूखा पड़ा था। तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से आह्वान किया था कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। हिन्दुस्तान के हर नागरिक ने उनकी बात सुनी और उपवास रखा, उस चुनौती का भी हमने सामना किया।

आज हम सिर्फ डैफरमेंट की बात कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। हमें स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। जिसकी आमदनी पचास हजार से ज्यादा है अगर वह कहे कि मेरा 10 प्रतिशत

25.03.2026/1745/AT/YK/02

डैफर कर दो। जिसकी आमदनी एक लाख से ज्यादा है वह कहे कि मेरा 15 प्रतिशत डैफर कर दो। इससे उनका घर बंद नहीं होगा, लेकिन अगर यह नहीं किया गया तो बहुत लोगों को इसका नुकसान होगा। वह आप भी जानते है और हम भी जानते हैं। उस नुकसान से उस वर्ग को कैसे बचाना है जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में सभी को सोच-विचार करने की ज़रूरत है। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। क्योंकि अगर हम पार्टी के आधार पर सोचेंगे, तो आप विरोध में बोलेंगे और हम पक्ष में बोलेंगे, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए सब इसके बारे में सोंचे।

अंत में, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है लोगों के प्रति उसको दर्शाता है :-

नेक इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं,
हर जन के सपने साकार करेंगे।
हर चुनौती का मुकाबला करेंगे,
विरासत में मिली खामियों को सुधारेंगे।
समग्र विकास की राह पर चलेंगे,
गौरवमय भविष्य की नींव सुदृढ़ करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट अनुमान का समर्थन करता हूं। जय हिंद।

25.03.2026/1745/AT/YK/03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह ठाकुर जी।

श्री दलीप सिंह ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 21 मार्च, 2026 के बजट अनुमान पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, यह सरकार का चौथा बजट है और सरकार का जब चौथा बजट आया, तो प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि इस बजट में हमारे नौजवान युवा हों, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। हमारी बहनें जो चौथे बजट का इंतजार कर रही थी कि उन्हें 1500 रुपये मिलेंगे और हमारे किसानों को भी लगता था कि सरकार उनके लिए भी कुछ-न-कुछ करेगी।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

लेकिन वास्तव में इस सरकार ने चौथे बजट में भी कुछ नहीं किया। इस सरकार की जनता को कुछ भी नहीं दिया।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1750/केएस/वाईके/1

श्री दलीप ठाकुर जारी ----

वह चाहे नौजवानों की बात हो, बहनों की बात हो या किसानों की बात हो सरकार ने इस चौथे बजट में इन सभी को ठगने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कोई ठोस या स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई देती जिससे साफ होता है कि सरकार जनता को कुछ देने की बजाय आंकड़ों के ज़रिये स्थिति छिपाने की

कोशिश कर रही है। वर्ष 2025-26 में सरकार ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और अबकी बार वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, ये तो सारे प्वाइंट्स पहले भी आ गए हैं। आप जल्दी से अपने चुनाव क्षेत्र के रिलेवेंट प्वाइंट्स के बारे में बताओ।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब वित्त सचिव कह रहे थे कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो इस सरकार ने फिर लोगों को बजट में यह दर्शाने का प्रयास क्यों किया कि हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं? मैं तो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना क्योंकि आज PDNA में 2 हजार करोड़ रुपये हमारे प्रदेश में आए हैं। जितने भी सड़कों के काम हो रहे हैं, बरसात में आपदा के कारण जो सड़कें टूट गईं थीं, उनमें चाहे डंगे, पैच वर्क या सड़कों की टारिंग की बात हो या कल्वर्ट की बात हो, अगर यह पैसा नहीं आता तो प्रदेश में ये सड़कों के काम नहीं होते। इसलिए मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। इन्होंने कहा था कि हम हिमाचल के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं और हमारा इरादा भी पहाड़ जैसा है और हमारा हौसला पहाड़ से ऊंचा है। अध्यक्ष महोदय, जब पेड़ बड़ा होता है तो सभी को अपेक्षा होती है कि उसमें बड़े फल लगेंगे। जब पेड़ बड़ा होता है तो सबको अपेक्षा होती है कि गर्मियों में सभी को छाया मिलेगी। परंतु आज इसके विपरीत इन परिस्थितियों में मुख्य मंत्री जी ने जो बातें यहां रखी हैं, मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री व वित्त मंत्री जी से अच्छे सम्बन्ध बनाए होते तो हम जो यहां पर बार-बार आर0डी0जी0 की चर्चा करते हैं, शायद यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता।

25.03.2025/1750/केएस/वाईके/2

अगर अच्छे सम्बन्ध नहीं बनाते तो उसकी वजह से कई बार नुकसान भी होता है। आपने प्रधान मंत्री जी से बात करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर आप ठीक से बात करते तो शायद अच्छा होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटी-मोटी कठिनाइयां आई हैं

अगर उनको हमने अभी भी सुधारना है तो हमें सभी से अच्छे सम्बन्ध बनाने पड़ेंगे, मिलजुल कर चलना पड़ेगा और प्रदेश और जनता के हित में काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको लोग याद रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात हुई। पिछले बजट में भी कहा था कि हर विधान सभा में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। उनमें 6 स्पैशल डॉक्टर होंगे, वहां एम0आर0आई0 और सिटी स्कैन की मशीन होगी और अनेकों प्रकार के टैस्ट होंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र सरकाघाट एक सैनिक क्षेत्र है परंतु कहां गया वह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान? मेरे क्षेत्र में तो आपने उसको खोला ही नहीं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1755/av/ag/1

श्री दलीप ठाकुर------- जारी

सरकाघाट का होस्पिटल हो चाहे जमली या बलद्वाड़ा का हो, आपने उसको दर्जा देने का प्रयास ही नहीं किया। आप वहां पर स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्ज भेजते हैं और फिर दो महीने के बाद उनका वहां से स्थानांतरण हो जाता है। वहां पर दो वर्षों से अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर नहीं है। आज भी सरकाघाट में ब्लड बैंक नहीं है। वहां पर अनेकों पोस्ट्स खाली हैं। बलद्वाड़ा में डॉक्टर्ज का अभाव है। सी0एच0सी0 जमली में केवल एक ही डॉक्टर है और वह सी0एच0सी0 केवल एक डॉक्टर से चला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सारी बातें यहां पर रखना चाहता हूं। अब मैं पशु पालन विभाग की बात करता हूं। यहां कहा जाता है कि इसके लिए 734 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आप यहां पर राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के माध्यम से एम0एस0पी0 की बात करते हैं। गांवों में मक्की 30 से 40 रुपये बिकती है और सरकार उस आटे को सोसाइटी के माध्यम से 50 रुपये में बेचने का प्रयास करती है जबकि उसको कोई नहीं खरीदना चाहता क्योंकि हमारे प्रदेश में मक्की पैदा होती है। आप

हल्दी की बात करते हैं और हल्दी के रेट 90 रुपये से 150 रुपये कर दिए। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि हल्दी कितने लोगों ने खरीदी है? आपने पिछले वर्ष कहा था कि हम हल्दी का एम0एस0पी0 तय करेंगे जिससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वर्ष में केवल 61 लोगों ने हल्दी खरीदी, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने किसानों ने इसका फायदा लिया। आप लोग गांवों की अर्थव्यवस्था और वहां के विकास की बात करते हैं। मुख्य मंत्री जी, आपने विधायक निधि को कम कर दिया। लेकिन अगर गांवों का विकास करना है तो विधायक निधि को आपको जारी रखना पड़ेगा, तब जाकर गांवों का विकास होगा। इस प्रकार की अनेकों प्रकार की बातें हैं। आपने गांवों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूध के रेट बढ़ाए। आपने दूध का रेट 51 रुपये से 61 रुपये प्रति लीटर कर दिया।

25.03.2026/1755/av/ag/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्वाइंट पर श्री लोकेन्दर कुमार जी बहुत अच्छा बोल चुके हैं।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि आज भी गांवों में भैंस का दूध 80 रुपये और गाय का दूध 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जबकि आपने किसानों से वायदा किया था कि गाय का दूध हम 80 रुपये तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। आप पहले अपने उस वायदे को पूरा कीजिए तब हमारे गांव का किसान खुशहाल होगा। यह सरकार किसानों की चिंता की बात करती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जय राम ठाकुर की सरकार के कार्यकाल में आपकी ओर से बार-बार आरोप लगते थे कि सीमेंट महंगा हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जबसे आपकी सरकार आई है, आपने कितनी बार सीमेंट के रेट बढ़ा दिए हैं? आपने सीमेंट के रेट बहुत बढ़ा दिए हैं।

वर्तमान सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि विधवा और अनाथ बच्चों को खुशहाल बनाने के लिए आप डीजल पर मिलने वाले वैट पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी करेंगे। आपकी

सरकार ने सत्ता में आते ही डीजल के रेट में 7 रुपये की बढ़ोतरी की थी तथा अब आप फिर से 5 रुपये तक और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इन सारी बातों का ध्यान रखें। आपने जो गारंटीज देने की बात की है तो इस बार आपका चौथा बजट है इसलिए आप उन गारंटीज को पूरा करने का प्रयास करें तभी प्रदेश की जनता आपको याद रखेगी। ...(घण्टी) अध्यक्ष महोदय, हमें लास्ट में बुलाया जाता है और फिर 8-10 मिनट्स के बाद घण्टी बजनी शुरू हो जाती है। नये विधायकों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। मैं मुख्य मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो दस गारंटीज दी थीं, आप उनको पूरा करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने यहां पर जो बजट पेश किया है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं तथा मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्य मंत्री टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1800/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि आप बीच में उठकर न जाएं और न ही वॉकआउट करें।

Speaker: Order in the House, please.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान चर्चा में तकरीबन 35 सदस्यों ने भाग लिया और 13 घंटे 50 मिनट तक चर्चा चली तथा सभी माननीय विधायकों ने अपने विचार रखे। परिस्थितियों के अनुकूल जो सरकार का दायित्व था, वह यह था कि प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई रखी जाए। हमने बजट के अनुरूप उस सच्चाई को सभा पटल पर रखा और जनता के सामने भी रखा तथा कोई भी चीज छुपाई नहीं गई। हम भी 20-22 वर्ष से विधायक हैं, हर बार बजट देखते आए हैं और चर्चा करते आए हैं। एक बात हमेशा देखी गई कि जो भी बजट प्रस्तुत किए जाते थे उनमें एक होल होता था। होल का मतलब यह

कि अगर बजट 55 हजार करोड़ रुपये, 56 हजार करोड़ रुपये या 58 हजार करोड़ रुपये का होता था तो 4 से 6 हजार करोड़ रुपये का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता था, लेकिन उसे योजनाओं में दिखा दिया जाता था। मेरा प्रयास था, मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा हुई और यह तय हुआ कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखनी चाहिए। रियल टर्म्स में हमने इस बजट को प्रस्तुत किया और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। विपक्ष के माननीय विधायक कह रहे थे कि बजट का साइज 58 हजार करोड़ रुपये से घटकर 54 हजार 928 करोड़ रुपये हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों बनीं ? जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि आर0डी0जी0 मोदी जी के समय इतनी मिली और वर्ष 1952 से इतनी मिल रही थी लेकिन सवाल आर0डी0जी0 का नहीं है, सवाल सच्चाई का है। आर0डी0जी0 कानून द्वारा दिया गया अधिकार है उन राज्यों के लिए जिनमें व्यय और आय के बीच अंतर अधिक होता है। केंद्रीय करों और राज्य के करों से जो हिस्सा आता है, उसी से इस अंतर की भरपाई की जाती है और जहां यह अंतर अधिक होता है, वहां आर0डी0जी0 के माध्यम से सहायता दी जाती है।

मैं 16वें वित्तायोग के पास 4 बार गया, केन्द्रीय फाइनेंस मिनिस्टर के पास 4 बार गया। मेरे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी और एडवाइजर्स की टीम बैठी तथा पूरी डिटेल तैयार

25.03.2026/1800/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

की गई। हमें यह अंदाजा नहीं था कि हमारी आर0डी0जी0 बंद हो जाएगी। जब आर0डी0जी0 बंद हुई तब हमारी आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं । इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि बजट की सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि मैं बजट के दिन ऑल्टो में आता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 वर्ष तक मैं ऑल्टो में आया।

पहले वर्ष जब मैंने आर्थिक समीक्षा की तो पाया कि इस प्रदेश की संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह एक

सच्चाई है। इस सच्चाई को मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं और उप, मुख्य मंत्री जी एक महीने तक मंत्रिमंडल के साथ लगातार बैठक करते रहे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष एन0एस0 द्वारा ... जारी

25-3-2026/1805/एन0एस0-ए0एस0/1

अध्यक्ष : दुरुपयोग शब्द यूज ठीक रहेगा।

मुख्य मंत्री : हिंदी के सरल शब्द अगर आप मितव्ययिता में बदल देंगे तो हमारा क्या रहा?

अध्यक्ष : मैं कोशिश करता हूं कि चोट कम लगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक महीने तक हमने मंत्रिमण्डल का विस्तार नहीं किया। मैंने पूरी तरह से आर्थिक स्थिति का आकलन किया और उस समय के सचिव, वित्त से बैठकर चर्चा की और जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय प्रदेश में वर्ष 2017-22 तक 70,000 करोड़ रुपये पूर्व सरकार को मिले और फिर भी आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पटरी पर नहीं ला सके। आप लाते भी कैसे? भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता दिल्ली में जाकर कहते हैं कि फ्रीबीज बंद करें। यह वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिए था। आपने क्या किया? पूर्व सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इन्होंने ऐसा जून के बाद किया और तक किया जब चुनाव के लिए 6 महीने रहे थे। आपने पूरे प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। जो लोग पैसे देना भी चाहते थे उनको भी फ्री की। आपने होटल वालों को भी 125 यूनिट बिजली फ्री में दी। परिस्थितियां ये पैदा हुईं। फिर आपने इतने ज्यादा शिक्षण संस्थान खोल दिए। आपका यह सवाल आज लगा था कि कितने शिक्षण संस्थान बंद किए गए। उस समय इन संस्थानों की शीघ्रता में नोटिफिकेशन्ज हुईं और हमने पूछा था कि इन नोटिफिकेशन्ज में बजट प्रावधान है। इन्होंने कहा कि बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है और ये चुनावों से पहले की गई नोटिफिकेशन्ज हैं। श्री बिक्रम सिंह जी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि मैंने दो एस0डी0एम0 ऑफिस खोल दिए। वहां पर न तो अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी और न ही कोई नई रिक्रूटमैंट हुई थी फिर भी संस्थान खुल गए। अध्यक्ष महोदय, जब इनकी

सरकार सत्ता में आई उस समय इनकी सरकार पर लगभग 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम तीन महीनों का आंकड़ा नहीं दिया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये हमारे ऊपर 76,746 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ कर चले गए। यह कहना कि 69, 666 करोड़ रुपये था तो यह गलत है। लोन की रिपेमैंट मार्च में होती है। मेक्सिमम रिपेमैंट मार्च के महीने में होती है और ये सारा कर्ज उस वर्ष की जी0एस0डी0पी0 के

25-3-2026/1805/एन0एस0-ए0एस0/2

आंकड़ों के अनुसार पूर्व सरकार को मिलता था। इनको हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा भेज दिया गया। ये जनता की अदालत में गए, मुफ्त में सब कुछ बांटा है, प्रदेश की संपदा को लुटाया है, चुनाव जीत कर आए और इनकी 25 सीटें आईं तथा हमें प्रदेश की सत्ता मिली। अगर कोई मेरी तीन वर्ष पहले की स्टेटमैंट देखे तो मैंने उस समय कहा था कि प्रदेश की हालत श्रीलंका जैसी है और उस समय श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था। यह हालत किसने की? इन लोगों (विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा) ने की जो ये सामने बैठे हुए हैं। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित किया। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है कि सवा तीन वर्षों के बाद मैं अल्टो को छोड़ कर इलैक्ट्रिकल व्हीकल में आया तो हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम आज आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ रहे हैं? मैं अल्टो के अलावा छोटी गाड़ी में आया हूं और हम हरित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष : यह बहुत अच्छा प्वाइंट बनाया है। You must appreciate it now. जैसे मर्जी बनाया but he has explained it in a very great manner.

मुख्य मंत्री : ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री जी आंकड़े पेश कर रहे थे कि इतना हो गया। कौन-सी ऐसी योजना है जिसमें इन्होंने धन का दुरूपयोग नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, लुटाना भी हिंदी का शब्द है और किताबों में पढ़ाया जाता है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.03.2026/1810/RKS/As-1

मुख्य मंत्री जारी....

आप इस शब्द को बाद में बदलवा देना। अगर अभी आप मेरी शब्दावली को बदल देंगे तो मेरे बोलने की लय भी बदल जाती है। आपने हिमकेयर योजना लाई। हिमकेयर अच्छी योजना थी लेकिन आपने जिस तरह से इसे लागू किया उसका तरीका ठीक नहीं था। प्रदेश में जितने भी निजी अस्पताल थे भले ही उन्हें एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों ने खोला था उन सबकी एम्पैनलमेंट कर दी गई। मैं किसी व्यक्तिगत या विशेष जिले की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन मण्डी जिले में सबसे ज्यादा निजी अस्पताल एम्पैनल्ड किए गए। इसके अतिरिक्त लुधियाना, चण्डीगढ़ और प्रदेश से बाहर कई स्थानों पर भी हिमकेयर योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। शायद हिमाचल के लोग लुधियाना भी अपना इलाज करवाने जाते होंगे। आपने अधिकारियों से इसकी फीडबैक नहीं ली होगी। आप फीडबैक लेने के समय व्यस्त रहे होंगे। हिमकेयर में दिसम्बर, 2022 से फरवरी, 2026 तक कुल 972 करोड़ रुपये मरीजों के उपचार में व्यय किए गए जबकि पूर्व सरकार ने अपने तीन वर्षों में 442 करोड़ रुपये खर्च किए और 3.98 लाख लोगों का उपचार करवाया। इन्होंने आयुष्मान भारत के नाम पर 2100 रुपये से 5 लाख रुपये तक के उपचार मुफ्त करवाने का पैकेज बनाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने एक ही खाते का ऑडिट करवाया है। उसी ऑडिट में हमें 100 करोड़ रुपये से अधिक का घपला नजर आया है। आपने कल विजिलेंस जांच कराने के लिए कहा था, मैंने कल ही इसके आदेश दे दिए हैं। हमने इस योजना के तहत लोगों का उपचार करवाने के लिए मानदंड निर्धारित किए। आज प्रदेश का कोई भी गरीब व्यक्ति अपने उपचार से वंचित नहीं रह सकता। हिमकेयर का पैसा पहली बार आर0के0एस0 मद में चला गया। यानी जो टेस्ट करवाने का 1 हजार रुपये, 2 हजार रुपये या 3 हजार रुपये लगता था, वह सारा पैसा इस मद में चला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर0के0एस0 में ऑडिट करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों की फार्मेसी की दुकानें हैं, वे सब पंजीकृत कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे व्यवस्था देनी है इसलिए कृपया आप बैठ जाइए। आपको चर्चा का जवाब देने में एक घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा इसलिए मैं इस सदन की कार्यवाही को सायं 7:15 बजे तक बढ़ाता हूं।

25.03.2026/1810/RKS/As-2

(सदन की कार्यवाही सायं 7:15 बजे तक बढ़ाई गई।)

मुख्य मंत्री : हमने व्यवस्था परिवर्तन करके निजी अस्पतालों से हिमकेयर योजना को वापस ले लिया। जिन सरकारी अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर हैं वहां हमने हिमकेयर योजना को लागू कर दिया। हमने कहा कि निजी अस्पतालों में लोग डायलिसिस करवा सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम वर्तमान में आर0के0एस0 का ऑडिट भी करवा रहे हैं। हम हिमकेयर योजना की जगह एक बीमा योजना लेकर आएंगे जहां कार्ड के माध्यम से व्यक्ति अपना इलाज करवा सकेगा। मुझे यह समझ नहीं आया कि इनके समय जो आर0डी0जी0 मिली उसे इन्होंने कहां व्यय किया? यहां कहा जा रहा था कि इन्होंने जो एक हजार करोड़ रुपये के भवन बनाए हैं वे खाली पड़े हैं। मैं उन भवनों में कितने दफ्तर स्थानांतरित करूंगा? इतने कार्यालय स्थानांतरित करने के बावजूद भी धर्मशाला में कई भवन खाली पड़े हैं। पालमपुर, ऊना, हमीरपुर और मण्डी में भी कई भवन खाली पड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये भवन किसके लिए बनाए गए थे? ये जो पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं उसमें मैं प्रदेश के धन को लूटने नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं करुंगा कि मैं केवल भवन बनाऊं और पूंजीगत व्यय बढ़ाऊं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

25.03.2025/1815/बी.एस./ए.एस.-1

मुख्य मंत्री जारी...

मैं प्रदेश के धन का सदुपयोग करने के लिए आया हूं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूं। मैं बिल्डिंग बनाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं भी खड़ा कर सकता हूं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी खड़ा कर सकता हूं। फिर देखिए अध्यक्ष महोदय, अभी यह कह रहे थे, अस्पताल के हाल देखिए। आप बोलते हैं कि ये बार-बार यह बोलते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जी के जिले का नेरचौक, मण्डी मेडिकल कॉलेज है। वहां डॉक्टर रखे? दो-चार फैकल्टी के प्रोफेसर भर दिए। मैं कहता हूं कि एम0आर0आई0 की मशीन कहां थी? एम0आर0आई0 की मशीन प्राइवेट में लगाई हुई थी और वहां पर 3000- 5000 रुपये तक एम0आर0आई0 कराने के लिए मण्डी के गरीब लोगों से लिए जाते थे। उस समय के मुख्य मंत्री जी इसे अपने जिले में भी यह नहीं लगवा सके। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई (***) नहीं है। जो मशीन है, मैं नही कहता कि आपने दी, आपने अपने (***) के कहने पर किसी को बाहर मण्डी में दे दी। लोगों का एम0आर0आई0 की मशीन के लिए 3000-5000 रुपये खर्च आ रहा है। हमने चारों एम0आर0आई0 मशीने लगाने का आर्डर दे दिया है और जल्दी ही लग जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष फिर खड़े हो गए। ये बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जो (***) के बारे में कह रहे हैं ये उनका नाम भी बताएं कि किस (***)की बात कर रहे हैं। आप हवा-हवाई बातें कर रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके साढ़े तीन साल हो गए आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?

अध्यक्षः ठाकुर साहब, कृपया शांत हो जाइए। मुख्य मंत्री जी अपनी बात कहें।

मुख्य मंत्री : ठाकुर साहब, कृपया आप बताइए कि नेरचौक के बाहर एम0आर0आई0 मशीन लगी है? यह सच्चाई है और यह आपके समय में लगी है।

25.03.2025/1815/बी.एस./ए.एस.-2

श्री जय राम ठाकुर : हमें इस बारे में क्या मालूम? हमने पूरा प्रयास किया, हमने टेंडर किया और आपने उसे केंसिल किया और साढ़े तीन साल से कोई मशीन नहीं लगी।

मुख्य मंत्रीः आपने ऐसा कोई टेंडर नहीं किया।

अध्यक्षः प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। मुख्य मंत्री जी आप अपने प्वाइंट पर जाइए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रयास किया, ऑर्डर दे दिया हैं और अब आ जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्य मंत्री जी से यह पूछिए कि ये पांच साल तक मुख्य मंत्री रहे, बाहर से क्यों एम0आर0आई0 होती रही?

श्री जय राम ठाकुर : आपको भी साढ़े तीन साल हो गए क्या आप इसे लगवा पाए?

मुख्य मंत्री : पूर्व मुख्य मंत्री जी आप गुस्सा मत करिए। यह झूठ नहीं है यह तो सच्चाई की परते खुल रही है। आप एक बात सुनिए कि आपके कार्याकाल में एम0आर0आई0 मशीन मण्डी में नेरचौक के मेडिकल कॉलेज के बाहर लगी थी या नहीं? यह सच्चाई है न।

श्री जय राम ठाकुर : हमें क्या मालूम।

मुख्य मंत्री : यदि आपको पता नहीं है तो मैं पता दे दूंगा, यह सच्चाई है।

श्री जय राम ठाकुर : मुझे आज तक नहीं मालूम कि किसकी एम0आर0आई0 मशीन है। (***)

25.03.2025/1815/बी.एस./ए.एस.-3

मुख्य मंत्री : (***)। अगर इन्हें मालूम नहीं तो मैं एड्रेस भिजवा दूंगा। ठीक है और कहां लगी है वह भी बता दूंगा।

श्री जय राम ठाकुर : हमारा ऐसा (***) नहीं है।

मुख्य मंत्री : अच्छा ठीक है आपका (***) नहीं है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1820/डीटी/डीसी-1

अध्यक्ष : आपके और इनके द्वारा प्रयोग किए गए (***) शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ...(व्यवधान) मैंने (***) शब्दों को कार्यवाही से हटाने के आदेश दे दिए हैं। ...(व्यवधान) कृपया अपनी सीट में बैठ जाइए। दोनों ओर से (***) प्रयोग किए गए शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।...(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। इसके बाद आपको और बढ़िया अवसर मिलेगा। कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आज मैंने आपको 25 मिनट का बोलने का समय दिया है। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी चीजें मत करवाइए जिसके कारण इस सदन की गंभीरता कम हो जाएं। किसी चीज को सुनने और बोलने की एक सीमा होती है। ये दोनों सीमाएं सिर से ऊपर चली गई है। मुख्य मंत्री जी हर बार लूटाने की बात करते हैं। इस शब्द को सुनते हुए साढ़े तीन वर्षों से हमारे कान पक गए हैं। लूटा दिया, लूटा दिया, कहां लूटाया आप हमें बताएं कि हमने कहां गलत किया है? अगर हमने गलत किया है तो आपने साढ़े तीन वर्षों में काई कार्रवाई क्यों नहीं की है? हम इसे फेस करने के लिए यहां बैठे हैं। आज हमारे ऊपर बिना वजह के आरोप लगा रहे हैं। क्या यह मैं तय कर सकता हूं कि किस प्राइवेट होस्पिटल में एम0आर0आई0 या सिटी स्कैन लगाई जाए। क्या आप इस बात को तय कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं? आप कहते हैं कि मेरे (***) ने एम0आर0आई0 मशीन लगाई है। मुझे खुद नहीं मालूम कि वह कौन है और कितनी मशीनें लगाई है। इस प्रकार से प्रदेश के खजाने को लूटाने की बातें करना उचित नहीं है। जब यह कहा जाता है कि यह सब (***)के लिए किया गया तो पीड़ा स्वाभाविक रूप से होती है। यह आरोप बेबुनियाद है। हमारे पास तथ्य के आधार पर आरोप लगाने के लिए बहुत सारी

बाते हैं लेकिन हम अभी तक सब्र रखे हुए हैं। हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिट में सौ करोड़ रुपये से ऊपर का घपला हुआ है। आप इस तरह की स्थिति जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं ताकि कुछ आरोप लगाए जा सकें। इसमें विपक्ष और मुझे टारगेट किया जा रहा है। अगर आप बिना तथ्य से बोलेंगे तो

25.03.2026/1820/डीटी/डीसी-2

ठीक नहीं है। आप जो 100 करोड़ रुपये के घपले की बात कर रहे हैं उसमें आप तथ्यों के साथ आईए। आपने जिसके खिलाफ और जैसी जांच करनी होगी उसमें हम आपको पूरा सहयोग करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत स्पष्ट है। आप थोड़ी शांति रखिए। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी और

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

25.03.2026/1825/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री..... जारी

एम0आर0आई0 भी लगा रहें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये मशीनें ऐसे ही लग जाती थीं। इनके समय में न कोई ऑर्डर हुआ, ठीक है, वह इनका (***) नहीं होगा लेकिन नेरचौक मेडिकल कॉलेज के बाहर एक एम0आर0आई0 मशीन लग जाती है और वहां पर लोगों से एक एम0आर0आई0 के 3 से 5 हज़ार रुपये लिए जाते थे। वह क्यों हुआ और मैं किस के संदर्भ में कह रहा हूं? वह सब हिमकेयर योजना का लाभ लेने के लिए हुआ क्योंकि हिमकेयर योजना में जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे, उन सभी को पूर्व सरकार ने इसके साथ अटैच किया था। हमने विपक्ष पर कोई आरोप नहीं लगाया है लेकिन हमने कहा

कि आपकी सरकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत इस प्रकार के कार्य हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 450 करोड़ रुपये पूर्व सरकार के समय में और 750 करोड़ रुपये हमारी सरकार के समय में यानी कुल 1100 करोड़ रुपये हिमकेयर योजना में व्यय किया गया।...(व्यवधान)है। हमने इस व्यवस्था को सुधारा है।...(व्यवधान) मैंने कहा है कि इन 1100 करोड़ रुपये को लूटने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि हम इनके स्थान पर मशीनें खरीदेंगे और अपने डॉक्टर्स को स्ट्रेंथन करेंगे।...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हिमकेयर योजना में 1100 करोड़ रुपये लूटा गया है। ये इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं?...(व्यवधान) आप कार्रवाई कीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने दुरुप्योग बोला है।...(व्यवधान) इन्होंने कहा है कि हिमकेयर योजना का दुरुप्योग हुआ है।...(व्यवधान)

(विपक्ष के कुछेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्य मंत्री जी से उनके द्वारा हिमकेयर योजना में लगाए गए आरोप के संदर्भ में जवाब मांगने लगे।)

25.03.2026/1825/एच.के.-एन.जी./2

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा, आप बैठ तो जाइए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने स्कीम का दुरुप्योग हुआ बोला है।...(व्यवधान) बता रहे हैं।...(व्यवधान) आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैं बता रहा हूं कि कैसे दुरुप्योग हुआ।...(व्यवधान) आप लोगों ने नहीं सुनना है तो बाहर चले जाइए। मैं बाद में बोल लूंगा।...(व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो शोरगुल लगे।)

Speaker : Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please, please. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी लगातार विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहें हैं और अब यह बर्दाशत से बाहर हो गया है इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए माननीय सदन से बहिर्गमन कर गए।)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो जाना ही था। यदि आप मुझे पहले बुला लेते तो थोड़ा जल्दी हो जाता। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने 100 करोड़ रुपये की जनता की संपदा लुटा दी है। अभी समस्या क्या है? अभी समस्या यह है कि हम जो मशीनें ले रहे हैं, वे हाई-एंड मशीनें ले रहे हैं। हम कौन-सी मशीनें ले रहे हैं? वही मशीनें ले रहे हैं जो एम्स में खरीदी गई हैं। उनकी कीमत क्या है? वही कीमत है जो एम्स में तय की गई हैं। हम जो मशीनें ले रहे हैं वे भारत सरकार की कंपनी के माध्यम से ले रहे हैं।

25.03.2026/1825/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर बनने की विपक्ष के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर प्रदेश तब बनता है जब प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 बढ़ रही हो और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने प्रदेश की दिशा को तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसका उदाहरण पिछले तीन सालों के परिणाम हैं

कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,73,000/- रुपये थी और आज बढ़कर लगभग 2,83,000/- रुपये हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, जब व्यवस्था परिवर्तन होता है और नीतिगत परिवर्तन होता है, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। पूर्व मुख्य मंत्री जी जब मुख्य मंत्री थे, तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज के पास एक प्राइवेट व्यक्ति ने एम0आर0आई0 की मशीन लगा दी है। हो सकता है इन्हें सच में न पता हो क्योंकि मुख्य मंत्री काफी बिजी होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और यह बात मैं आज फिर से कह रहा हूं। हमने पहले अपनी सरकार की तरफ से ऑडिट करवाया। अब हमने विजिलेंस विभाग को लिखकर दिया है और विजिलेंस विभाग अब उसकी इन्क्वायरी करेगा। जब उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, तो हम उसे आपके सामने रखेंगे। पूर्व सरकार को लगभग 70,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कम्पनसेशन व आर0डी0जी0 के रूप में मिला।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

25.03.2026/1830/एच0के0/ए0पी0/-01

मुख्य मंत्री जारी ....

हमें जी0एस0टी0 कंपंसेशन का कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर ये फाइनेंशियल प्रूडेंस के अनुसार कार्य करते, फिस्कल डिसिप्लिन के अनुसार कार्य करते तो पूर्व में वर्ष 2017 में 48 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। इनकी सरकार अगर 70 हजार करोड़ रुपये में से अगर 40 हजार करोड़ रुपये कर्ज भी दे देते तो प्रदेश पर आठ हजार करोड़ का कर्ज चढ़ा होता। अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री जी कर्ज के आंकड़े बता रहे थे। मैं आपको इनके कर्ज के आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 के दौरान इनके समय में राज्य सरकार ने 45,251 करोड़ रुपये का कुल ऋण उठाया। उस समय इन्होंने वापस कितना किया? अध्यक्ष महोदय, 38,723 करोड़ रुपये का ऋण वापिस किया गया और

इसमें मूलधन 16,525 और 22,198 का था। हमारे समय में वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 (इस महीने के अंत तक) हमने कुल ऋण 37,000 करोड़ रुपये का उठाया और इसमें से 28,340 करोड़ रुपये वापिस किये। हमने इनसे ज्यादा ऋण वापस किया है। जब हमारे पास 17,000 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 आती थी तो हमने औसतन 4,500 करोड़ रुपये का ऋण हमारी सरकार ने हर साल वापिस किया है। इन्होंने 7,750 करोड़ रुपये हर साल वापस किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ऋण भी ज्यादा वापिस कर रही है। यही प्रदेश की आत्मनिर्भरता की सच्चाई है। हम हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहे हैं।, वहीं पर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव ला रहे है। इनके समय प्रदेश की संपदा को लूटा दिया गया। अब लूटाना शब्द तो बोल सकता हूं।

अध्यक्ष : अब तो आप जो मर्जी बोलो।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय प्रदेश की संपदा को लूटा दिया गया। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, 70,000 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 थी। फिर भी उन्होंने पांच हजार बीघा जगह एक रुपये के हिसाब से कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत प्रदेश की उस संपदा को भी लूटा दिया। हिमकेयर योजना के रूप में 100 करोड़

रुपये लूटा दिए गए। तकलीफ इन्हें तब हो रही है जब आज हमारी सरकार उसकी गहराई तक जा रही है। हमारी सरकार जनता के सामने इनके सब सत्यों को लाना चाहती है जो इनकी सरकार के समय प्रदेश की संपदा को लुटाया गया है। निश्चित तौर पर मुझे पता था कि जब मैं बोलूगां तो इन्होंने वॉकआउट करना है। मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे हेल्थ सेक्टर में भी काफी सुधार हुए हैं। इस बजट में हमने क्या दिया? इस बजट में उस गरीब की आवाज को शामिल करने की कोशिश की गई है जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। कभी मछुआरों ने सोच भी नहीं होगा कि उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन आएगा। सरकार उनसे उनकी कमाई का 15 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी लेती थी। मैं मछुआरों से मिला, वे मेरे पास विधान सभा में मिलने के लिए भी आए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम सौ रुपये दिन का कमाते हैं तो उसमें से पंद्रह रुपये हमें सरकार को देने पड़ते हैं। पिछली बार जब वे

मुझसे मिलने आए तो हमने उनकी रॉयल्टी 7.5 प्रतिशत कम कर दी। इस बार वे फिर दोबारा मिलने आए तो हमने एक प्रतिशत रॉयल्टी कर दी ताकि उनके जीवनयापन में सुधार हो सके। यह भी कहा कि जो उनकी नौका है, जिस नौका से वे सुबह चार बजे मछली पकड़ने जाते हैं। तकरीबन दस-से-पंद्रह हजार परिवार इस दिशा में कार्य करते हैं। उनकी नौकाएं टूटी हुई हैं वे सब अपनी जान जोखिम में डालकर सुबह चार बजे मछली पकड़ने जाते हैं। हमने कहा कि उनकी नौका पर भी हम 70 प्रतिशत सब्सिडी देंगे और नेट पर भी सब्सिडी देंगे। बरसात में जब दो महीने उनकी कमाई का साधन बंद हो जाता है तो हमने कहा कि हम मुख्य मंत्री सम्मान योजना के तहत उन्हें 3,500 रुपये प्रति माह देंगे। ये बजट उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए था। कई सालों से कई परिवार आई0आर0डी0पी0 में हैं। 11,000 परिवार जो पिछले 20 वर्षों से आई0आर0डी0पी0 में थे। वे कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उसमें 16,000 अतिरिक्त परिवार को मिलाया गया और अब 27,000 परिवार कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था विपक्ष के साथियों से जिसमें मुख्य मंत्री अपना परिवार सुखी योजना लेकर आए हैं। मैं इनसे सुन रहा था कि 300 यूनिट बिजली कैसे देंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.03.2026/1835/AT/YK/01

मुख्य मंत्री जारी....

1500 रुपये कैसे देंगे इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि हम गरीबों को ऊपर उठा रहे हैं बल्कि तकलीफ इस बात से है कि हमने इसी बजट में अपनी सारी गारंटियां पूरी करनी और कर दी हुई है। हमने अपनी गारंटियों की शुरुआत गरीबों से की है। हम 300 यूनिट बिजली गरीबों से शुरू कर रहे हैं और धीरे-धीरे व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इन सभी गारंटियों को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा प्रिस्क्रिप्शन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट में कभी कोई कल्पना कर सकता था कि हमें पीने का पानी किस तरह का दिया जाता है? हम क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर डालकर ठेकेदार को ठेका देते थे। बड़े-बड़े टैंक बनते थे, एक-दो बोरी डाल दी जाती थी और पूरे पानी में स्मेल रहती थी। आप होलिडे होम का खाना खाए, उसमें पानी की स्मेल, घर में खाना बनाए, चपाती में पानी की स्मेल। पहली बार हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए माननीय उप-मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद, वर्ल्ड क्लास वाटर क्वालिटी टेक्नोलॉजी की ओर कदम बढ़ाया गया है। इसके लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कैसे संभव हुआ और इसका पता कैसे चला? हमने डॉक्टरों के साथ इंटरैक्शन किया मेडिकल कॉलेज मंडी, चंबा, आईजीएमसी, टांडा, नाहन हर जगह 2-3 घंटे बैठकर चर्चा की। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और जोनल हॉस्पिटल्स के डाक्टरों के साथ भी बातचीत की। हमें पता चला कि हमारी ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 लगभग 2 करोड़ के करीब है। मैंने उनसे पूछा क्या पूरा हिमाचल प्रदेश बीमार है? 75 लाख की जनसंख्या में हर व्यक्ति किसी-न- किसी अस्पताल में जा रहा है इसका कारण क्या है? इन सभी कारणों का आकलन करने के बाद हमने कहा कि हम ऐसी दृष्टिकोण अपनाएंगे जिससे प्रदेश की जनता को अच्छा पानी मिले और अच्छा खाने की सुविधा मिले। इसी दृष्टिकोण से हमने तय किया कि अगले पांच वर्षों में ओजोनाइजेशन और गैसीय क्लोरीन तकनीक के माध्यम से पूरे प्रदेश को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव-गांव तक साफ पानी उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए शिमला नगर निगम क्षेत्र में पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिससे लोगों को वर्ल्ड क्लास पानी

25.03.2026/1835/AT/YK/02

मिलेगा। जहां लोग ताज़ी हवा के लिए आएंगे और वहां अब क्वालिटी वाटर के लिए भी आएंगे।

अब सवाल है कि हम खा क्या रहे हैं? इस बजट में हमने यह दर्शाने की कोशिश की है कि हम क्या खा रहे हैं। हम खाना खाकर पेट भरके चले जाते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं? इसलिए हमने देश और राज्य की पहली स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी

की बैठक की और उसके लिए पोस्टें भी सैंक्शन की हैं। इसके साथ ही हम जल्दी ही न्यूट्रिशन पॉलिसी ला रहे हैं, जिसमें तय किया जाएगा कि डिपो में किस क्वालिटी का राशन दिया जाना है और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला खाना हम देने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि दो रुपये किलो का आटा और तीन रुपये किलो का चावल खाते-खाते पूरा समाज बीमार हो जाए। हम क्या खा रहे हैं यह जनता नहीं सोचती, यह हमारी सरकार सोच रही है। लेकिन जब सरकार इस तरह से सोचती है, तो उसे ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। इस बजट में उसका आंकलन किया गया है। सड़कों के क्षेत्र में भी, अगर PMGSY की बात करें तो ये अपने समय में पांच साल के अन्दर कुछ नहीं लाए। PWD मंत्री और उनके साथ हम सबने प्रयास किया और तीन साल में इनसे ज्यादा धन लेकर आए हैं और यह बात कर रहे थे PMGSY की। सड़कों पर हम तेजी से काम करवा रहे हैं। ये बी0जे0पी0 के लोग सिर्फ जनता के पास जाकर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और फिर इस सदन से वॉकआउट करके चले जाते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी प्रधानमंत्री जी के पास गए लेकिन उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर एक भी बयान नहीं दिया। क्या उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की बात की? ये लोग वहां जाकर मुंह नहीं खोल सकते। फिर जनता इन्हें वोट क्यों देगी? यह मुंह नहीं खोल सकते और इनके अन्दर कोई हिम्मत तक नहीं है। अभी उप-मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं तो कोई चिट्ठी यहां पर रख दो। अगर वे चार दिन बाद चिट्ठी रखेंगे तो वो भी झूठी ही होगी। अगर आपको प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मौका मिला है तो आप 1500 करोड़ रुपये की बात क्यों नहीं की? फिर ये सोचते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। अध्यक्ष महोदय, ये सत्ता परिवर्तन का ख्वाब लेकर चले हैं। मैं कहना नहीं चाहता, ये भूल जाएंगे

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

25.03.2025/1840/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी ---

जब अपने नेता के पास किसी के अंदर ताकत ना हो, नैतिकता खत्म हो जाए, वह विपक्ष द्वारा रिपीट नहीं कर सकता। जो अपने नेता के सामने यह नहीं बोल सकते कि प्रदेश की वर्ष 1952 से मिली हुई आर0डी0जी0 बंद कर दी गई, इस प्रदेश के लोगों का अधिकार बंद

कर दिया गया, वह जनता की समस्याओं का क्या समाधान करेंगे? जो हम इनके सामने गलत काम ला रहे हैं, ये उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। इन्होंने रोबोटिक सर्जरी के बारे में कहा लेकिन ये बताएं कि इन्होंने कागज क्यों नहीं रखे? मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने चार रोबोटिक सर्जरी खरीदीं उसमें वेरिएशन का हमारे पास अधिकार है कि हम उसी में 2 की जगह 4 खरीद सकते हैं। अगर आज भी इनके पास रोबोटिक सर्जरी के कागज हैं, हमने दो ऑर्डर देने हैं, 28-29 करोड़ में देने को तैयार हैं तो हम उनको ऑर्डर दे देंगे। लेकिन इनको आकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार दिशा तय करके चलती है और दिशा में अडिग रहती है इसीलिए हमें 17 हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 मिलने के बाद भी आज हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूती से बनी हुई है। यह जो हमने 6 महीने के लिए डेफर किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमारे कर्मचारी, विधायक और मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं, चाहे विपक्ष के विधायक भी हैं, हम सभी लोगों ने एक नैतिकता का परिचय दिया है कि ऐसी परिस्थिति में जब आर0डी0जी0 कटी है तो हम लोग आपके साथ हैं, प्रदेश की जनता के साथ हैं। बिजली बोर्ड को इनके समय से 2200 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती थी। आज मैंने उसको कम करके 1200 करोड़ रुपये पर लाया। हमने आज ही एक और फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी 22-23 लाख परिवार हैं, उनको एक परिवार को 2 मीटरों पर सब्सिडी मिलेगी, बाकी सभी मीटरों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्योंकि वे चाहते ही दो परिवार हैं। अध्यक्ष महोदय, आप चम्बा की बात कर रहे थे। आपको पता है कि मैडिकल कॉलेजों में हम 192 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। पहली बार आपके चम्बा में ढंग से मैडिकल कॉलेज शुरू होगा, नाहन का मैडिकल कॉलेज ढंग से चलना शुरू होगा। वहां पर पी0जी0 की क्लासें ही नहीं हैं। फैकल्टी ही पूरी नहीं है। हमने नाम के प्रोफैसर भर रखे हैं। एक प्रोफैसर और एक एसोसिएट प्रोफैसर है। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 120 है। उस दृष्टिकोण को भी हमने मैडिकल

25.03.2025/1840/केएस/वाईके/2

हैल्थ सिस्टम में सोचा और 40 साल में 270 पी0जी0 बने थे, हम 1 साल के अंदर 275 पी0जी0 की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। हर चीज़ में बदलाव है। फोरैस्ट में जाइए, वहां

बदलाव है। हैल्थ में बदलाव है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है, डिपार्टमैंट ऑफ रिक्रूटमैंट बनाया है। अभी ये 374 लोग बोल रहे थे, ये इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे थे, ये पढ़ते नहीं हैं। उसमें 2374 लोगों को अनइम्प्लॉयमेंट अलाउंस 1500 रुपये के हिसाब से मिला है जो मैंशन किया है और ये बोल रहे हैं 374 लोगों को रोज़गार मिला। ये चीजें सोचने वाली हैं कि हम किस प्रकार व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश को आत्मनिर्भर करने जा रहे हैं। मैं अपने माननीय सदस्यों को इस बार यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह तकलीफ़ नहीं है, यह हमारा प्रतीक है कि हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस परिकल्पना को ले कर हमारी सरकार चली है, निश्चित तौर पर वर्ष 2032 में हम आत्मनिर्भर के अलावा समृद्धशाली प्रदेश बनेंगे। अगर प्रदेश की 8 हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 नहीं काटी होती तो एक वर्ष पहले ही हम आत्मनिर्भर बन गए होते लेकिन फिर भी हमने वर्ष 2027 में कमिटमैंट की है। हम नौकरियां दे रहे हैं, डी0ए0 दे रहे हैं लेकिन कई बार हमें एक परिस्थिति के अनुसार फैसला करना पड़ता है। उसके अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, इसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई शुरू है। अभी हमने हाई कोर्ट में हमारी लैंड रेवन्यू में पिछले कल पेशी थी। हमने कहा हमें पास थ्रू दीजिए, अगर हमारा लैंड रेवन्यू लग जाता है तो इस प्रदेश के पानी से जो हमारी सम्पदा है उससे हमें हर साल लगभग 1800 करोड़ रुपये की आय होगी। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हम बंद करेंगे। वह कैसे बंद होते हैं, जो चीज़ इनके समय में 10 रुपये की होती थी, इनके समय 50 रुपये की खरीदी गई। हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

25.03.2026/1845/av/ag/1

मुख्य मंत्री------- जारी

हम तब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कभी कोई कल्पना कर सकता था कि किसान कौन है और किसान को कैसे काम पर लगाना है। जिस प्रदेश के पास सिर्फ 32 प्रतिशत लैण्ड हो और कृषि क्षेत्र में

महज 20 या 22 प्रतिशत लैण्ड हो तथा उसमें भी मात्र 10 प्रतिशत पर किसान कार्य करते हों; उसमें एक नीतिगत सोच के साथ बदलाव लाया गया। आंकड़े तो बहुत ज्यादा प्रस्तुत होते हैं परंतु मैंने आज फैसला किया है कि जिन लोगों की हल्दी पिछले वर्ष 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी थी उसको इस वर्ष दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से डेढ़ सौ रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाएगा। इसके अतिरिक्त गेहूं और मक्की 80 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब खरीदी जाएगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा प्रदेश ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अदरक अर्की और सिरमौर के क्षेत्रों में होता है। मेरी इस बारे में माननीय उद्योग मंत्री और माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी से बात हुई है। हमारी सरकार अदरक का समर्थन मूल्य भी देने जा रही है। किसानों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में लहसुन भी होता है। हम इसी वर्ष लहसुन का समर्थन मूल्य भी देंगे ताकि हमारे किसानों को इससे इन्कम प्राप्त हो। हम जब इस बारे में समर्थन मूल्य तय करेंगे तो वह पैसा हमारे किसानों के हाथों में सीधा जाएगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में एक गति आएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तीन वर्षों में प्रति कैपिटा इन्कम 2.83 लाख रुपये बढ़ना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह इतने वर्षों में क्यों नहीं बढ़ी?

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, कृपया गुरनु चाय को भी सपोर्ट प्राइस में शामिल कर लीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय ने गुरनु चाय को सपोर्ट प्राइस में शामिल करने की बात की है तो मैं आप से सहमत हूं। **लहसुन के साथ-साथ गुरनु चाय को भी सपोर्ट प्राइस में शामिल कर लेंगे।** आपकी बात को कोई टाल सकता है?

25.03.2026/1845/av/ag/2

हमने नई इण्डस्ट्रीयल पॉलिसी लाने की बात की थी। हमारे विपक्ष के साथी पूछेंगे कि आप इण्डस्ट्रीयल पॉलिसी क्यों नहीं लाए। मैं बताना चाहता हूं कि हमने उसी इण्डस्ट्रीयल पॉलिसी में संशोधन कर दिया है। हमने जब यह देखा कि किसी को एक बीघा

जमीन एक हजार रुपये में मिल रही है तो वह इण्डस्ट्री के नाम पर जगह ले लेगा। इनके समय में एक बीघा जमीन एक हजार रुपये में दी जाती थी। इसी तरह से उसमें दस वर्षों के लिए तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाती थी। इनके कार्यकाल में इस प्रकार कस्टमाइज पैकेज था। उस समय बोला जाता था कि आप एक बीघा जमीन एक हजार रुपये में ले लीजिए और इसके लिए रजिस्ट्री करवाने की भी जरूरत नहीं है तथा स्टैम्प ड्यूटी भी फ्री होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रकार से इस प्रदेश को लुटाने का काम किया है। लेकिन मैंने उसमें सुधार किया है। मैंने कहा कि किसी ने पूरे मार्किट रेट में प्लॉट लेना है तो ले लीजिए और बिजली भी कोई सस्ती नहीं मिलेगी। हमने इनकी इण्डस्ट्रीयल पॉलिसी में इस प्रकार के पहले ही बदलाव कर दिए थे। हम यहां पर वे इण्डस्ट्रीज लाएंगे जिनसे हमारे प्रदेश को फायदा होगा। हम टूरिज्म सेक्टर, डेटा सेंटर और डेटा स्टोरेज में इन्वैस्ट करना चाहते हैं। हम नये शहर बनाना चाहते हैं जिससे हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं दुबई के बारे में पढ़ रहा था कि वह वर्ष 1971 में यू0ए0ई0 का हिस्सा बना था। उसकी जनसंख्या भी लगभग हमारे प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है तथा इसके अलावा पांच नदियां तथा 68 प्रतिशत भूमि पर जंगल हैं। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास देश में सबसे पढ़ी-लिखी जनता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.380 प्रतिशत है। यहां पर केवल दिशा की कमी थी। उस दिशा को हमारी सरकार ने पकड़ा और उस पर आगे बढ़ते हुए हम आज तभी आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। हमने हर चीज में परिवर्तन किया है और यह सब व्यवस्था परिवर्तन के कारण हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन में फैसले लेने पड़ते हैं और जनता की सोच को अपनाना पड़ता है। जनता कैसे सोचती है, उस दिशा में सोचकर अपनी रणनीति को बदलकर नई रणनीति को लाना पड़ता है और इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। यहां पर जोर-जोर से चीख कर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन तो काम करके होता है।

टी सी द्वारा जारी

25.03.2026/1800/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्री ... जारी

व्यवस्था परिवर्तन में फैसले लेने पड़ते हैं, जनता की सोच को अपनाना पड़ता है। जनता किस दिशा में सोचती है, उसी अनुसार रणनीति बनानी पड़ती है और नई योजनाएं लानी पड़ती हैं। जोर-जोर से बोलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता,काम करके व्यवस्था परिवर्तन होता है। हमने कहा था कि एक वर्ष के अंदर जब अगला बजट प्रस्तुत करुंगा तो मेडिकल कॉलेज में कोई वैकेंसी खाली नहीं रहेगी और हाइएंड टैक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज में होगी। हम अगले वर्ष तक 100 प्रतिशत नहीं तो 80 प्रतिशत तक लक्ष्य पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया गया है और हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। जो व्यवस्था 40-45 वर्षों से चली आ रही है उसे बदलने में समय लगता है उसे धरातल पर उतारने में समय लगता है लेकिन खुशी इस बात की है कि हम उसे धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं, विरोध भी हुआ लेकिन कर्मचारी वर्गों ने हमारा साथ दिया। आज हम पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, अध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं, डॉक्टर्ज की भर्ती कर रहे हैं, स्टाफ नर्सिज की भर्ती कर रहे हैं, अस्सिटेंट फोरेस्ट गार्ड और पटवारी की भर्ती कर रहे हैं। जहां-जहां रोजगार की संभावना है वहां रोजगार पैदा किये जा रहे हैं। पहली बार इस प्रदेश में ओवरसीज डिपार्टमैंट बनाया गया और सरकार के माध्यम से युवाओं को बाहर के देशों में रोजगार के लिए भेजा जा रहा है। यही सरकार की दृढ़ नीति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जितना हमारे पास धन था उस धन के अनुसार हमने कार्य किया। इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज जो विधायक निधि कटी है उसे परिस्थितियां अनुकूल होने पर भविष्य में बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। अगर विपक्ष सहयोग करेगा और सत्ता पक्ष के निर्णयों को आगे बढ़ाने में साथ देगा तो हम प्रदेश को और आगे ले जाएंगे। जिस प्रकार विपक्ष आर्थिक संकट का ढिंडोरा पीट रहा है इन्हें शर्म आनी चाहिए और कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आ गया है, financial emergency की बात कर रहे हैं, जहां नौकरियां दी जा रही हैं, जहां सैलरी समय पर मिल रही है, पेंशन समय पर मिल रही है, वहां financial emergency कैसे हो सकती है? डेफरमैंट का मतलब यह नहीं है

25.03.2026/1800/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

कि सैलरी रोकी गई है या सैलरी में कटौती की गई है। यह निर्णय कर्मचारियों से चर्चा के बाद ही लिया गया है।

कल सोशल मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में यह बात फैलाई गई कि 5 रुपये सेस लगा दिया गया। हमने केवल विधान सभा से अधिकतम 5 रुपये लगाने का अधिकार लिया है। इसे लगाना या न लगाना परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक्ट बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम वैट बढ़ाकर भी 5 रुपये ले सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर वैट बढ़ता तो पैसा ट्रेजरी में चला जाता। हमने ऐसा तरीका चुना जिससे विधवा बहनों और अनाथ बच्चों को सीधा लाभ मिले और उनका अधिकार सुरक्षित रहे। यह सेस उसी उद्देश्य के लिए रखा गया है ताकि यह राशि उन्हीं बच्चों पर खर्च हो। कानून के अनुसार वह बच्चा कोर्ट में जाकर भी अपने अधिकार की मांग कर सकता है। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के बयान दे रहे हैं जबकि अभी एक्ट बना है और नोटिफिकेशन बाकी है। ऐसी बातें प्रदेश के हित में नहीं होतीं। ये पैट्रोल पंप वालों से मिले होंगे लेकिन मैंने उसको इसलिए रखा कि अगर हम इस स्कीम के तहत रहेंगे तो सेस उन्हीं बच्चों के ऊपर खर्च होगा और कोई भी अनाथ बच्चा जा करके बोल सकता है कि सरकार ने मुझे अधिकार दिया है। मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए उस अधिकार को हमने सुरक्षित रखा है। नहीं तो हम इसे ऐसे ही लगा सकते थे। लेकिन दिल्ली से एक न्यूज चल रही थी, पूर्व में एक वित्त मंत्री रहे हैं मुझे बोलना तो नहीं चाहिए परंतु वे कुछ और ही बोल रहे थे। वे कैसे वित्त मंत्री थे? जिन्हें पता नहीं लगता कि अभी एक्ट बनना है और इसकी नोटिफिकेशन होनी है। ये चीजें कहना प्रदेश के हित में नहीं होती। हम प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हैं, हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए आए हैं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

25-3-2026/1855/एन0एस0-ए0एस0/1

मुख्य मंत्री ---------

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार महिलाओं के सम्मान की आवाज बन कर आई है। अभी 1 लाख लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और 1500 रुपये तो हम महिलाओं को दे ही रहे हैं। आगे-आगे देखिए होता है क्या? इसी बजट वर्ष में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और वर्ष 2032 में हम प्रदेश को सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे। विपक्ष को बड़ी तकलीफ़ होती है और कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन विपक्ष को इस बात की तकलीफ़ होती है कि प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है और ऐसी वित्तीय स्थिति में भी प्रदेश कैसे चल रहा है? विपक्ष केंद्र में जाकर कभी आर0डी0जी0 रुकवा देता है, कभी मनरेगा के पैसे रुकवा देता है। मैं तो आज ही का सोच कर चलता हूं और यह मेरे स्वभाव में है। मैं आज के लिए मुख्य मंत्री हूं, यही सोच कर चलता हूं। मैं कल की कभी नहीं सोचता। आज अच्छा फैसला कर जाऊं, मेरे जीवन का सुकून और मेरे जीवन का कर्म यही है। मैं बहुत जनूनी आदमी हूं और मैं जनून के साथ काम करता हूं। अधिकारी भी जानते हैं कि मैं सवेरे 6.00 बजे, 7.00 बजे कभी भी फोन कर सकता हूं लेकिन अगर प्रदेश-हित में कोई कुठाराघात करे तो उसका मेरे मन में बहुत दर्द होता है। इन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया इसलिए मेरे मन में बहुत दर्द है। इन चीजों को हम आने वाले समय में प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्य मंत्री जी और इनके साथी बोल नहीं पाते लेकिन इनसे अच्छा तो मैं स्वयं बोल लेता हूं तथा प्रदेश के लिए अच्छी धनराशि ले आता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं जब भी वित्त मंत्री जी से मिलता हूं उनसे भी मैं अच्छी धनराशि ले आता हूं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। ये अभी नीचे सुन रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय, दूध का डेढ़ लाख लीटर का प्रोसैसिंग यूनिट इस वर्ष सितम्बर माह में स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटी मिल्क मिलेगा। दहीं, घी और मक्खन भी क्वालिटी का मिलेगा। उसमें फैट की रेशो मापी जाएगी। एस0एन0एफ0 जो भी होगा उसको भी मापा जाएगा। पहाड़ी प्रदेशों में डेयरी इंडस्ट्री बहुत प्रोसपेरोस हुई है। आने वाले 5 से 10 वर्षों में हमारी भी डेयरी इंडस्ट्री बहुत प्रोसपेरोस होगी। मैंने जैसे ही दूध का रेट 61 रुपये किया तो मुझे कई महिलाओं की आंखों में खुशी के आंसू

दिखे क्योंकि वे सोच रही थीं कि अब हमारा गुजारा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले कल ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से चर्चा की और हमने बी0पी0एल0 में अति गरीब परिवारों के लिए 6 चरण बनाएं जिन्होंने 50 दिन मनरेगा में काम किया था। उसमें 93,000 परिवार अभी तक सम्मिलित हुए हैं। सातवें चरण में मंत्री जी ने राय दी कि अब इसको घटाया जाए और जिसने 20 दिन मनरेगा में काम किया है उन सबको शामिल किया जाए। हम अभी जो 'सुखी परिवार योजना' लाए हैं तो इसको भी हम एक मेन मकसद के साथ लेकर आए हैं। उनको क्या मिलने वाला है और इनके जीवन में हमारी सरकार बहुत अधिक सुधार आने वाले एक वर्ष में करने जा रही है। अब देखना, हम इनको याद करवाएंगे कि हमने किस क्षेत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति की पहचान की है। विपक्ष के माननीय सदस्यों को कभी-कभी तकलीफ़ हो जाती है। मुझे नहीं पता कि इनका दोस्त नहीं है लेकिन मण्डी का ही है पर मण्डी के लिए सोचा जाना चाहिए था और पूर्व मुख्य मंत्री जी एम0आर0आई0 की मशीन मण्डी के अंदर ही लगा देते। ...(व्यवधान) (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

जारी आर0के0एस0

25.03.2026/1900/RKS/As-1

मुख्य मंत्री जारी.....

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि गरीब को उसका अधिकार इस प्रदेश की सम्पदा से मिले। अनाथ बच्चों को उनका अधिकार इस प्रदेश की संपदा से मिले। विधवा बच्चों की पढ़ाई का खर्च इस प्रदेश की संपदा से मिले। मजदूर को उसका अधिकार इस प्रदेश की संपदा से मिले। व्यवस्था परिवर्तन से किसान का भी इस प्रदेश की संपदा में अधिकार है। आम लोगों का भी इस प्रदेश की संपदा पर पूरा अधिकार है। इस सरकार में

यह पहली बार देखने को मिला है कि आम लोगों तक सरकार अपनी सोच के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। आपने इस प्रदेश में यह पहली बार देखा होगा। हम लोग सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कल आपका जन्मदिन है। मैं इससे पहले सदन को स्थगित करूं, आपको कल जन्मदिन के अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जैसा मुझे श्री अनिरूद्ध सिंह जी से संदेश प्राप्त हुआ है कि परसों आप डिनर भी दे रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से 27 मार्च, 2026 को शाम 8:00 बजे डिनर होस्ट किया जा रहा है।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 25 मार्च, 2026 **यशपाल शर्मा**

शिमला-171004. **सचिव।**